The House re-assembled at thirty-four minutes past twelve of the clock,

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.]

SHORT DURATION DISCUSSION

Liberhan Commission Report and trial of Babri Masjid case

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now we shall take up the Short Duration Discussion. Shri Amar Singh.

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, Special Mention.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Later. ...*(Interruptions)*... They will be laid.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, will it be taken up after lunch? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will do that. We will take it up. There is time-constraint. Please. We will call you.

श्री अमर सिंह (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का आपने जो अवसर दिया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, कल से मेरा हृदय बड़े संशय में डूबा हुआ है। जिस तरह के बहस का स्तर हमने लोक सभा में देखा— मैं किसी माननीय सदस्य या दल का नाम लिए बगैर कहना चाहता हूं— उससे मुझे भारी मानसिक वेदना पहुँची। मैं हतप्रभ था कि आज इस बहस में मेरे ऐसे कनिष्ठ व्यक्ति को, एक छोटे आदमी को, कई बड़े-बड़े पुरोधाओं के बारे में टिप्पणी करनी पड़ेगी। मुझे डॉ0 कर्ण सिंह जी बहुत याद आए। शैशवावस्था से कर्ण सिंह जी ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर गीता का संदेश सुनाने का काम किया है। वह अभी अनुपस्थित हैं। गीता का संदेश यह है कि युद्ध के मैदान में अगर सामने कोई वरिष्ठ भी हो तब भी कनिष्ठ को उस पर आक्रमण करने से चूकना नहीं चाहिए। इसलिए मैं अपना वाक्य-वार आरम्भ करने से पहले सभी वरिष्ठ लोगों, जिनका मैं नाम लूँगा, उनसे अग्रिम क्षमा-याचना चाहता हूँ।

मैं बाबरी मस्जिद मामले में लिब्रहान कमीशन के रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। इसकी सिटिंग्स 399 बार हुईं, मात्र 48 बार इसका extension हुआ और इसको आने में कोई ज्यादा समय नहीं लगा। इसमें सिर्फ 17 साल लगे, सिर्फ 17 साल। मैंने इसी सदन में एक बार कहा था कि इस बीच उस समय जो बच्चा था, वह जवान हो गया, जो जवान था वह बूढ़ा हो गया और जो बूढ़ा था वह मर गया। इसको आने में सिर्फ 17 साल लगे। ...**(व्यवधान)**... दो वर्षों तक श्री पी0वी0 नरसिंह राव का शासनकाल रहा, 5 वर्षों तक NDA का शासनकाल रहा, 5 वर्षों तक UPA का शासनकाल रहा। सदन में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद UPA के वरिष्ठ नेताओं ने सदन के पटल पर कहा था कि घबराओ मत, चिन्ता मत करो, मस्जिद वहीं बनाएँगे। लेकिन, यह पाँच साल रहे फिर भी मस्जिद नहीं बनी। मान्यवर, यह लोग भी रहे। 'सौगंध राम की खाते हैं, मन्दिर वहीं बनाएंगे।...' ...**(व्यवधान)**... लेकिन, आपने मन्दिर नहीं बनाया ...**(व्यवधान)**... आपने मस्जिद नहीं बनायी। ...**(व्यवधान)**... मस्जिद का वादा किया, लेकिन जब आपका शासन आया तब मस्जिद नहीं बनायी। मन्दिर का वादा किया, लेकिन जब यह शासन में आए तो मन्दिर को भूल गए। वहाँ आप मन्दिर कह रहे हैं? 1528 से अयोध्या में उस स्थान पर गंगे शहीदन नामक स्थान पर मस्जिद का अस्तित्व है। 1528 से 1885 तक वहाँ मस्जिद में अजान भी होती रही और वहाँ उस मस्जिद में पूरा-का-पूरा कार्यक्रम चलता रहा। पहली बार 1885 में महंत रघुवर दास ने मस्जिद के बाहर एक चबूतरे पर एक शेड के लिए, मस्जिद के लिए कोई विवाद नहीं था, एक मुकदमा किया। वह मुकदमा किया हुआ petition भी cancel कर दिया गया। इसमें मस्जिद का विवाद

तो था ही नहीं। कांग्रेस के हमारे साथी मुझे क्षमा करेंगे। मैं कोई व्यक्तिगत आक्रमण करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कुछ ऐतिहासिक सत्य हैं, जिन्हें बताना मेरी मजबूरी है।

सर, 1949 में वहाँ पर मूर्तियाँ रखवाई गईं थीं। वहाँ मूर्तियाँ रखवा कर के ताला लगाया गया और मूर्तियों की आराधना तथा पूजा-अर्चना की अनुमति दी गई। मैं नाम ले लेता हूँ। 1949 में यहाँ शासन किसका था? 1949 में कांग्रेस का शासन था। दूसरा प्रमुख वर्ष 1986 है। 1949 में वहाँ पर मूर्तियाँ रखवाई गईं और ताला लगवाया गया, लेकिन 1986 में वह ताला खोल दिया गया। वह किसका शासनकाल था? कांग्रेस का। जब वह ताला खोला गया, तब वहाँ का मुख्य मंत्री कौन था? श्री वीर बहादुर सिंह जी। कौन था असली गृह मंत्री? श्री अरुण नेहरु।

जिनकी आत्मा में भाजपा बसी हुई थी और जो बाद में आपके दल से चुनाव भी लड़े। मैं कहना चाहता हूँ कि जब...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्य: अमर सिंह जी की किनसे मित्रता है ...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंह: मेरी मित्रता तो अरुण जी से भी है, तो क्या उनकी नीतियों से भी मेरी मित्रता है? मैं यह कह रहा हूँ कि 1986 में ताला खुला। कांग्रेस के साथी यह तर्क दे सकते हैं और मैं यह बात मानता हूँ कि अदालत के कहने से ताला खुला, लेकिन किस स्तर की अदालत? जिला स्तर की अदालत। तो क्या उस समय कांग्रेस की सरकार इतने बड़े विवाद की परिकल्पना करके अदालत के उस आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट नहीं जा सकती थी और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती थी? ऐसा लगता है कि मानो किसी बहाने की तलाश थी कि बहाना मिला नहीं कि ताला खुले। जब माननीय वीर बहादुर सिंह जी मुख्य मंत्री थे और श्री अरुण नेहरू गृह मंत्री थे तब ताला खुला और ताला खुलने के बाद पूजाकीर्तन करताल से चालू हुआ। उसके बाद विवाद और उग्र गति से बढ़ना शुरू हुआ। 1949 के बाद 1986। क्या 1949 का यह सच असत्य है कि मूर्तियाँ 1949 में कांग्रेस के शासनकाल में रखवाई गईं और ताला लगाया गया? क्या 1986 में ताला खुला और ताला खुलने के बाद छोटे कोर्ट के आदेश से उसकी कोई अपील नहीं की गई? क्या यह असत्य है? फिर आइये, 1989। यानी 1949 में पहली गलती, 1986 में दूसरी गलती और 1989 में तीसरी गलती यह कि चुनाव से 10 दिन पहले शिलान्यास होता है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन इसके लिए चुनाव से पहले का समय ही क्यों चयनित किया गया?

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखण्ड): कौन सा चुनाव?

श्री अमर सिंह: वर्ष 1989 का लोक सभा चुनाव। लोक सभा चुनाव के मात्र 10 दिन पहले कांग्रेस के शासन काल में शिलान्यास हुआ, शिला-पूजन हुआ और राम राज्य की परिकल्पना की बात की गई। यानी इसके तीन लैंडमार्क, वर्ष 1949, जब मूर्तियाँ रखी गईं, ताला लगा और कांग्रेस के शासन काल में पूजा की स्वीकृति मिली। 1986 में छोटी अदालत के कहने से ताला खुला और 1989 में चुनाव के 10 दिन पहले शिलान्यास आरंभ हुआ। तो वर्ष 1949, 1986 और 1989, इनको आप भुला नहीं सकते। मैं स्पष्ट रूप से कहूँ कि मैं कांग्रेस की धर्म निरपेक्षता के ऊपर कोई प्रश्न चिह्न लगाने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। मैं सिर्फ इतिहास का सत्य और उन वर्षों को दोहरा रहा हूँ जो इतिहास के पन्ने में दर्ज हैं।

अब आप यह देखिए कि 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले परम आदरणीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का अनशन और उस अनशन को तुड़वाने तत्कालीन गृह मंत्री चव्हाण साहब का जाना। इसके बाद बाबरी मस्जिद 6 दिसम्बर को शहीद हुई और 4 दिसम्बर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माननीय अर्जुन सिंह जी का अयोध्या जाने का ऐलान और बजाए अयोध्या जाने के लखनऊ जाकर कल्याण सिंह जी से मिल कर उनके आश्वासन से आश्वस्त होकर वापस आ जाना। इसके बाद तत्कालीन गृह सचिव, जिनके बारे में जस्टिस लिब्रहान ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, मार्क तुली ने अपनी रपट में लिखा है कि गृह सचिव और पुलिस

ने अकर्मण्य और निष्क्रिय होकर पूरे के पूरे जत्थे को खुली छूट दे रखी थी। वह गृह सचिव थे, श्री प्रभात कुमार, कल्याण के लाडले प्रभात कुमार और नरसिंह राव जी के दुलारे प्रभात कुमार। वही गृह सचिव, जिन्होंने मस्जिद की शहादत अपने नेतृत्व में पुलिस को अकर्मण्य और निष्क्रिय रख कर करवाई। वे कांग्रेस के शासन काल में पांच साल तक कैबिनेट सचिव थे और जब माननीय अटल जी आए तो उनकी पुरानी सेवा, जो उन्होंने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की शहादत करवाते हुए की थी। उसके स्मृतिचिन्ह के रूप में झारखंड का राज्यपाल बना दिया। चिदम्बरम साहब हमारे बहुत योग्य और विद्वान मंत्री हैं, कल हमने उनका सारगर्भित वक्तव्य देखा है और सारगर्भित वक्तव्य सुना भी है, लेकिन जिस तरह से वे पल्ला झाड़ गए हैं, वह नहीं चलेगा।

मैं श्री सलमान खुर्शीद जी की तारीफ करुंगा, उस समय वे भी मंत्री थे, कम से कम उन्होंने हिम्मत दिखाई और उन्होंनें कुछ तल्ख टिप्पणी खुलेआम की। लेकिन, जिस तरह से एक वृत्ति दिख रही है, यानी नरसिंह राव जी कांग्रेस के थे ही नहीं, यह नहीं चलेगा। वे कांग्रेस के सिर्फ प्रधान मंत्री ही नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे और उनके मंत्रि-मंडल में जो लोग थे, अल्पसंख्यक समुदाय के भी, चाहे भाई गुलाम नबी आजाद हों, भाई सलमान खुर्शीद हों, आदरणीय चिदम्बरम जी हों, नरसिंह राव जी की legacy को आप कैसे नकार सकते हैं, उनकी सबसे बड़ी legacy का नाम डा0 मनमोहन सिंह है। नरसिंह राव जी ने इनको चिन्हित किया, खोजा और गुमनामी के अंधेरे से लाकर राजनीति के पटल पर रखा और आज वे प्रधान मंत्री हैं। प्रणब दा भी उस समय थे। 90% मंत्री, जो इस कैबिनिट में हैं, प्रवीण और वरिष्ठ, वे नरसिंह राव की भी कैबिनिट के मंत्री थे और कैबिनिट की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। इसलिए आज आप यह कहें कि वह तो नरसिंह राव जी का राज था, आज किसी और का राज है, तब सूरतेहाल कुछ और थी, अब कुछ और है, यह नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। एक त्याग-पत्र मुझे याद है श्री माधव राव सिंधिया का, लेकिन वह भी बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए नहीं, हवाई जहाज के लिए था और on record, उस समय के बहुत शक्तिमान व्यक्ति, श्री माखन लाल फोतेदार जी ने नरसिंह राव जी की स्वीकृतियों के बारे में विस्तार से कहा है कि यह जो रणनीति है कि segregate Narasimha Rao from Congress, यह नहीं चलेगी। नरसिंह राव जी कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रधान मंत्री रहे और अगर आप उनका segregation करते हैं तो फिर आप मनमोहन सिंह जी को भी नकार दीजिए। फिर आप, जो उदारीकरण हुआ, जिसका कि आप पूरा श्रेय लेते हैं, globalisation, उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण, जिसने पूरे देश के आर्थिक मानचित्र को विश्व के धरातल और पटल पर रखा है, उसका आप श्रेय लेते हैं, तो माननीय चिदम्बरम जी, आप उसका श्रेय लेना भी बंद कर दीजिए, फिर पूरी की पूरी legacy को ही नकार दीजिए। पांच साल का वह जो शासनकाल है, उसके पन्नों को ही फाड़ दीजिए, इतिहास के उन क्षणों पर कालिख लगा दीजिए, उन्हें मल दीजिए, लेकिन इतिहास मिटता नहीं, इतिहास छिपता नहीं। इतिहास और भूगोल, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनके साथ आपको जीना पड़ता है। इतिहास भी यथार्थ है, भूगोल भी यथार्थ है। हम इस भूगोल से कैसे भाग सकते हैं कि हमारे पड़ोस में विभाजन के बाद पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल और लंका हैं। यह हमारा भूगोल है और भूगोल के इस यथार्थ के साथ हमें जीवित रहना पड़ेगा। उसी तरह से आदरणीय नरसिंह राव जी कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधान मंत्री दोनों थे और कैबिनिट मंत्री, चाहे प्रणब दा हों, चाहे चिदम्बरम साहब हों और पिछली यू0पी0ए0 की सरकार तक श्री अर्जुन सिंह जी हों, ये सभी पुराने लोग, चाहे शरद पवार जी हों, सभी उसमें थे। तो यह तो एक अच्छी नीति है कि *मीठा-मीठा घूंट और कड़वा-कड़वा थू।* जो मीठा हो, जो श्रेय लेने लायक हो, उसका घूंट लो — आर्थिक उदारीकरण हो, लाओ, लाओ, जो अच्छा हो, लाओ, लाओ, लेकिन जो बुरा हो, नहीं, नहीं, थूक दो, यह नहीं चलेगा।

एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के रूप में अच्छा तो यह होता कि जिस तरह से सलमान खुर्शीद ने कहा, उस तरह से सबने कहा होता। हमसे कहा जाता है कल्याण सिंह जी के लिए, चलिए मैं मानता हूं हो गई

गलती, क्या कहेंगे हम, हो गई गलती, लेकिन उस गलती को हमने हिम्मत के साथ सुधारा है। लेकिन, उस गलती में आपकी भी भूमिका रही है और आपकी क्या भूमिका रही है, आपको बताते हैं। आपकी भूमिका यह रही है कि मायावती की सरकार को हटाने के लिए, जो सरकार बनी थी, उस सरकार में पूरा का पूरा समर्थन कांग्रेस का था। अगर आप समर्थन नहीं देते, आपकी बड़ी कृपा है, आप समर्थन नहीं देते तो सरकार नहीं बनती।

राजभवन में आज भी वह चिट्ठी पड़ी है, जब आपकी कृपा से, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के आशीर्वाद से मुलायम सिंह की वह सरकार बनी, तो उस सरकार में कल्याण सिंह का दल शामिल था। यहां कुसुम राय जी बैठी हैं, कुसुम राय जी हमारी मंत्री थीं, इनसे पूछ लीजिए। ये कल्याण सिंह जी के दल की सदस्या थीं और हमारी मंत्री थीं तथा इनके मंत्री पद को कांग्रेस के समर्थन की चिट्ठी थी। आज़म खान साहब भी इनके मंत्री थे। कल हमारे साथी श्री * बढ़-चढ़कर बोले थे। उनको मेरा उत्तर है कि आपके बेटे राकेश वर्मा भी मंत्री थे ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: वे उस हाउस के मेंबर हैं, उनका नाम मत लीजिए ...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंह: अच्छा, ठीक है, मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री उपसभापति: एक्सपंज हो गया है ...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंह: मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: नहीं, कल की जो बात थी, उस संदर्भ में ...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंह: आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu) : There is not one word about Liberhan.

श्री अमर सिंह: आप कह रही हैं कि मैंने लिब्रहान के बारे में एक शब्द तक नहीं कहा है, ये सब लिब्रहान है, क्योंकि यह लिब्रहान का मूल है, अगर प्रस्तावना नहीं होगी, अगर भूमिका नहीं होगी, तो फिर आगे बात कैसे होगी? लिब्रहान के बारे में मैं क्या कहूं? लिब्रहान में RSS की भूमिका के बारे में जितना कहना चाहिए, उतना नहीं कहा गया है। जयन्ती जी, मैं लिब्रहान के परिप्रेक्ष्य में ही कह रहा हूं कि आप लोगों ने यह कहा कि तत्कालीन प्रधान मंत्री जी को यह पता ही नहीं था। कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य ने, जो एक दिन के मुख्य मंत्री थे, वे कल्याण सिंह जी के समर्थन से बने मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, एक सदस्य के लड़के, कल्याण सिंह के दल के द्वारा सम्मिलित मंत्रिमंडल में सदस्य थे, वे भी बोल रहे हैं। सूप तो सूप बोले, हमारे उत्तर प्रदेश में कहावत है कि — "चलनिओ बोले जामें बहत्तर छेद।" उन्होंने कहा कि पता नहीं था, अगर पता नहीं था, तो मैं बता रहा हूं। यह श्री नरसिंहराव जी की पुस्तक है, वे भी इस सदन के सदस्य नहीं हैं, लेकिन माफ कीजिए कि बोलना पड़ रहा है। यह उनकी पुस्तक है, मैं इसको प्रणाम कर रहा हूं, उन्होंने यह दस्तावेज़ छोड़ा है। खुद रेड्डी साहब, जो उस समय गवर्नर थे, उन्होंने यह चिट्ठी लिखी कि— "The possibility of the damage to the disputed structure itself may not be ruled out. Therefore, in my opinion, we should be very cautious on this issue." यह चिट्ठी रेड्डी साहब ने, जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे, मस्जिद की शहादत से 5 दिन पहले कांग्रेस के अध्यक्ष, देश के तत्कालीन प्रधान मंत्री, माननीय पी.वी. नरसिंहराव जी को लिखी। यह माननीय नरसिंहराव जी की लिखी किताब है, पृष्ठ नंबर 150, "अयोध्या"। अगर हम अयोध्या के बारे में नहीं बोलेंगे, तो लिब्रहान के बारे में क्या बोलेंगे? अब मैं लिब्रहान के ऊपर आ रहा हूं, लेकिन इसमें से श्री पी.वी. नरसिंहराव साहब गायब हैं और श्री गुलजारी लाल नंदा अंदर हैं, जब कि गुलजारी लाल नंदा सक्रिय राजनीति से विदा हो गए थे और बाबरी मस्जिद की शहादत से 3 साल

*Expunged as ordered by the Chair.

पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। अब आप कहेंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी का तर्क दे रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी का तर्क बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि उसमें देवरहा बाबा का जिक्र है और मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं भी देवरहा बाबा के यहां गया हूं, कांग्रेस के भी तमाम लोग उनके यहां गए हैं। देवरहा बाबा एक निर्विकार संत थे और उनका सांप्रदायिक राजनीति से कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन देवरहा बाबा का नाम इसमें है। मुझे लगता है कि गलती से श्री पी.वी. नरसिंहराव जी की जगह, पूर्व प्रधान मंत्री, श्री गुलजारी लाल नंदा जी का नाम आ गया है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं एक पत्र का जिक्र करना चाहूंगा, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन वे बहुत ही सभ्य महिला हैं।

दिल्ली की मुख्य मंत्री हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ ...**(व्यवधान)**... वह बहुत लोकप्रिय हैं और बार-बार चुनाव जीतती हैं। मेरी बड़ी बहन है। वह चिट्ठी लिख रही हैं, प्रिय नरसिम्हा राव जी, आप लगातार भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिन्दू परिषद् और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ गुप्त वार्ताएं चलाते हैं और स्वयंभू मुस्लिम नेताओं से भी आप बातचीत चलाते हैं। साधु-संतों से तो आप अंतरंग वार्ताओं में तल्लीन रहे। यह तब आपने किया, जब इन घटनाओं ने हमारी संपूर्ण राजनीतिक जीवन में अस्थिरता को जन्म दिया और संविधान की मान और धारणाएं पददलित होती रहीं। 6 दिसंबर, 1992 के बाद ...**(व्यवधान)**...

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam) : Sir, I have a point of order. He is reading a letter purported to be written by somebody to somebody. I want to know whether he can read such a letter and whether the letter is authenticated. I want a ruling on this issue, Sir.

SHRI AMAR SINGH: I am not yielding. ...*(Interruptions)*... I am not yielding.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: I am on a point of order. I want a ruling from you, Sir.

SHRI AMAR SINGH: I am not yielding.

SHRI RAJEEV SHUKLA (Maharashtra): Amar Singhji, can you authenticate it? ...*(Interruptions)*...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, I request a ruling on that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: See, you are reading some letter written by somebody to somebody.

SHRI AMAR SINGH: I authenticate it, Sir. यह authentic letter है ...**(व्यवधान)**...

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: How can he authenticate it? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is taking the responsibility. ...*(Interruptions)*... Let him authenticate it. He is saying that he will authenticate it. If it is not an authenticated document, you can take the privilege. ...*(Interruptions)*... Amar Singhji, can you authenticate that letter and lay it on the Table of the House? ...*(Interruptions)*... Can you authenticate the letter which you are reading?

SHRI AMAR SINGH: Yes, Sir.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, after authentication, he is to lay it on the Table of the House. After authentication only, he can read it. ...*(Interruptions)*... He has to lay it on the Table of the House. ...*(Interruptions)*... That is the rule. ...*(Interruptions)*...

1.00 P.M.

श्री अमर सिंह: संविधान की मान और अवधारणाओं ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप authenticate करके ले कर दीजिए।

श्री अमर सिंह: ठीक है, सर, मैं ले कर दूंगा ...**(व्यवधान)**... 6 दिसंबर, 1992 के बाद हमारी नैतिक धर्मनिरपेक्षतावादी प्रतिबद्धताओं पर सवालिया निशान बना हुआ है। 6 दिसंबर को सरकार क्या कर रही थी? राष्ट्रपति शासन की अवधि में क्या कर रही थी? 6 दिसंबर को अयोध्या में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए थे? इन घटनाओं की रोकथाम क्यों नहीं हो रही थी? ...**(व्यवधान)**...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, is it going on record?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is going to authenticate it. ...*(Interruptions)*... I think, he is to lay it on the Table of the House; otherwise, I will expunge it.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: We have a right to get a copy of that. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He will authenticate it and lay it on the Table of the House; otherwise, if he is not authenticating it, I will expunge it from the record.

श्री अमर सिंह: मुंबई में जो कुछ घटा, उसने सारे संसार में हमारे नाम को कलंकित किया। नरसिम्हा राव जी आप मुंबई गए, लेकिन आपने शिव सेना के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। अतएव आम जनता हमारी धर्म निरपेक्ष प्रतिबद्धता पर सवालिया निशान उठा रही है। मस्तिष्क में तमाम सवाल उठ रहे हैं। हम 6 दिसंबर के बाद की परिस्थिति पर गंभीर चर्चा के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महाधिवेशन की प्रार्थना करते हैं। मैं पूरा पत्र नहीं पढ़ रहा हूँ। हमारे साथियों को बड़ी खलबली मच रही है। हमारी अपेक्षा है कि कांग्रेस कार्य समिति पत्र में उल्लेखित सवालों पर सार्थक निर्णय लेगी और देश के कोने-कोने में जनता का आह्वान करेगी कि जहां कहीं भी देशवासी हैं, वहीं इस अवसर पर विश्वास के साथ धर्म निरपेक्षता के दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। इसमें एक पूर्व विदेश मंत्री, जो इस सदन के सदस्य थे, किसी मामले में गए, उसके भी हस्ताक्षर हैं। हमारी बड़ी बहन का हस्ताक्षर है, उसके साथ एआईसीसी के पूर्व महासचिव के हस्ताक्षर हैं और कांग्रेस के चार वरिष्ठ नेताओं के हस्ताक्षर हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री विनय कटियार: आप डाटा तो दे ही रहे हैं, उनके नाम भी बता दीजिए ..**(व्यवधान)**..

श्री अमर सिंह: मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जो लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में इन मामलों पर बड़ी चुप्पी है। आदरणीय नरसिम्हा राव जी आज जीवित नहीं हैं, अतः उनके बारे में मेरा ज्यादा बोलना उचित नहीं होगा। पर, मामले की गंभीरता को देखते हुए मस्जिद के शहादत के लिए ये तो जिम्मेदार हैं ही, इन्होंने तो कुछ छोड़ा नहीं। मैं आदरणीय अटल जी की बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन 6 दिसंबर को मस्जिद शहीद हुई और 5 दिसंबर को आदरणीय अटल जी ने कहा है कि हे कार सेवको, समतलीकरण होना चाहिए। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है। दल के नेता के रूप में कार सेवकों को अयोध्या जाने से पहले समतलीकरण की बात करके निश्चित रूप से अटल जी ने यह कह दिया, ईश्वर उनको लंबी आयु दे, मैं बहुत श्रद्धा से और विनत होकर कहता हूँ, बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, कि भारतीय जनता पार्टी की घोषित कार्यक्रम धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह राजनीतिक कार्यक्रम का एक हिस्सा बन गया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे। कार सेवकों को संबोधित करते हुए उन्होंने समतलीकरण की बात की थी और हे बजरंगी विनय कटियार जी ! आप तो वहां उत्पात मचा रहे थे। आप तो वहां उपस्थित थे और उत्पात मचा रहे थे। वहां पर उमा जी, मुरली मनोहर जोशी जी, कलराज जी, माननीय आडवाणी जी, ये सब लोग थे। यह कैसा दुर्भाग्य

है लोकशाही का? उस समय स्थिति क्या थी? एक प्रधान मंत्री थे, जो सुप्त थे, लुप्त थे। पूरी क्षमता रहने के बावजूद देश के संविधान की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं थे। एक नेता, विरोधी दल थे, आदरणीय आडवाणी जी, जिन्होंने रथ यात्रा चलाकर, नफरत का ज़हर बोकर, देश को विभाजित करके, परम आदरणीय आडवाणी जी, जो पैदा हुए पाकिस्तान में, लड़ाने चले हैं हिंदुस्तान में, हिंदू को श्मशान में और मुसलमान को कब्रिस्तान में। ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार): उस वक्त वह पाकिस्तान नहीं था। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: वह पाकिस्तान नहीं था। उस वक्त तो ...**(व्यवधान)**...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, I have an objection....*(Interruptions)*... I want to make a mention. ...*(Interruptions)*... I am from Sialkot. Sialkot is a part of Pakistan now. We are all displaced persons. Our forefathers were displaced from west Punjab and we suffered to give freedom to this nation and people suffered in the eastern part of Bangladesh—East Pakistan and West Pakistan; there you say that we are Pakistanis? We fought for the Independence of this country. ...*(Interruptions)*...

श्री रवि शंकर प्रसाद: डा. मनमोहन सिंह कहां पैदा हुए थे? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: अमर सिंह जी....(व्यवधान)... नहीं, नहीं ...**(व्यवधान)**... अमर सिंह जी ...**(व्यवधान)**...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, this is very unfortunate. They can say that we were born on the other side which was sacrificed by Gandhiji for a different nation.

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal): Sir, they are diverting the issue.

SHRI S.S. AHLUWALIA: What is this?

श्री अमर सिंह: अच्छा आपकी भावनाओं ...**(व्यवधान)**... मैं खेद प्रकट...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: अमर सिंह जी बोलिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री राजीव शुक्ल: माफी मांग लीजिए।

श्री अमर सिंह: माफी क्यों मांग लूं? मैं आपके चक्कर में पड़ने वाला हूं क्या? आप इतना कच्चा समझते हैं माफी मांगने को? लेकिन हां, यह ज़रूर है कि भावनाओं को आहत करने का मेरा मन नहीं था, इतना मैं ज़रूर कहना चाहूंगा। मैं दुखी हूं कि आपकी भावनाएं आहत हुई हैं। ..**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: तो उसमें सुधार कीजिए। वह पाकिस्तान नहीं है। वे जहां पैदा हुए, उस समय वह भारत का हिस्सा था। आज़ादी की लड़ाई वहां से लड़ी गई। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंह: अच्छा ठीक है, ठीक है। ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कांग्रेस ने जो लाहौर के resolutions पास किए, लाहौर में जो फैसले लिए गए, क्या वे पाकिस्तान के फैसले थे? आप क्या बात करते हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: तिरंगा भी नेहरू जी ने पहली बार वहीं फहराया था, वह हिंदुस्तान का पार्ट था। ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: हां, तिरंगा झंडा कहां फहराया गया था?...**(व्यवधान)**... लाहौर के किले पर.... लाहौर के किले पर फहराया गया था।...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंह: ठीक है अहलुवालिया जी, आपने दुरुस्त कर दिया है, आप बैठिए। आपने दुरुस्त कर दिया है। ...**(व्यवधान)**... तो मैं कहना चाहता हूं कि ये सभी चेहरे ...**(व्यवधान)**...

डा. ऐजाज़ अली: *

श्री उपसभापति: आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**... बिल्कुल.. बिल्कुल, बैठिए। ...**(व्यवधान)**... कोई नहीं कह रहा है, आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**.... आप बैठिए प्लीज़....प्लीज़... कोई नहीं कह रहा है। ...**(व्यवधान)**... यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ...**(व्यवधान)**...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: It is grossly unfair and should not go on record.

श्री उपसभापति : यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ...**(व्यवधान)**... ऐजाज़ अली जी, आपको identify नहीं किया गया है, it will not go on record.

श्री अमर सिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि ...**(व्यवधान)**...

श्री सीताराम येचुरी (पश्चिमी बंगाल): बाकी सब जा रहा है, तो यह क्यों नहीं जाएगा?

श्री उपसभापति : नहीं, नहीं, उनका कहना है कि उनको "पाकिस्तानी" कहा जा रहा है, लेकिन उनको identify नहीं किया गया था, वे बीच में उठकर बोले, इसलिए it will not go on record. Otherwise, everything may go on record.

श्री अमर सिंह: 6 दिसम्बर की दुखद घटना और उस शहादत के दिन एक ऐसा प्रधान मंत्री जो सुप्त और लुप्त है, एक ऐसा विरोधी दल का नेता — मैं वह शब्द नहीं दोहराऊंगा, जिस पर आप आहत हो रहे हैं — जो रथ यात्रा चलाता है, राजनैतिक कार्यक्रम बनाता है कि राम मंदिर बनाएंगे और जब मस्जिद की शहादत हो जाती है तो सुश्री उमा भारती और * कटियार मुरली मनोहर जोशी के कंधे पर चढ़कर हो-हल्ला मचाते हैं, चिंग-पो करते हैं, कलराज जी वगैरह भी — ये सभी चरित्र बैठे हैं, मूर्तियां बैठी हैं, आपको प्रणाम और नमन ।

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश): वहां के साक्ष्य ...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंह: बैठते हैं, सब लोग बैठे हुए हैं और उसके बाद भी ये लज्जित नहीं हैं और कहते हैं कि हम गर्वित हैं कि हमने शहादत कर दी, हमने देश के हिन्दू-मुसलमानों के दिलों को तोड़ दिया — हम इसके लिए गर्वित हैं। इन्होंने उस बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं किया, विदेश में उसकी प्रतिक्रिया में कई मंदिरों को तुड़वाया है।

श्री कलराज मिश्र : वह विवादित ढांचा था।...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंह : आज मुम्बई में जो आतंकवाद हुआ है, आज धूलिया में, मालेगांव में, असम में जो दूरियां बढ़ी हैं, उसके मूल में यही महान मूर्तियां बैठी हैं, उसकी जड़ में यही हैं। उस नफरत के बीज को बोने वाले यही हैं। इन्होंने बोया है। ...**(व्यवधान)**... इन्होंने समाज को दो दायरों में बांटा है। ...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्य : उसकी जड़ में ...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंह : मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, मुलायम सिंह यादव, हनुमान के भक्त, ईश्वर के पुजारी...**(व्यवधान)**...

श्री विनय कटियार: उपसभापति महोदय, मैं, अभी नहीं, लेकिन बाद में चाहूंगा कि जितने लोग मेरा नाम ले रहे हैं, इस सदन का सदस्य होने के नाते मुझे भी अपनी बात स्पष्ट करने का मौका दिया जाए। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your name is there in the Report. They are entitled to take.

श्री विनय कटियार: मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूं।

*Not recorded.

श्री उपसभापति: आपकी पार्टी से पूछिए, वे टाइम दे दें। ...**(व्यवधान)**...

श्री विनय कटियार: पार्टी की बात नहीं है। अगर कोई सीधा मेरा नाम ले...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आपका नाम रिपोर्ट में है तो लेना पड़ेगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं?

श्री विनय कटियार: वे मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आपका नाम रिपोर्ट में है। ...**(व्यवधान)**...

श्री विनय कटियार: मैं टोक नहीं रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री तारिक अनवर (महाराष्ट्र): आपका नाम रिपोर्ट में है। आपने जो किया है, उसके कारण आपका नाम रिपोर्ट में आया है।...**(व्यवधान)**...

श्री सीताराम येचुरी : आपका नाम रिपोर्ट में है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Time is limited. Only eight hours are allotted. Different political parties are going to make their submissions on this subject, and it is an important subject. But there are names mentioned in the Report. From every corner, people will speak on this. So, the Members, whose names will be taken, should get an opportunity beyond these eight hours...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: यह ठीक नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

प्रो0 राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): रिपोर्ट में इनका नाम है। ...**(व्यवधान)**... ये सारे नाम कमीशन की रिपोर्ट में हैं इसलिए उनका नाम लिया जाना जरूरी है। ...**(व्यवधान)**...

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा): उनका नाम बार-बार लिया जा रहा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: अहलुवालिया जी, नयी-नयी परम्पराएं मत बनाइए प्लीज़। ...**(व्यवधान)**...

SHRI S. S. AHLUWALIA: Why don't you make a rule? It is a right of the Chair. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It can't be. ...*(Interruptions)*...

SHRI S. S. AHLUWALIA: Sir, there is a rule for this. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will check the rule and let you know. ...*(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, the point is, a Commission was appointed under the Commission of Inquiry Act. They have taken his name. He does not have the right to reply. His party can give him time if he wants to speak. ...*(Interruptions)*...

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): How will Advaniji reply? How will Joshiji reply? Their names are mentioned in the Report.

श्री अमर सिंह: सर, मेरा समय जा रहा है। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: On this, I will not allow you to take extra time. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): ये लोग भी interrupt कर रहे हैं और वे लोग भी interrupt कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री कलराज मिश्र: हम लोगों का नाम लेकर आरोपित किया जा रहा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री विनय कटियार: उपसभापति जी ...**(व्यवधान)**... मुझे ज्यादा समय नहीं चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आपकी पार्टी के पास टाइम है, उनसे लीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री विनय कटियार: ये बोलेंगे तो ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: बिल्कुल नहीं। अमर सिंह जी, आप बोलिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (उत्तराखण्ड): सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी स्पीकर बोल रहे हैं, उनके अलावा अन्य लोग अगर बीच में हस्तक्षेप करे, हम करें या वे करें, कोई भी करे, उस पर आप रोक लगाइए वरना उस स्पीकर के समय में से उतना समय ज़ाया होता है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: अमर सिंह जी, बोलिए।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अगर कोई भी हस्तक्षेप करे तो उसे रोकिए और वह समय उस स्पीकर के समय में नहीं माना जाएगा।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप बैठिए।

श्री विनय कटियार: सर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि या तो आप यह व्यवस्था हमेशा के लिए दे दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक ...**(व्यवधान)**... आप ऐसा मत करिए। ...**(व्यवधान)**... अगर कुछ लोग मिलकर हमें फांसी पर चढ़ा देंगे तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। सर, यह तो सही नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: देखिए कटियार जी, लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट पर यह डिस्कसन हो रहा है और जिन-जिन लोगों के नाम लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट में मेंशन किए गए हैं, तो स्पीकर वे नाम लेंगे। Just because you are a Member of the House you should be give an opportunity and others should not be given an opportunity is not correct. ...**(व्यवधान)**... आपकी पार्टी के पास टाइम है, आप लीजिए। एक्स्ट्रा टाइम क्यों ले रहे हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री विनय कटियार: मेरी बात तो सुनिए।...(व्यवधान)... आप मेरी बात भी नहीं सुनेंगे।

श्री उपसभापति: मैं सुन रहा हूं, मैंने आपकी बात सुनी है।...**(व्यवधान)**... बात करते जाइए...**(व्यवधान)**... आपकी बात मैंने सुन ली, आपका विषय भी मैंने सुन लिया।

श्री विनय कटियार : आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मेरा ऐसा कहना है कि नियम या कहता है, मुझे जानकारी नहीं है।...**(व्यवधान)**... जब किसी मेंबर का नाम लिया जाता है तो सदन में यह बात रही है कि सफाई देने का मौका मिलता है...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: देखिए, मैं रूल बताता हूं...**(व्यवधान)**... अब मैं समझ गया।...**(व्यवधान)**...

SHRI SITARAM YECHURY: Let his party give him the time ...*(Interruptions)*...

SHRI AMAR SINGH : Sir, my time is being wasted. I am not yielding...*(Interruptions)*...

श्री विनय कटियार: या तो आप यह व्यवस्था कर दें। यह तो मैं इनको * करके इनकी सब बात को मैं सुनूंगा, मुस्कराऊंगा भी, क्योंकि मैं जानता हूं कि लिब्रहान कांग्रेस का उपन्यास है।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: नहीं-नहीं।...**(व्यवधान)**... Nothing will go... आप बोलिए। In an explanation you go on...**(व्यवधान)**... बिल्कुल नहीं...**(व्यवधान)**... आप बोलिए। ...**(व्यवधान)**... आप चेयर को थ्रेटन नहीं कर सकते।...**(व्यवधान)**... No, no. You cannot threaten the Chair...*(Interruptions)*... I request the hon. Members, please sit down. We are discussing a very sensitive issue. Definitely, there will be acrimony...*(Interruptions)*...

---

*Not recorded.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Heavens are not going to fall...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: देखिए, अहलुवालिया जी, आपके लिए एक रूल होता है, दूसरों के लिए एक रूल नहीं होता है। I am appealing to you. ...**(व्यवधान)**... रूल जो कहता है, If he is a Member of the House and any allegations are made against that Member, he would be given an opportunity to respond. They cannot take the names of Members of the other House. If the Member belongs to the same House and if there is any allegation, he will be given an opportunity. Here, this is not an allegation. The name has been mentioned in the Report. It is not an allegation. So, it cannot ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, this Report has not been accepted by the House ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not necessary...*(Interruptions)*... Mr. Ahluwaliaji, we are discussing the Report...*(Interruptions)*... This is laid on the Table of the House. How can the Report be accepted by the House? Whether any Report has been accepted by the House. Which Report has been accepted by the House? You tell me.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Should I believe that all the Papers laid on the Table of the House are accepted? Should I believe that?...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You are saying a new thing...*(Interruptions)*... I will not be able to reply to your question...*(Interruptions)*... The Report is the property of the House...*(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, Report is never accepted or rejected by the House. It is laid on the Table of the House. It is the property of the House that we are discussing ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have given the ruling. Please...*(Interruptions)*... Whether you accept it or not. With all humility at my command, I request you to please allow the debate to go on...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: That is not fair...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have seen it...*(Interruptions)*... You may not accept my ruling.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, this Report has not been accepted by the House unanimously.. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Who is accepting or who is not accepting? ...*(Interruptions)*... That is not the issue here. ...*(Interruptions)*...

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, रिपोर्ट की सब बातें कैसे सही हैं ? ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ravi Shankar Prasad, please, this is not a correct thing. ...*(Interruptions)*...

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, यह आपने कहा है कि इनका नाम रिपोर्ट में है। ...**(व्यवधान)**... सर, रिपोर्ट कैसे सही होगी? ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I know, you are arguing, but that is wrong. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: What is wrong, Sir? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have given the ruling. ...*(Interruptions)*... He is a Member of a political party. ...*(Interruptions)*... The political party has been given some time and within that time he can speak; I have no objection to that. ...*(Interruptions)*... There is no question of giving additional time. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Exactly, Sir.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, when his name is mentioned in the House ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: His name is mentioned in the Report. ...*(Interruptions)*... Mr. Ahluwalia, I cannot give an answer to you. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, they are all accused in the .. ...*(Interruptions)*...

श्री रवि शंकर प्रसाद: आपने कहा है कि ...**(व्यवधान)**... सर, इनका रिपोर्ट में नाम है। फिर, इनको कहां बोलने दिया जा रहा है? ...**(व्यवधान)**... सर, रिपोर्ट करेक्ट है, यह कहना ठीक नहीं है। ...**(व्यवधान)**... आप यह कैसे कह सकते हैं कि रिपोर्ट ठीक है।...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Why are you putting words into ...*(Interruptions)*... I did not say the Report is right. Did I say? ...*(Interruptions)*... The House is discussing the Liberhan Commission Report, which has been laid. ...*(Interruptions)*... The Report is laid under the provisions of the Commission of Inquiry Act and it is the property of the House. ...*(Interruptions)*... The House is discussing the Report with your support. ...*(Interruptions)*... You are a party to it. ...*(Interruptions)*...

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, रिपोर्ट करेक्ट है, यह कहना ठीक नहीं है। ...**(व्यवधान)**... आप यह कैसे कह सकते हैं कि रिपोर्ट ठीक है।...**(व्यवधान)**...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, how can you say that the Report is correct?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Who is saying that? I did not say that...*(Interruptions)*..

SHRI S.S. AHLUWALIA: You see the Report. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ahluwalia, we are discussing the Report. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: How can you say that, Sir?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What? Are you not discussing the Report? ...*(Interruptions)*... Is the Report not the property of the House?...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, how can you say that the Report is correct?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Who is saying that? ..(Interruptions).. I did not say that the Report is correct. ...*(Interruptions)*... I said that the Report is the property of the House. ...*(Interruptions)*...

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, I do not think that they want to have a discussion on it. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I did not say that the Report is right. The Report is the property of the House. ...*(Interruptions)*...

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, let us not disturb the debate. Let us have a meaningful debate. ...*(Interruptions)*...

श्री उपसभापति: अमर सिंह जी, आप बोलिए। ...**(व्यवधान)**... आपकी आवाज़ तेज है। आप बोलिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री एस. एस. अहलुवालिया: कलराज मिश्र जी का नाम लिया गया है, उनको बोलने का अधिकार है। ...**(व्यवधान)**... विनय कटियार जी का नाम है, उनको बोलने का अधिकार है। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: See, they are referring to the Rule. An allegation has been made against a Member but it is not an allegation. ...*(Interruptions)*...

श्री अमर सिंह: सर, हमें बोलने दीजिए।...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have given the ruling. ...*(Interruptions)*...

श्री अमर सिंह: सर आप मेरे बोलने के बाद अपनी रूलिंग दीजिएगा।...**(व्यवधान)**... हम रिपोर्ट डिसकस कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If I give an opportunity to a Member because his name is being mentioned, then, the House will be unfair to those who are not being given the opportunity. ...*(Interruptions)*...

श्री विनय कटियार: सर, सदन का सदस्य होने के नाते मैं आपसे न्याय मांग रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Narsimha Raoji's name has been mentioned. ...*(Interruptions)*...Various other names have also been mentioned. ...*(Interruptions)*...

श्री सीताराम येचुरी: सर, सिम्पल क्वेश्चन है I Why is BJP not giving him time? ...*(Interruptions)*...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : टाइम देंगे। ...**(व्यवधान)**...

श्री सीताराम येचुरी : आप टाइम देंगे, तो इश्यु खत्म है। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंह : सर, मुझे बोलने का समय दीजिए। मेरा बहुत समय जाया हो रहा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप बोलिए। ...**(व्यवधान)**... आपने बहुत टाइम waste किया । ...**(व्यवधान)**... आप बोलिए।...(व्यवधान)... आप बैठ जाइए। आप बोलिए।

श्री अमर सिंह: उपसभापति महोदय,

"हुई हमसे यह नादानी, तेरी महफिल में आ बैठे।
जमीं की खाक होकर, आसमां से दिल लगा बैठे।"

...**(व्यवधान)**... आप लोगों के साथ। आप दोनों तंग कर रहे हैं। आप दोनों से दिल लगाया, दोनों तंग कर रहे हैं। सर, समाजवादी पार्टी ने हमेशा सैक्युलर मूल्यों का पालन किया है। ...**(व्यवधान)**... ये अकर्मण्य लोग उदासी ले आए, तीन-तीन बार मैंने बता दिया है और ये नफरत का बीज बोते रहे। हमारे दल और हमारे नेता को देश

के संविधान की रक्षा के लिए गोलियां चलानी पड़ीं, तो गोलियां चलाई। हमारे 16 कार सेवक मारे गए और आपने यह आरोप लगाया कि उन कार सेवकों के खून से मुलायम सिंह के हाथ लाल हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : बैठिए, बैठिए। Please, sit down. आप सुनकर जवाब देना सीखिए। ...**(व्यवधान)**... डिस्टर्ब मत कीजिए। Please, आप बैठिए।

श्री अमर सिंह : हमें इस बात का दुख है कि 16 कार सेवकों की मृत्यु हुई। किसी की भी जान जाती है, तो हमें दुख होता है, लेकिन हिन्दुस्तान के संविधान की रक्षा करने के लिए तथा कानून बचाने के लिए, हिन्दू-मुस्लमानों के दिलों को टूटने से बचाने के लिए 16 की जगह यदि 1600 लोग भी मर जाते, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ...**(व्यवधान)**... देश बड़ा है और देश का कानून बड़ा है। देश कानून से चलता है, आपकी भावनाओं से नहीं। ...**(व्यवधान)**... देश जज्बात से नहीं, कानून से चलता है। ...**(व्यवधान)**... समाजवादी पार्टी और हमारे नेता मुलायम सिंह यादव ने ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद : उत्तर प्रदेश का वोट बैंक। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंह : मुलायम सिंह यादव ने ...**(व्यवधान)**... अयोध्या, मथुरा और काशी इस विवाद की सारी जड़ वही हैं।...**(व्यवधान)**...

श्री विनय कटियार : *

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, why are they continuing to interrupt like this?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing that they are saying will go on record.

श्री अमर सिंह: हमने सारे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा की है। ...**(व्यवधान)**... मैं यहां पर दिनकर जी को उद्धृत करते हुए कहना चाहता हूं कि ...**(व्यवधान)**...

श्री विनय कटियार: *

श्री उपसभापति: प्लीज़, कटियार जी, बैठिए। ...**(व्यवधान)**... आप बैठिए, बैठिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री विनय कटियार : आज इस सदन में नाम लेकर अपमानित किया जा रहा है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आपकी पार्टी को जो समय है, आप उसमें बोलिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंह: आपका नाम लिया है, तो हम इसको वापस लेते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप बोलिए। ...**(व्यवधान)**... आप बैठिए।

श्री विनय कटियार: अमर सिंह जी, आधा मिनट बोलने दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: Please. यहां ऐसे नहीं चलेगा, जो आप अमर सिंह जी से वक्त ले रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... मैं चेयर पर बैठा हूं और आप अमर सिंह जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यह क्या बात है? ...**(व्यवधान)**... वे समय देंगे, तो क्या मैं नहीं दूंगा? ...**(व्यवधान)**... आप बैठिए।

श्री विनय कटियार: यह सदन संविधान के कानून से चलता है। आप कानून बताइए कि किस नियम के अंतर्गत सदस्य नहीं बोल सकता है? ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती वृंदा कारत : बोल सकता है। ..**(व्यवधान)**..

श्री उपसभापति: जो यहां नियम है, वह मैंने पहले ही पढ़ा है। ...**(व्यवधान)**... देखिए, it is not that...*(Interruptions)*... Please. It is given, "...A Member during the course makes any allegation..." It is not an allegation. ...*(Interruptions)*...

*Not recorded.

SHRIMATI BRINDA KARAT: This is the truth....*(Interruptions)*....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is your view, not my view.

श्री विनय कटियार : यह कोर्ट नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : देखिए, आपने कहा है कि हाउस rules पर चलता है और चेयर की कुछ अथॉरिटी है, rules की कुछ interpretations हैं, वह देखकर, I have given the ruling. You must respect it.

श्री बलबीर पुंज (उड़ीसा): उन्होंने जब रिपोर्ट में नाम लिया, विनय कटियार ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: मैं मानता हूं। ...**(व्यवधान)**... जरा सुनिए, जहां उन्होंने adjectives add किए हैं, मैं वे डिलीट करूंगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, अपमानित करने की भावना दिखाई है। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप उनका नाम लीजिए और रिपोर्ट में जिस तरह से उनका नाम लिखा गया है, उसी तरह से लेना चाहिए, दूसरा और कोई adjectives नहीं लगाना चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: ये तो सदन को चलने ही देना नहीं चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप वह सब छोड़िए। ...**(व्यवधान)**... हम चलाएंगे। ...**(व्यवधान)**... सदन सबके cooperation से चलता है। ...**(व्यवधान)**... वे भी cooperate कर रहे हैं। Please. ...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंह: उपसभापति जी, यदि इनको * कहने पर आपत्ति है तो मैं इसे वापस लेता हूं ...**(व्यवधान)**...

श्री विनय कटियार: हम * नहीं हैं...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंह: ये * नहीं हैं...**(व्यवधान)**... मैं वापस लेता हूं...**(व्यवधान)**...

श्री विनय कटियार: सर, एक मौका दीजिए...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: मैं मौका नहीं दूंगा...**(व्यवधान)**... आप बैठिए...**(व्यवधान)**...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: सर, ये बहस नहीं होने देंगे...**(व्यवधान)**... इनकी पहचान ...**(व्यवधान)**... उजागर हो चुकी है...**(व्यवधान)**...

श्री विनय कटियार: उपसभापति जी...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: बोलिए...**(व्यवधान)**... आप बैठ जाइए...**(व्यवधान)**... यह क्या तरीका है...**(व्यवधान)**... आपकी कोई व्हिप नहीं है...**(व्यवधान)**... कभी रूल्स की बात करते हो...**(व्यवधान)**... कभी रूल्स तोड़ते हो...**(व्यवधान)**... आप ही रूल्स की बात करते हो...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंह: दर्द उठता है जिगर में, कभी दिल दुखता है...**(व्यवधान)**...

श्री विनय कटियार: उपसभापति जी...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: ठीक है...**(व्यवधान)**... क्या कह रहे हैं...**(व्यवधान)**...

श्री विनय कटियार: सर...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप जो सही समझते हैं, मैं वह बोल नहीं सकता हूं...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंह: मैं कह रहा हूं कि दर्द उठता है जिगर में, कभी दिल दुखता है, कुछ ये अच्छे नहीं आसार खुदा खैर करे। आप सदन के बाहर भी कानून को नहीं मानेंगे, सदन के अंदर भी रूलिंग को नहीं मानेंगे, यह आपका स्वभाव हो गया है...**(व्यवधान)**... और देश के कानून को बचाने के लिए ...**(व्यवधान)**...

---

*Not recorded.

श्री विजय कुमार रूपाणी (उड़ीसा): उपसभापति जी, ये चार्ज लगा रहे हैं...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंह: मैं चार्ज नहीं लगा रहा हूं...**(व्यवधान)**... सर, ये बहस नहीं करने देंगे...**(व्यवधान)**... सर, मैं कहना चाहता हूं...**(व्यवधान)**...

श्री विनय कटियार: उपसभापति जी, कौन सा कानून नहीं मान रहे हैं...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: क्या परंपरा है, आप मुझे बता रहे हैं...**(व्यवधान)**... देखिए, वे आपकी जबान नहीं बोलेंगे...**(व्यवधान)**... आप जो चाहते हैं, वो नहीं बोलेंगे...**(व्यवधान)**... वो जो चाहते हैं वो बोलेंगे...**(व्यवधान)**... जब तक कोई वर्ड अनपार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है और कानून के खिलाफ नहीं है, आप हर वक्त उठकर बोलते रहेंगे तो कैसे चलेगा...**(व्यवधान)**... जब आपकी पार्टी आपको मौका देगी तो उनको refute कीजिए...**(व्यवधान)**... यह सही नहीं है कि आप उनको हर वक्त टोकते रहें, तब आप यह बताइए कि डिबेट कैसे चलेगी।

श्री सीताराम येचुरी: जो रिपोर्ट में लिखा है...**(व्यवधान)**... इस तरह से सच्चाई साबित हो रही है।...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंह: 6 दिसम्बर, 1992 का अपराध छुपा रहे, ढका रहे, इसके लिए कोई बहस नहीं होने दे तो हम क्या करें? हम यह कहना चाहते हैं कि National Integration Council की मीटिंग में सत्यनारायण रेड्डी ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी को भी लिखा, हमारे नेता मुलायम सिंह जी ने कहा और श्री हरकिशन सुरजीत जी ने भी कहा कि मस्जिद नहीं बच रही है, उसकी शहादत हो रही है। इसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। मैं कहना चाहता हूं कि लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट में, जिनको दोषी ठहराया है, हम उससे सहमत हैं, लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि उनको और ज्यादा दोषी ठहराया जाना चाहिए और इतिहास के पन्नों और हमारे हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों के दिल में इस अपराध में तत्कालीन प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष की संलिप्तता को छोड़ना नहीं चाहिए था। मैं यह कह रहा हूं। सर, इसमें विसंगतियां भी हैं। विसंगतियां कुछ विचित्र हैं। रिपोर्ट के पेज 336 में गुलजारी लाल नंदा को रज्जू भैया ...**(व्यवधान)**... और दाऊ दयाल खन्ना के साथ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: अमर सिंह जी, डिबेट के टाइम का ध्यान रखें।

श्री अमर सिंह: सर, हम जल्दी खत्म कर देंगे।

श्री उपसभापति: उसको निकालकर भी...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंह: जल्दी खत्म कर देंगे। गुलजारी लाल नंदा, रज्जू भैया और दाऊ दयाल खन्ना के साथ उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया। जबकि सर्वविदित है कि श्री नंदा ने सत्तर के दशक में सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था और बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले उनकी मौत हो गई थी। इस तरह की विसंगति के लिए मुझे हंसी आती है। हो सकता है कि इस विसंगति की जांच के लिए एक और कमीशन बिठा दिया जाए। इस कमीशन का समय पूरा होने में सत्रह साल लगे, हो सकता है कि विसंगति की जांच करने वाला कमीशन चौंतीस साल का समय ले ले। यह हो सकता है। और तो और जिसका घर टूटा, जिसकी मस्जिद शहीद हुई, उस बाबरी मस्जिद ऐक्शन कमेटी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरुद्ध भी टिप्पणी हो गई। मुझे यह समझ नहीं आता कि आप मस्जिद की शहादत करने वालों की जांच कर रहे थे या मस्जिद वालों के ऊपर आप रिपोर्ट कर रहे हैं। जाफरयाब जिलानी, जो बाबरी मस्जिद ऐक्शन कमेटी के संयोजक हैं, की बात से मैं सहमत हूं, उन्होंने इस मसले पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। मैं बाबरी मस्जिद ऐक्शन कमेटी के संयोजक श्री जाफरयाब जिलानी की बात और उनके विचारों से पूरी तरह से सहमत हूं, मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन अगर ये विसंगतियां नहीं होतीं तो आदरणीय गृह मंत्री श्री चिदम्बरम् जी इस कमेटी की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्नवाचक चिह्न नहीं लगता। जैसा कि हमारे मित्र अहलुवालिया जी कह रहे थे

कि एक तिथि गलत है या गुलजारी लाल नंदा, जिनकी मृत्यु इस शहादत से पहले ही हो गई, उनको नामजद कर दिया गया है, नरसिम्हा राव जी को छोड़ दिया गया है। इन तमाम विसंगतियों के कारण, हम यह नहीं कह रहे हैं कि अटल जी का नाम क्यों जोड़ा गया, क्योंकि समतलीकरण की बात नेता के रूप में उन्होंने की थी, मैं उनका जितना सम्मान करूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के एक पथ-प्रदर्शक और एक नेता के रूप में वे अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते। सबसे बड़ी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आयोग की रिपोर्ट चाहे जितनी लचर थी, उसके बनने के बाद आपको उसे यहाँ तक लाने में पाँच महीने लगे और इन्तजार करना पड़ा कि पहले अखबारों में leak हो जाए। आज तक रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट नहीं आई। रंगनाथ मिश्र आयोग भी अखबारों में आ गया है। पहले हम यहाँ बोलते थे और अखबार छापते थे, लेकिन अब अखबार छापते हैं, तब हम बहस करते हैं। क्या अद्भुत परम्परा आ गई है! अब रोज सवेरे हम अखबार पढ़ते हैं, तो हमें यह मिलता है कि आज हम सदन में क्या करें। पहले हम सदन में करते थे और उसकी रिपोर्ट होती थी। यह लोकशाही का मन्दिर है, इसका मजाक मत उड़वाइए, मैं यह कहना चाहता हूँ।

देश के एक बड़े युवा नेता, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वे इस सदन के सदस्य नहीं हैं, वे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में थे। वहाँ पर मुसलमान भाइयों ने पूछा कि क्या देश का सबसे बड़ा पद, प्रधान मंत्री का पद, कभी मुसलमान को मिलेगा? उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जो सबसे ऊँचा पद है, वह merit के आधार पर मिलेगा, जाति और धर्म के आधार पर नहीं। मैं कांग्रेस की बात करूँ, अपने दल की बात क्यों करूँ, क्योंकि कांग्रेस बड़ा दल है, 50 साल से ज्यादा समय से शासन में है। मौलाना आज़ाद, रफी अहमद किदवई, डा. ज़ाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति तो हो गए, क्या इनमें से कोई प्रधान मंत्री बनने के काबिल नहीं थे? यह प्रश्न है मेरे मन में ...**(व्यवधान)**...

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): इसका इस रिपोर्ट से क्या मतलब है? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: बैठिए, बैठिए ...**(व्यवधान)**... आप बैठिए प्लीज़ ...**(व्यवधान)**... अमर सिंह जी, आप बोलिए ...**(व्यवधान)**...

[उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) पीठासीन हुए]

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन) : बैठिए, बैठिए ...**(व्यवधान)**... Please take your seats ...*(Interruptions)*... बैठिए, बैठिए ...**(व्यवधान)**... No, please ...*(Interruptions)*... Please allow him to speak ...*(Interruptions)*... Take your seat ...*(Interruptions)*... No, no, no. That is only his opinion, why do you worry? ...*(Interruptions)*... No, please.

श्री अमर सिंह: जो तुमको हो पसन्द वही बात कहें ...**(व्यवधान)**... तुम दिन को कहो रात, तो रात कहें ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Amar Singhji, address the Chair. ...*(Interruptions)*... Take your seats.

श्री अमर सिंह: सर, यह कहना कि राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता था, मैं बहुत संक्षेप में कहूँगा, बड़े वकील, मेरे बड़े भाई कपिल सिब्बल बैठे हैं, वे असहमत नहीं होंगे, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, वे नाराज होंगे, लेकिन असहमत नहीं होंगे ...**(व्यवधान)**... The Constitution mentions three types of

Emergencies. When the security of the country is threatened by war, external aggression, or armed rebellion — Article 352. Armed rebellion तो हो गया अयोध्या में। And, when the financial stability of the country is threatened — Article 360. लग सकता था। क्यों नहीं लगा? देश बचता, लोगों के दिल टूटने से बचते। दूसरी बात, लिब्रहान की रिपोर्ट में तीन बिन्दु दिए गए हैं। इसकी क्या जरूरत थी? यह कहा है — हिन्दुत्व, Leaders are * — All leaders, which include our entire fraternity sitting here, in the middle and that side — और सब नेता * हैं। हम लोगों को * बताते-बताते रिपोर्ट में 100 पन्ने लिखने में 17 साल लगाई है। इतने extensions लिए हैं, भत्ते लेते रहे, 8 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन हम सब * हैं, आपसाधु हैं। ठीक है, हम * हैं। आपने रिपोर्ट में लिख दिया, हम कैसे कहें, आप जज साहब हैं। उसमें आपने एक चीज़ लिख दी कि मंडल की वजह से खरमंडल हुआ है। यह देश के पिछड़ों का अपमान है। क्या यह assignment था उनका? यह कांग्रेस की सरकार द्वारा नियुक्त की गई है और इस रिपोर्ट में मंडल के ऊपर हमला, पिछड़ों के ऊपर हमला। अगर वे यह सब नहीं करते, ये सब विसंगतियाँ नहीं करते, मंडल का नाम नहीं लगाते, उसका खरमंडल नहीं करते, तो इसकी प्रमाणिकता ज्यादा होती। मुझे इस बात का दुख है कि इतनी लम्बी अवधि के बाद आई रिपोर्ट, जिसमें तमाम अपराधियों को चिन्हित किया गया है, वह इन विसंगतियों की वजह से हल्की हो गई है। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बाबरी मस्जिद के विवाद का मामला है। आपकी ओर से सदन में अर्जुन सिंह जी ने कहा कि मस्जिद बनाएंगे और इन्होंने कहा कि मन्दिर बनाएंगे, लेकिन मन्दिर-मस्जिद दोनों नहीं बने। अब एक बहाना मिल गया है कि वह अदालत में चल रहा है। 1987 से लेकर आज तक 20 साल से अधिक हो गए हैं, अभी तक अदालत में चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। हम कहते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि हम मर जाएं और हमारे बच्चे भी बूढ़े हो जाएं तब तक भी निर्णय न आए।

यह एक अद्भुत तरीका है मैनेजमैंट का। मन्दिर है या मस्जिद है, आप 'Fast Track Court' लाइए, जहां within six months decision होता है। आप भ्रमित मत करिए। आप 'Fast Track Court' लाइए और छः महीने के अन्दर इसका निर्णय कीजिए। लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सभी आरोपियों पर नये सिरे से मुक़दमे दायर किए जाएं, चाहे वे आज के संघीय नेता हों, हमारे कल के दोस्त कल्याण सिंह हों या आपके पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और कांग्रेस के नेता शंकर सिंह वाघेला हों, आप किसी को मत छोड़िए। सबकी खबर लें और सबको खबर दें, आप यह करिए। चाहे वह जगदम्बिका पाल हों, जिनका नाम कार सेवक के रूप में लिया गया है। आप हिन्दुओं और मुसलमानों की भावनाओं से मत खेलिये।

मैंने अपनी बात श्री कृष्ण के नाम पर, गीता के नाम पर शुरू की थी, इसलिए अल्ला के नाम पर बात खत्म करूंगा। मैं यही कहूंगा कि या अल्ला! जिसने तेरा घर तोड़ा है, तू उसका गुरूर तोड़ना और या अल्ला! जिसने तेरा घर बचाया है, तू उसकी आबरू बचा लेना। घर चाहे इधर के लोगों ने तोड़ा हो या उधर के लोगों ने तोड़ा हो, इनका गुरूर तो जरूर टूटेगा और हमारे नेता मुलायम सिंह जी, जिन्होंने घर बचाया है, उनकी आबरू बचेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Thank you. Now, Dr. Abhishek Manu Singhvi.

DR. ABHISHEK MANU SINGHVI (Rajasthan): Mr. Vice-Chairman, Sir, and, hon. Members of this House, I have heard with rapt attention my good friend, Shri Amar Singh, and, also with attention the various interruptions. Sir, at one level, this debate is not necessary. Fortunately, this country has moved forward and it does not need to look back. India, rightly, looks upon

*Expunged as ordered by the Chair.

now as a united nation, a nation of proud Indians. But, Sir, sadly, this is not because of, but in spite of one of the most vicious campaigns to divide the country along fault lines which could have become unbridgeable chasms.

Sir, the fact that it did not happen is our good fortune but not for want of trying by one political party. So, Sir, may I with utmost respect submit that this debate must take place? It must take place as a stark reminder of how perilously close we came to destroying India's proud secular heritage. But, more importantly, Sir, this debate must take place as a catharsis, as an outlet to emotions. This debate must take place so that all of us, sitting on this side and that side, can come to terms, and, you cannot come to terms without truth and reconciliation. And, therefore, this debate must take place because we, the people of India, must learn the lessons of history, without which we are bound to be condemned to repeat its errors.

Sir, sometimes, shared anguish can also be a bridge to reconciliation, and, therefore, most importantly, this debate must take place because we must call a spade a spade, and, also because this country has a right to know. Sir, when you delve deeply, what do you find out, and, what does this country come to know? There are many sub-themes in this voluminous Report. I am going to touch upon five broad factual areas, five broad themes, which I will deal with one by one. Apart from those five broad themes, there are several sub-themes which time does not permit me to deal with, but I must identify and itemise them for this august House because those sub-themes in a sense are more important than the broader factual themes. So, just for identification, before I come to my main five themes, the first broad subtheme is that this was, let us accept it, a sad, sordid saga... ...of brazen cheap politics, that was played with dangerous, uncaring abandon for life, liberty and property of the *Aam Aadmi*. The second sub-theme is that it is a story about pelf, about power and about politics. It was about self-aggrandizement, in particular, that of one man, a person who was then the President of the BJP and is today the Leader of Opposition. The third sub-theme, Sir, is the age-old question which the Liberhan Report, the Babri issue raises: Who will guard the guardians? What will happen when protectors become predators? And, we found that happening in UP, at the top Constitutional post in UP, at the level of administration. रक्षक जब भक्षक बन जाते हैं, तब यह मुद्दा उठता है। The fourth sub-theme, Sir, is that of utter hypocrisy, of double-faceted conduct of fark tongued speech; and I am going to give some examples of that presently. The Fifth sub-theme, Sir, is the attempted demolition, they demolished one *masjid*, but the larger sub-theme is the attempted demolition of secularism itself. Indeed they attempted demolition of the very idea of India which the Home Minister mentioned yesterday. Ultimately, it is that very idea and the pillar of that idea is secularism which singles us out, marks us out from each of our neighbours in South Asia. Ask yourself this simple question, between 1930 and 1960, so many countries

became independent from the yolk of imperialism, and yet India is the only country, out of 20-30-40 countries across Africa, Asia, South Asia, South America, the only country which remains a proud democracy. It is that pillar which was sought to be demolished by 1992.

Sir, as I turn to my first broad theme out of the five themes, I must remind this House of just one thing. The central theme of this debate has to be remembered time and again, and we have to remind ourselves of that central theme. The central theme, the highway issue, is only one. Mr. Vajpayee is not the highway issue; Mr. Narasimha Rao is not the highway issue; factual inaccuracy is not the highway issue; Deoraha Baba is not the highway issue; Jagdambika Pal is not the highway issue; leakage is not the highway issue; Gulzarilal Nanda is not the highway issue; they are all by lanes and alleyways in which some of our friends want us to get lost. The Highway issue is only one — who broke the mosque? Why did they do it? How did they do it? And, we have to come back to that each time to set our goals right, to set our plans right. महोदय, मैं पहले मुद्दे पर आता हूँ। वह पहला मुद्दा यहहै कि बी0जे0पी0 और बी0जे0पी0 के तथाकथित परिवार ने एक ऐसे मुद्दे को चुना, जो लगभग पाँच सौ वर्षों से शांत था और लुप्त था। उसको जान-बूझकर एक विस्फोटक राजनीतिक मुद्दा बनाया, जो पाँच सौ वर्षों से किसी जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया था, सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए। मैं इस पर आपको 4-5 निष्कर्ष अभी submit करूँगा, लेकिन इस तथ्य को पुरज़ोर करने के लिए आप gaps देखिए। आप पाँच तिथियाँ देखें और gaps देखें।

सर, पहला गैप है-1528 से लेकर 1767 तक। वहाँ पर चबूतरा पहली बार 1767 में बना, लेकिन उन 200 वर्षों में कुछ नहीं हुआ। दूसरा गैप है- 1767 से लेकर 1885-86 तक। आप जानते हैं कि 1885 में इसमें suit हुआ, इसके बाद अपील हुई और 86 में अपील खारिज हुई। इस तरह 1767 से 1885 तक कोई उथल-पुथल नहीं हुई । वहाँ पर शांति थी। वहाँ पर जो था, वह था। सबसे ज्यादा अगर कुछ था, तो वह एक लोकल मुद्दा था। गैप का जो तीसरा पीरियड है- वह 1886, यानी जब सूट और अपील खारिज हो गए, उसके आगे से लेकर 1934 तक, जब पहली बार 1934 में कुछ साम्प्रदायिक दंगे हुए, लेकिन 1886 से 1934 तक कोई खास उथल-पुथल वहाँ पर नहीं था, जिसका जिक्र माननीय अमर सिंह जी ने किया, 1949 से लेकर 1985 तक, यानी हमारी स्वतंत्रता के 40-45 वर्षों बाद तक, वहाँ कोई incident नहीं हुई। उथल-पुथल नहीं हुई, जान-माल की हानि नहीं हुई। इसका निष्कर्ष क्या है? इसके चार या पांच निष्कर्ष हैं। मैं इनको संक्षेप में कहूँगा और पहले मुद्दे पर अपनी बात का अंत करूंगा।

इसका पहला निष्कर्ष है कि यह मुद्दा, न तो मुद्दा था और अगर मुद्दा था तो सबसे ज्यादा यह लोकल मुद्दा था। यह न तो प्रादेशिक था और न अखिल भारतीय था। दूसरी बात यह कि हर जिम्मेवार राजनैतिक पार्टी ने स्वतंत्रता के पहले और उसके बाद कभी उस मुद्दे को विभाजन का मुद्दा बनाने का प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने इससे सस्ती राजनीति नहीं खेली। उन्होंने इसको साम्प्रदायिक रंग देने का कम से कम प्रयत्न किया। तीसरा, इस पूरे गैप पीरियड में एक वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है और वह है वर्ष 1984, जब एक विपक्ष की पार्टी को सिर्फ दो सीटें मिलीं। उस वक्त वे राजनैतिक वनवास पर थे और जंगलों के सत्ताविहीन जीवन से शायद बौखला गये थे। चौथा निष्कर्ष, इसीलिए उन्होंने सोच-समझ कर 1986 से इसे शुरू कर दिया, लेकिन 1989 में औपचारिक रू प से पालमपुर में प्रस्ताव रखा। पहली बार एक राजनैतिक पार्टी ने जान-बूझ कर इसको एक राजनैतिक मुद्दा बनाया, विभाजन का मुद्दा बनाया, ळागड़े का मुद्दा बनाया और हमको बांटने का मुद्दा बनाया। क्यों? क्योंकि बांटो और शासन करो, divide and rule. अगर हम अपने साम्प्रदायिक imperial masters, बेचारे ब्रिटेन को

इतना criticize करते हैं तो जो लोग आज हमारी स्वतंत्रता के 50 साल बाद divide and rule की एक औपचारिक नीति, जो उन्होंने पालमपुर के अपने प्रस्ताव में उठाई, उनका क्या कहें? वह अवसरवादी स्वार्थ की राजनीति थी।

इस पहले मुद्दे का अंतिम निष्कर्ष यह कि उन्होंने बिना सोच-समझ कर यह नीति अपनाई, यह प्रस्ताव अपनाया कि इसके क्या दु:खद परिणाम जान के लिए, माल के लिए और आम आदमी के लिए हो सकते हैं। कम से कम 2000 लोगों की मृत्यु हुई है और जो लोग घायल हुए हैं, अगर आप आज भी उस जिले में जाएं तो पाएंगे कि वे काम नहीं कर सकते, बेघर हैं और लापता हैं। इसके अलावा, जो एक बहुत बड़ा चिरस्थायी मनोवैज्ञानिक दाग होता है, चोट होती है, वह यह कि इनमें से किसी बात पर उस राजनैतिक पार्टी ने ध्यान नहीं दिया।

Sir, now I come to the second major issue. The first is the creation, invention, and enhancement of a non-issue into a politically divisive issue. The second is the carefully conceived, cold-blooded, and calibrated conspiracy to ensure the demolition on 6th December with humongous logistical preparation and enormous pre-planned conspiracy. The most amazing part of my second issue is that the BJP wants us to believe that this was a spontaneous action. Obviously, the BJP thinks that they eat grain while the rest of this country and this House eat grass. Obviously, they think that with this humongous logistical preparation, about which I will talk in a moment, this action was spontaneous, there was no pre-planning.

Sir, consider this. The number of people present there was 200,000. This is the most conservative estimate. There were thousands of trucks, buses, and transportation. They were housed, fed, and kept for over 3-5 days, possibly a week. There were heavy implements and tools. Apparently, along with the spontaneous action, they also dropped from heaven like lightning. That is what the BJP would like us to believe. There were heavy implements, efficient implements to bring down that mosque which was an eyesore to their eyes. On training, you don't need to read the Liberhan Commission Report. Pick up *The Indian Express* of 6th December. It shows you ***karsewaks*** using long rope, carrying huge boulders and pulling it along, and undergoing training. I am sorry this was on 5th; the newspaper was of 6th. Logistics, buses, implements, training, all this happened spontaneously. Consider the amount of money. We are in economic meltdown; the world was in economic meltdown a year ago. I think, the amount of money spent was hundreds of crores of rupees with which we could have combated a lot of economic meltdown. It would have helped Mr. Pranab Mukherjee bridge many Budget deficits. But, this money was through accounts and through institutions which had no accountability. Maybe, the money was raised in the name of God Ram who didn't ask for accounts and maybe, money used to lie in the pockets of those who spoke in the name of Ram! Sir, journalists were manhandled. A person as eminent as Mark Tully — read his report — was kept under restraint, not allowed to reach the site and his equipment were destroyed. Why? Because he knew what was going to happen on 6th. You didn't want an immediate eye-witness account which could have gone to BBC the same night.

Remember, in 1992, the media in India was not as सर्वव्यापी as it is now. This is the action which BJP wants us to believe as spontaneous action. Sir, the Liberhan Commission is a formal vindication, but this Party and its conduct was damned in the eyes of the public eighteen years ago. You didn't need a Liberhan Commission report for that. You needed common sense and the BJP wants us to use 'uncommon nonsense'. Sharat Pradhan, in rediff.com, in an eye-witness account, said that the cops, who were under the District Magistrate's control, who reported directly to one man, the then U.P. Chief Minister, whose name I won't take, said, "Go faster. Don't waste time. Take this way." Warning came on the public address system. I quote, "All those on top of the disputed structure must come down as the structure is about to crumble." हिन्दी में थी वार्निंग। यह spontaneous action का एक उदाहरण है! These are hundreds of examples. Guardians had become devouces. Who would guard the guardians is the issue because the U.P. Government had become a parallel Government of the Sangh. The BJP Government of U.P. had been outsourced by the then Chief Minister to the mother organisation which always had the remote control. Can you imagine, Sir, there was not one single video recording of the entire episode when the Supreme Court was monitoring it and when everybody in the whole country was looking at it? Who had to manage law and order? It was the State Government. If you want additional facts, there are several books. You just have to go through those books and see them. Sir, that is the second aspect. As I said, cold-blooded, calculated and calibrated conspiracy which you require us to believe was a spontaneous action.

Sir, the third aspect is hypocrisy and double-facedness. Sir, Gandhiji said that hypocrisy and distortion are passing currents under the name of religion. But, to the BJP, more apt is the comment that the true hypocrite is the one who ceases to perceive his deception and who lies with sincerity. I must congratulate them for lying with sincerity. That is really true hypocrisy. Let me give you two or three examples. I would just make two quotes of the then President and the current Leader of Opposition in Lok Sabha. First quote is of BBC News of April 5, 2004. He said, "What happened in Ayodhya should never have happened. I was so upset with the demolition of the mosque. It hurt me tremendously." Then, on November 22, 2009, he said, "But the establishment of a huge Ram Temple on that spot in keeping with people's aspirations is my aim in life and until it happens, I will pursue it." Is it the saddest moment of his life or the happiest moment? We don't know. Even a crocodile has more genuine tears. We just insult the crocodile when we see such examples. The learned Member of the House, who was protesting a short while ago, at least, is to be commended because he has the courage of his convictions. Unlike the President of his party, who was playing hypocrisy and double-facedness, the Member who is here, clearly said कि कुछ बिगाड़ने पर ही कुछ बनता है। And he, at that time, had said that it was the happiest moment of his life. At least, he was honest, candid and transparent. The President of his Party was not. Is it like Alice in Wonderland or like Humpty Dumpty that you can say in the same sentence, it hurts me tremendously, it is the saddest day of my life, and then you say in

keeping with the people's aspirations to make a temple on that spot is my aim in life. Well, I don't know. Like Alice in Wonderland words mean what the Leader of the Opposition thinks or says and they mean that.

The third prima donna in this — I am only on the hypocrisy and double-facedness, the forked-tongue — is the then UP Chief Minister. There is no greater flip-flop-flop and flip-flop-flip which you can find in the history of politics and possibly in the history of joining, unjoining and rejoining parties. There is a story about Elizabeth Taylor; Richard Burton having married, divorced and remarried six times. I don't know if the then UP Chief Minister is trying to better that record in terms of political marriage, political divorce, political re-marriage, political re-divorce, and political re-remarriage. He, of course, said first that it was a conspiracy against him by the BJP leaders. This is the then UP Chief Minister. It was a conspiracy to oust him. Then he said recently and many times again, "the earlier the temple is built, the better it is for the nation so that the Babri Mosque can never come up there". These are the people, and let me add now, at least, we have been trying to explain. There is a certain amount of explanation, call it 'great' or call it 'genuine' contrition. I don't find any contrition, regret, anywhere there on the other side. But we have never glorified it, whatever our faults, whatever our imperfections are. The other side, this political party, has glorified this event. Each one of the names was mentioned in the Report. I can take the names because they are in the Report. But each one of them has been promoted and occupies a central position in their party. The then President of the BJP, the permanent Prime Minister in waiting, is the current Leader of the Opposition. The Member who interjected was the UP chief of the BJP. One important political party head was their coalition partner in Maharashtra. Another person listed in the Report, Mr. Singhal, was a Member of the Rajya Sabha till recently. Another person listed in the Report, Shri K. Sudarsan, was the head of the RSS. Another gentleman was the President of the UP BJP. At least, some persons, including an expelled BJP member, were more honest about their feelings, the expelled BJP member being one from Madhya Pradesh, the lady. They, at least, spoke their heart honestly. But here are leaders who practise deception on the country, who spoke with forked tongue. That is my third broad issue.

My fourth broad issue, given the 16 or 17 years which have passed, about the very clever manner in which criminal proceedings have been dodged and avoided at different places is also important. Just consider these brief facts. On the day of the demolition two FIRs were filed, one was called "97" and the other was called "98". The FIR 97was against "lakhs of unknown karsevaks" when was a nameless cadre, an anonymous cadre. Shortly thereafter, FIR 98 specifically charged a conspiracy hatched on 5th December and the people named in the FIR are the present Leader of the Opposition, Shri Murli Manohar Joshi, Ms. Uma Bharati, Shri Ashok Singhal, Shri V. H. Dhalmiya, Sadhvi Rithambara and a few others. Curiously, the FIR 97 "lakhs of unknown karsevaks" was assigned to the CBI. The FIR 98 was assigned initially to the State CID. Subsequently, the CBI filed a joint chargesheet.

श्री कलराज मिश्र: किसके द्वारा किया गया?

DR. ABHISHEK MANU SINGHVI: When you hear the last date, then, perhaps, you won't interrupt. I am only giving the sequence. Who else than you know it better? Who else than the Leader of the Opposition know it better? The heart of the chargesheet was a secret meeting of 5th December naming people. The Special Judicial Magistrate on 27th August, 1994 committed those listed in the chargesheet to trial. The Additional Session Judge on 9th September, 1997 framed the charges and found them *prima facie* liable to be prosecuted. On 12th of February, 2001, a fortuitous event occurred which is being distorted. Justice Bhalla of the High Court on a purely tactical jurisdictional ground said, "You could not transfer case-1 to case-2. You could not issue a notification without consulting the High Court." But in the same order he said three times, "It is a curable defect. You can issue a notification tomorrow after consulting the High Court." He also said, "I specifically uphold the joint chargesheet which the CBI had filed and on which the Additional Sessions Judge, J.P. Srivastava, on 9th September had framed charges." Despite this, astonishingly, with the High Court only talking about jurisdictional point of consultation for a notification for transfer and upholding the main chargesheet, the Additional Sessions Judge, Shrikant Shukla, of Lucknow on 4th May, 2001 dropped the conspiracy charge from the FIR 197 altogether. In September 2002, case 198 was retransferred to Rai Bareilly. We are already, from 2001 onwards, in the NDA rule. The dates here are of 2001. On 30th of May, 2003, bang in the middle of the NDA rule, the CBI files a fresh charge sheet, but themselves, for the first time dropped the charge of conspiracy against Mr. Advani. Remember, the chief allegation in the original FIR was, on the 5th of December you all sat together and hatched the conspiracy that tomorrow you will demolish. The CBI files the charge sheet on 30th May, 2003 — mark the year — dropping, for the first time itself, not taking the charge of conspiracy. On 19th of September, Mr. Advani, is discharged by an order by the Judge, Shri V.K. Singh. This is the episode when one Anju Gupta's testimony was taken; who was the Special Police Officer, standing there said that he made no attempt to stop the whole thing. He did not stop it. Anyway, that result comes. Luckily and fortunately, the 19th September order has been set aside by the High Court and the discharge order has been set aside. The net result of all these tactical shenanigans has been that largely during the period of 1999 to 2003, coupled with the earlier initial delays in any matter of this sort, for 16 long years, along with the Liberhan delay, the *prima donnas* have avoided criminal culpability. They have avoided even reaching a healthy stage of criminal culpability in that procedure. That is my fourth aspect.

The fifth aspect is the aspect about the highways and the alleys I talked about, that post-Liberhan, we have, at least, five or six complete red herrings taken up by several persons, principally the BJP. But, unfortunately, our good secular friends and Shri Amar Singh's party also, sometimes, falls into the trap and joins them and taking up those red herrings. The first red

herring is a complete non-issue. As I said, the main issue in the Liberhan report is who broke the mosque, how did they do it and why did they do it. The first red herring after the report is the so called leakage issue. First of all, I hope, I don't have to belabor the point to a House of this eminence that if a report is leaked all the contents of the report should be thrown to the dustbin. I don't think we have reached that stage in this country where we take such an extreme position that because the report is leaked, therefore, all its contents are garbage. Perhaps, somebody did want us to believe that. I want to ask one question to appeal to your logic, to your mind. Why on earth would this Government, this Home Minister or this Home Ministry leak this report? This Home Ministry was to Table the report latest by 22nd December. If it could do it earlier, why should they leak it? There are, of course, also official writings from both The Indian Express and the NDTP saying that they have received no unofficial copy.

The second red herring and non-issue is Shri Atal Bihari Vajpayee. I happened to take the briefing when the whole issue of leakage came. I said that there appears to be basis to say that if Mr. Vajpayee is in the list which says 'individually culpable', he should have got an 8B notice. Mr. Vajpayee is a respected leader of this country and a former Prime Minister. But even a non Prime Minister and an ordinary person can get an 8B notice. There is no question of it. Well, Mr. Vajpayee has every right. If he has agreed to go to the Court and get any remark about himself expunged from the court of law, as far as the Liberhan Commission's mention of Mr. Vajpayee is concerned, what earthly connection does it have on the central issue which we are debating, which the Liberhan Commission has dealt with? Yes, there was an error, possibly. That error also will be set aside, if only Mr.Vajpayee invokes his judicial remedy. How does it affect? Apart from anything else, that part is totally separable from the Report. That part is not inexplicably intertwined like a scrambled egg, that you cannot sever Mr. Vajpaee from the Report, and have an intelligent Report left. Why is it said? It is said to mislead the nation, as I said, to take you down an alley-way, a by-lane. Let us pause for a minute. Mr. Vajpayee, maybe, is right technically; there is a technical error. Maybe, he is technically right. But, substantively and morally, the Outlook of 25th February, 2005 — Video Recording of Mr. Vajpayee's 5th of December speech — said, and I quote: "Body language was buoyant; mood was upbeat and strident and his tone was sarcastic." But, I am sure, that is only the Outlook's subjective view. What did he, actually, say? He said, and I quote: "Sharp stones are emerging from the ground. No one can sit on them. ज़मीन को समतल करना पड़ेगा।" Then, he said, "If a *Yagna* begins, there will be some construction." Contemporaneously, the same day, somewhere else, when asked: "Will the mosque be safe?" He said, in his great ambivalence, which, perhaps, helped him reach where he was: "आशा है, आशंका भी।" आशा भी है और आशंका भी है।" Sir, Mr. Vajpayee, certainly, shares some guilt by association. What he should have done is to either change his political party, or, change his friends in 1992. He cannot always run with the

communal hare and hunt with the secular hound. I leave it at that because it is a complete red herring about Mr. Vajpayee.

Sir, about Shri Narasimha Rao, the departed Shri Narashimha Rao, the third red herring; a lot has already been said about the issue. Certainly, everybody in this nation was misled, starting with the Supreme court, then, following with the nation and the Congress (I) party, and, of course, Shri Narasimha Rao. They were misled. They were misled by them. Let us put things in perspective. I am not trying to justify at all. I am only trying to explain. Keep a balance; keep a perspective. Isn't this whole allegation about Shri Narasimha Rao amounting to saying that the principal accused tells you that that policeman did not do his duty properly? The principle accused is telling you from the rooftops that that policeman, who should have acted better, committed an omission. Certainly, the police had to be blamed, if he has been misled. He should not have been misled. But if the police has to be blamed, how much more is the principal accused to be blamed? He should be hanged straightaway. सर, मिर्ज़ा ग़ालिब ने किसी और संदर्भ में, किसी रोमांटिक संदर्भ में कहा था—

"गज़ब किया, तेरे वादे पर एतबार किया"

जो रोमांटिक संदर्भ था, वह उसके बाद था—

"तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया।"

लेकिन हमने भी गज़ब किया, देश ने भी गज़ब किया, उच्चतम न्यायालय ने भी गज़ब किया, कई लोगों ने गज़ब किया कि "गज़ब वादे पर एतबार किया"... ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती वृंदा कारत: देश ने वादा नहीं किया। देश ने ...**(व्यवधान)**...

डा. अभिषेक मनु सिंघवी : नहीं, मैं कल्याण सिंह के वादे की बात कर रहा हूं और कह रहा हूं कि "गज़ब किया, तेरे वादे पर एतबार किया" — गलती हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश और बी.जे.पी. के बारे में मीर की दो पंक्तियां और भी उपयुक्त हैं। उन्होंने कहा था—

"नहीं शिकवा मुझे कुछ बेवफाई का तेरा हरगिज़,
गिला तब हो अगर तूने किसी से कभी निभाई हो।"

यह हमारी और भी बड़ी भूल थी कि हमने ऐसे व्यक्ति पर विश्वास किया, जिसने कभी किसी की निभाई नहीं। ऐसी पार्टी पर विश्वास किया, जिसने कभी किसी की निभाई नहीं, लेकिन ...**(व्यवधान)**... आप सिर्फ उसकी बात सोचते हैं, और भी बहुत से मीर हुए हैं, प्रसिद्ध भी हुए हैं।

Let me now come to how he was misled. Just two quotations. On 25th November, 1992, this is what Mr. Venugopal, our colleague in the Supreme Court, on behalf of the State Government, Mr. Kalyan Singh's Government said. I quote, "If the State Government is not in a position to come forward with a convincing stand that will reassure the Court that no violation of its orders will be permitted, we might have to consider the prayers in the IA for appointment of a receiver or a direction to the Central Government to ensure obedience to court orders. We do hope that the State of U.P. will not compel the court to take that course leaving no other option." This was Mr. Venugopal pleading with the court saying, "Please, do not directly intervene. The State Government will ensure that nothing happens on the 6th of December."

Officially recorded by the then Chief Justice, Venkatachelliah. On 28th of November, three days later, the U.P. Government filed an undertaking saying, "The State Government assures the court that no construction materials or machinery would be on the acquired land and no construction activity will take place or be carried out." This was converted into an undertaking. On this undertaking, for the first time, the only time in the history of India, a sitting Chief Minister suffered contempt. Well, if the Supreme Court could be misled, I think, there is, at least, some explanation as to why contractually others were misled. But, Sir, as the Home Minister rightly put it, we paid the price for it. For whatever little omission, secondary role we had. I would like to put it like that. Remember the perspective. It is between the principal accused and a policeman. But, yes, at the policeman's level, whatever responsibility we had, we paid the price. We paid the price of eight years' political *vanvaas.* And we have expressed remorse and regret for a secondary role. What have you done? A single word of contrition, a single word of regret, a single word of apology? Even today, yes, theday- before-yesterday, your current President said that was like the Quit India Movement. Just the-day-before-yesterday, in the Lok Sabha, he said that it was like the Quit India Movement. That is the level of your contrition; that is the level of your apology!

Sir, issues like Mr. Jagdambika Pal's names, etc., are non-issues. But, let me give you half a line clarification. Jagdambika Pal's name occurs at part 2, page 958. His name is under the heading, "individual culpability for leading the country to the brink of communal discord, the Commission finds these following persons culpable." This is the heading under which Mr. Vajpayee and others are named. But the heading under which Mr. Jagdambika Pal and others were put is, "Persons or leaders or *sadhus or* saints who participated in the movement." Let us not forget the sense of balance. Of course, he has clarified he was in the jail virtually. Where is the question of his participating? He was participating in a movement against the movement which you are doing, and he was imprisoned or restrained. But, even the heading of the Liberhan Commission is, at page 272 for Jagdambika Pal, I am sorry, not 958. Page 958 was for Mr. L.K. Advani and Mr. Atal Bihari Vajpayee. And the heading is, "Persons or leaders or *sadhus* or saints who participated in the movement."

Sir, another complete red-herring, Mr. Rajiv Gandhi, *shilanyas* and the locks. It is all very well. As I have said that there are series of red herrings in this whole debate. Just note these three short points. Will they appeal to your reason or not? The *shilanyas* was done in 1989, and it was done specifically on the non-disputed land. Was the *shilanyas* an invitation to come and break the mosque? Was the *shilanyas* an invitation for the people to come and do something to the structures standing there? We are now talking of the central theme of the Liberhan Commission Report. ....*(Interruptions)*.... I am just finishing. Please, don't interrupt me. ....*(Interruptions)*.... One minute.

श्री बलबीर पुंज: अगर वहां नहीं बनना था तो कहां बनना था?...**(व्यवधान)**... वहीं बनना था जहां ...**(व्यवधान)**...

DR. ABHISHEK MANU SINGHVI: Mr. Punj, you and your party will get the time. I am just finishing. ...*(Interruptions)*... The *shilanyas* was done on the non-disputed portion, not on the structure, in the structure, breaking the structure or demolishing the structure, the *masjid*. Number two, on 27th of October, 1989 a little known fact, Mr. V.N. Tarkunde, an eminent person petitioned the Supreme Court seeking a ban on *shilanyas*. The Supreme Court said, "No, we will not interfere." They dismissed Mr. Tarkunde's petition. Thirdly, last but not the least, the *shilanyas* was done after verifying that the site is not covered by any interim order of any court.

We are now talking, three years later, of people going on to an existing mosque and existing building and existing structure and demolishing it. That is as far from *Shila Nyas* as chalk is from cheese, as heaven is from earth. There is absolutely no issue of demolition in that action.

Sir, you were very kind and I will not abuse your licence and I now come to the end of my submissions. There are many more issues that one could talk about. There are many more Alleyways and bye-lanes. This House should come back to the central theme. And, frankly, Sir, we do not need the Liberhan report to condemn the principal Opposition, the principal protagonist which perpetrated this fraud on the nation. They stand condemned at the bar of public opinion 17 long years ago. On both substance and perception, and politics as much about perception, if not more about perception and less about substance, on both perception and substance they stand condemned. This is a party which has consistently sought to pull India back to the medieval ages. It talks the language of division, it talks the idiom of conflagration.

श्री रवि शंकर प्रसाद: शाहबानो क्या था? प्रोग्रेसिव था क्या शाहबानो केस में?

DR. ABHISHEK MANU SINGHVI: Just yesterday, Sir, my good friend remembers, that the President of this party likened this to the Quit India movement. Well, if he compares this movement to the Quit India movement, I can only pity this party's sense of history, I can only feel sorry for stalwarts like Mahatma Gandhi. ...*(Interruptions)*...

Ultimately, Sir, we cannot forget a sad and stark truth. The sad and stark truth is that the dead cannot cry for justice and, therefore, it is the duty of the living to do it for them. The Opposition here has tried to guillotine the idea of India and to rubble up the mosque. It is, of course, a great tribute to the resilience of India, to our unity, to our tensile strength that like many others, before you, you have also failed. Thank you very much, Sir.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI ARUN JAITLEY): Mr. Vice-Chairman, Sir, I was just listening to my good friend, Dr. Abhishek Singhvi, and he probably overstated his case, which he is good at. He says that we stand condemned at the bar of public opinion in the last seventeen years. In the five General Elections held in the last seventeen years, we were voted as a largest single party in Parliament at least three times. We have been the second largest party in the other two Elections.

I think, overstating one's case for the purpose of advancing a political argument is understandable. I was wondering how to make a realistic assessment of the Liberhan report. Should I understate? If I do understate and be more realistic as to what it is, as is apparent from the ATR, it is a report which is devoid of any credibility, it is a report which is an exercise in futility, it is a report which almost all the major media in this country has referred to as a dud report, a report which the ATR itself indicates that it is an unimplementable document! But, if I go into each of the 999 pages of this report along with its annexures, Sir, factually, I cannot help but saying that this report is a * on a factfinding process in the last seventeen years.

The first question which comes to light is: Why did it take seventeen years for a commission to come to a recommendation which is being referred to as a dud recommendation? Was this opportunity being used by the gentleman who headed the Commission only to perpetuate selfemployment? There are probably indications coming from a former Cabinet Secretary, who dealt with him, to the effect that this was true. I do not want to go much into the leakage of the document. But the manner of its leak is almost as dubious as the contents of this Report.

My friend, the Home Minister has categorically stated here that neither he nor any of his officers leaked the Report. In fact, he was so cautious, he said that the only copy they had was in the lock and key. That is why perhaps the ATR was very difficult to make because the report was in the lock and key. When the leak took place I mentioned there was one other copy available perhaps with the Commission itself. After I read the Report, I must correct myself. I think, it was not one but two copies available outside the Home Ministry. One was, perhaps, with the Chairman of the Commission, and the second as is apparent from the contents of its Report with the de-facto author of the Report. And when I say *de facto* author, the Law Minister, — Shri Veerappa Moily, is not here — I think if he takes a leaf out of this Report and one of his proposed law reforms to expedite pendancy of arrears in the Legal Justice system, it would be 'judgment out-sourcing' and this is what the Report seems to have done and the intrinsic evidence of who wrote the report is in the report itself and I will make it good. I said, Sir, that the ATR itself indicates that it is an unimplementable document except for saying 'agreed', 'noted' or 'agreed with some political observations of the judge', all that the ATR says, is The Communal Violence (Prevention, Control and Rehabilitation of Victims) Bill be legislated. A Bill on which the Central Legislature may perhaps have no legislative jurisdiction and then it further says that some matters will be referred to the UPSC and some matters will be referred to the Election Commission. Sir, I made a statement that the author appears to be somebody else. We are all familiar, at least some of my friends present here are as much familiar as we are or, perhaps, more with the language a judge writes. The first training of a judge is never to enter the political wicket. He looks at the evidence, he looks at the issue which he has to decide, and he links the evidence with the issue and comes to a conclusion. He does not go into political disputes. He

*Expunged as ordered by the Chair.

does not start commenting on ideologies as to which ideology is good and which is bad. If a judge does that, it becomes a Commission which is not fact finding but a Commission with an ideology, and in this case, just let us read what the Commission says in the last paragraph of its Report on page 999. I am not only referring to the various political statements he has made. My friends, in the Left, will be very pleased that the draft person of the Report took some inspiration from Karl Marx and said, 'Religion is the opium of the masses.' He starts his political document...

SHRI D. RAJA: Only one line he has said, not the full quotation.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, after the Commission went on for hundreds of sittings and for 17 years, the Judge and the advocate assisting the Judge — even in today's Hindustan Times — has leaked out documents with his name mentioned which he says that the IB Report is available with the Commission prior to 6th of December, 1992. So, the Judge and the earlier advocate, Mr. Gupta, probably had differences. And, the Commission goes on to pass strictures against Mr. Gupta saying that he betrayed his trust. So, after the evidence was recorded, the entire arguments have been heard. This Judge, whose familiarity with the Queen's language was somewhat inadequate, needed a draftsman. So, he gets another gentleman only for the purposes of helping him to draft the Report. Now, what does the Report need to be done? Somebody has to go through the evidence, somebody has to get the ideas what is the direction of your findings, he has to correct and put the language in place and then he has to find who is guilty and who is not guilty. So, he is saying in the last paragraph of the Report, "Lastly, I am thankful to Harpreet Sing Giani, who has whole-heartedly spent days and nights over the last one year..." — after the hearings were completed — "...in helping me..." — to do what — "...to analyse the evidence, coming to conclusions... editing the report... modifying language...adding to and modifying the ideas...to clear the mess created by predecessors." So, Mr. Giani did all these things. Mr. Giani analysed the evidence, he came to the conclusions, he gave the ideas, he modified the Report, he added to the language and the Judge did the reset!

Sir, as I said, if this is possible and the Government, in all seriousness, can say, "we accepts such a document", I think, judicial outsourcing may, perhaps, be one of the reforms that Shri Veerappa Moily should consider. He is attempting to bring down the arrears. Perhaps, that may speed up our trials and judgment writing. This is how this document was prepared.

The core question — Dr. Singhvi was right when he said it — was who demolished this structure and what is the evidence against those people? What is the evidence against those people? Was there a conspiracy or was it a spontaneous reaction of a small group? It was possible on evidence to come to any of the findings, but the finding had to be based on the evidence and the material which was laid before the Judge or the Commission. The Commission is to give a finding on evidence. The Commission is not to give a political opinion. The Commission is a truth investigator; a Commission is not a political pundit. I am afraid, this

Judge, besides having outsourced the writing of this Report, and either he or outsourced draftsman or the Home Ministry or anybody leaked it out, ignored the entire evidence which was placed before him and then come to a finding which was completely in consistent with what was stated in the Report.

Sir, since Dr. Singhvi says that this is the 'highway.' Let us deal with this 'highway.' I can go through each one of the pages which he has mentioned. For the benefit of some of the learned friends here, I mention the page. There were a large number of lawyers and parties appeared on behalf of certain Muslim organisations. The Judge records at page 15, "No evidence was led or information provided to the Commission with respect the conspiracy or pre-planning or the joint common enterprise by any of these counsels." So, the persons — representatives of the Muslim organisations — who are naturally aggrieved came up and said, "We have no evidence to prove any conspiracy." Then, he comes to others. At page 775 he says, "No documentary or direct evidence is possible in a conspiracy of this manner nor unimpeachable of firm evidence of some actions of planning of demolition is available." So, I have no evidence of any planning which is available.

On page 782, the Home Secretary, Mr. Godbole appears as a witness. Mr. Godbole stated that there was no information of planning and, as such, it could not be inferred that there was a conspiracy of the Congress and the BJP for demolition. This could not be accepted on the face of it, particularly, in the absence of any specific circumstances leading to such an inference. And, then, come the entire Intelligence agencies of this country and everybody else who had to give materials. So, at page 992, he says, "Neither the Police nor the investigative team of the Commission, that is, neither the CBI — CBI was the police in this case — nor the investigative team of the Commission, despite the prolonged process was able to identify any witness nor produce any witness, not a single witness, who could identify any of the demolishers or lead to any other evidence against suspects. Suspects were not even identified. Even after the unprecedented publicity throughout the long spell of inquiry, nobody came forward to advance the case or identify the persons who physically carried out the demolition or the ones who plotted the demolition." He then goes on to say at page 724, while indicting the RSS he says, "you planned it, but you kept the political leaders out of your knowledge." And, then, he says, "In totality, it becomes obvious that some leaders were consciously kept out of the operational area or planning in order to protect them and preserve their secular credentials for later political use." On the political leadership he says on page 994, "The Commission observes that important leaders of political parties — icons of movements, organisers of the movement— continuously issued statements from time to time in relation to the conspiracy of demolition, but no affidavit was filed before the Commission by any of them." Sir, the Police led no evidence who demolished or an evidence of who plotted. The Muslim organisations which are aggrieved have no evidence. No evidence is led by any political person, not a single man is identified and you wait, merrily, for 17 years and then come to a finding that, well, yes, it could not have

happened without the knowledge of X, Y and Z. Your ideology which started in 1925 is like this. The RSS stated in 1925. Your ideology is like this. Your ideology inherently promotes it. Therefore, you are the person who must be accused of this. I have no evidence, not a shred of evidence against you, but I have a political opinion against you; that is why, Sir, I ask myself this question. Was he a truth investigator or was he a political *pandit*? For some of these Commissions, heads are chosen. On important matters, you have inquiries whose precedents are cited for generations — The Vivian Bose Inquiry, The Justice Das Inquiry — these were all inquiries held in the 1950's where you picked up the most illustrious sitting Judge of the Supreme Court and they asked him to inquire. When Britain was shaken by the Profumo scandal, you asked Lord Denning to investigate and head a Commission? Here when the incident takes place, you go and choose a junior Judge of the Punjab High Court. How does your eyes fall on him, Sir? Sir, there is a popular saying or a belief with all our appointment processes of Judges at the Bar, when they say that there are two kinds of judges. There are those who know the law and there are those who know the Law Minister. ***...(Interruptions)...*** And, I am quite clear that this Judge fell in the second category, and, that is how a junior Judge of the Punjab High Court was chosen. ***...(Interruptions)...***

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Shrimati Viplove Thakur, please sit down. ***...(Interruptions)...*** Mr. Jaitley. ***...(Interruptions)...*** Shrimati Viplove Thakur, please sit down. ***...(Interruptions)...***

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश): यह क्या तरीका है ...**(व्यवधान)**...

श्री एम. वेंकैया नायडु (कर्णाटक): आपकी problem क्या है? ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती विप्लव ठाकुर: यह गलत बात है ...**(व्यवधान)**... इसे वापस लिया जाए...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please take your seat, Shrimati Viplove. ***...(Interruptions)...*** Please take your seat.

SHRIMATI VIPLOVE THAKUR: Why did he say that? ***...(Interruptions)...***

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): The hon. Leader of Opposition is an erudite leader, a legal expert and a legal luminary. My only request is***...(Interruptions)...*** I would only request that personal aspersions against a Judge should not be made.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I will respect your ruling. But a Commission of Inquiry headed by a retired Judge gives a Report. We are debating it. And it has large ramifications. If you give somebody the authority to make sweeping allegations against people, then, perhaps, all the facts would also have to be gone into. Having said this, Sir, a report must be a document which carries credibility. A report cannot be a document which becomes the subject matter of an endless controversy. A report cannot be a document which becomes un-implementable. A report cannot be a document which becomes a national embarrassment, as I will just show as to what this Report has done. Sir, the difficulty is that you pick up a puny Judge who uses 17 years

to perpetrate a selfemployment and then, the character of the Report almost appears to be an application for a future employment! If these are the kinds of reports these Commissions are going to give, I am afraid the credibility of the entire institution will go down. That is why, we read in newspapers, 'Judges and former Judges now commenting whether Judges should at all be heading such Commissions', which are to be used for entering the political thicket rather than only going into judicially determinable matters. So, what does this Report say? Let me start off. When I said the Report is probably an outsourced document — it is not like, as Dr. Singhvi says, there is one trivial error here or there; if a Judge has heard the evidence and the Judge is writing the Report, every fact he says will be connected to the document. Now, I think my friend, Shri Sitaram Yechury, here would appreciate this. I turn page after page. I was reading page 282. Who is the leader of the Ayodhya Movement against whom they tried to find an evidence but could not find? It was Prof. R.S. Sharma and Prof. D. N. Jha, two well-known Leftist historians, who appeared on the negotiating side of the Babri Masjid Action Committee. Who is the 'karsevak'? You are embarrassed only by the name of Mr. Jagadambika Pal. So, who is the 'karsevak'? It is Col. B.S. Zaidi of the Babri Masjid Action Committee. It is at page 271.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Can you just yield for a minute? I don't know if Mr. Sitaram Yechury has quickly turned to page 282! I think, you have made an error. I don't say that the Judges make no errors. Perhaps, like you have made an error, he has made errors too. The reference to Prof. R.S. Sharma and Prof. D. N. Jha is not in a section where you are trying to find out who is involved in the movement. It says, 'Leaders of movement have no particular role except participating in some negotiations.' They may have participated on this side or that side or on the neutral side. I think you are misreading it. It says leaders of Movement have no particular role. 'Movement' does not here mean the Ayodhya Movement. In this whole chapter, people mean who participated in negotiations. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: I am afraid the Home Minister has to bend backwards to come up with an, and not so convincingly, explanation. Page 270 says, "Persons or leaders or Sadhus and Saints who participated in the Movement." The word 'Movement' is continuously used throughout the Report as the Ayodhya Movement. He mentions here the DGP, Intelligence. See page 69, it is elementary. You ask a primary school child what is the date of birth of Mahatma Gandhi and what is the date of his assassination, he will give it to you correctly. He gives the date of Gandhi's assassination wrong. See page 562. After spending 17 years in doing a research on the RSS and BJP as to who was the founder of the RSS, he says it was Veer Savarkar and Dr. Hedgover only succeeded in. He erred on basic facts and it leads to my suspicion. These are not all facts which came in the course of a hearing. My colleague mentioned in the other House yesterday. Just turn to page 566, if you can defend this. He wanted to damn the BJP. So, he said that BJP's ideology is like the Muslim League's ideology of Jinnah. That is the argument he wanted to build up. So, to build up this argument up, he needed

a fact. At page 566, para 85.14, and this is important, he comes to a finding. He says, "Deen Dayal Upadhya by his conduct agreed with MA Jinnah's theory that Hindus and Muslims were two separate nations." Then, he allegedly quotes Deen Dayal Upadhya's saying and the quote is, "The problem of India is not intercaste, it is international. If peace is to reign here, the major communities must be given their own separate chunks of land. It is nothing but a mere dream to imagine that Hindus and Muslims can stay together in India as members of a composite nationality. The Muslims are not a minority community, they are a nation. They must have their own independent land and their own State." When we read this, we were all surprised how could Deen Dayal*ji* have said this? We started researching the source of this quote and we found out that he picked up the quotation of Mohammad Ali Jinnah put it in the mouth of Deen Dayal Upadhya and said that look the views of Deen Dayal Upadhya and Jinnah are the same. And you want to tell the whole country to treat this Report with any sense of seriousness. He picks up Jinnah's quotation, puts it into Deen Dayal*ji*'s mouth and said that look their views appear to be similar. Then he suddenly realises that it is not his quote. No judge who hears the case, who hears the evidence and then on the basis of that evidence gives findings on facts will ever come to a conclusion of this kind. At ten places he says that 'there is no evidence of conspiracy' and then says, "I think, this couldn't have happened without conspiracy." My friend Amar Singh*ji* just mentioned it. He has a huge bias, I will tell you, against the whole idea of a Ram Temple at Ayodhya. He has a huge bias against social justice and the Mandal Commission. I would like the Home Minister to read these two paragraphs at page 556. No Judge who writes on judicially determinable matters would give a political discourse of this kind. "Our leadership must step forth and with more equal responsibility and put a lid on the mischievous element in the society bent upon exploiting the factors referred to above, for their individual aggrandizement through repression, misguidance, acquiring power through mass means and improper reliance on philosophies such as Hindutva, Mandal, sons of soil, etc.

Now, suddenly, he says, "Mandal is a divisive philosophy. You must not rely on Mandal as a political leadership of this country." Now, Mandal recommendations are something which have almost been unanimously accepted by this country and implemented. The Judge has a bias on his past reservations and postings. So, he brings in this. How was this connected? *...(Interruptions)...*

SHRI KAPIL SIBAL: You brought down a Government on this. Now, you are saying, "unanimously".

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Advaniji was arrested in Bihar. Sorry, you are making a wrong statement.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Allow your Leader to speak. *...(Interruptions)...*

श्री विनय कटियार: सर, ...**(व्यवधान)**... इस पर क्या लिखा है ...**(व्यवधान)**... इससे सहमत हैं? ...**(व्यवधान)**... इसके संबंध में अगर सरकार सहमत हो, तो बताए ...**(व्यवधान)**... नहीं तो लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Your Leader is speaking*...(Interruptions)...* You are interrupting the LoP.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I will decline my friend, Mr. Kapil Sibal's, invitation to get into sidelanes. The issue is, the gentleman investigating the facts and circumstances leading to the events on 6th December, 1992, now has a whole theory on Mandal. It is not an isolated observation. Read recommendations on page 970. Read the two paragraphs together, that is, para 173.8 and para 173.9. In para 173.8, he says that the recruitment policy of the Government of India must change. Recruitment must be on merit alone. He does not want to lose over Mandal here. He has said it in the body of the Report. He says, "merit alone", and in next paragraph, he says, "The civil servants, who are posted at the helm of affairs, ought to be picked for the skills that they are required to exercise, rather than for completely unrelated academic skills or for casteist or regional basis." The ATR says, "This recommendation will be referred to the UPSC." — para 6.6. *...(Interruptions)...* Now, where is the gentleman? I do not know whether these are the ideas of Justice Liberhan or the *gyan* of one *gyani* because it is still not clear as to who wrote this report. But, you are investigating something...

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL (Gujarat): Sir, just one sentence.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, no, he is not yielding.

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL: Everybody knows that anti-reservation agitation in 1988 in Gujarat was headed by the BJP and they were against*...(Interruptions)...*

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, ...**(व्यवधान)**...

श्री विजय कुमार रूपाणी: सर, ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): बैठिए, बैठिए ...**(व्यवधान)**... Please take your seat.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I am only substantiating what are really the contents of this Report and I will come to the key contents which I have referred to in the context of conspiracy. Just read page 540. At page 540, he now refers to the political leadership of India. The discussion starts at 539. How is it concerned with the events of 6th December and events leading to that? I will just read the relevant sentences, and this is not on the BJP or RSS; this is on the entire political leadership of the country. I quote, "The loss of political neutrality and the convenience with which justification can be found for every action has rendered all objectives of peaceful civilized society as enunciated by intellectuals, leaders, philosophers, thinkers since ancient times, obliterated. 79.4. The law — common or constitutional, morals, ethics, epics and everything else is being examined in the scales of politically desirable results. It is immaterial whether those results are legitimate or healthy for democratic governance. Everyone is out to become a Politician rather than a Statesman." And, in the next sentence — he could not have

given an 8(b) notice to all of us — he says, "The politician has become the epitome of the proverbial rags-to-riches story. 79.5. The Common Indian has formed the firm belief already that the ills that face us can be traced to the political leadership and can be cured by a voluntary reform in the political parties in India...".

SHRI P. CHIDAMBARAM: "...voluntary reform in the political parties and their leadership itself." It is that you reform yourself also. This is what he is saying. He blames us. He blames the political leadership. I do not have to defend every line that he has written. He blames the political leadership. He gives expression to his view, and, he says, 'voluntary reforms by political parties and their leaders'. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: Therefore, the Home Minister... ...*(Interruptions)*...

SHRI P. CHIDAMBARAM: Tell me, Arun, what turns in it. ...*(Interruptions)*... The question is the question that you posed. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: Only one fact turns in it.

SHRI P. CHIDAMBARAM: The question is: who demolished the mosque? Please come to that. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: Only one fact turns in it and I am glad that you have answered that question, which I have been asking. I have repeated that sentence. Was he a truth investigator or a political *pandit*?

SHRI P. CHIDAMBARAM: We will answer that. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: Read these observations and you will get the answer. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. CHIDAMBARAM: We will answer that. ...*(Interruptions)*...

SHRI S.S. AHLUWALIA: You will answer with slogans only. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: And, it will be clear that he was dwelling on a political path not concerned about other things because when it comes to the question of who demolished it, he says that he cannot identify a single person. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. CHIDAMBARAM: You tell us, who demolished it. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: After seventeen years of wasting public time and money, the situation is that you are still... ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: We are debating the Commission of Inquiry Report. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, these are not trivial errors. My friend, Dr. Singhvi said, "Oh, he has made some trivial errors. You made trivial errors. But the whole Report is a compilation of howlers, the whole Report is a tragedy of errors, rather than a comedy of errors, and, there are hundreds of these kinds. What does he say about Gulzari Lal Nanda? The last I heard of Gulzari Lal Nanda was that after being the Prime Minister of this country for a short duration, he lived in a *barsati* in Defence Colony, and, he was dispossessed, and his luggage was on the road before he passed away.

About Gulzari Lal Nanda, he says on page 336, Rajendra Singh, the RSS leader, Dau Dayal Khanna, and, Gulzari Lal Nanda, die-hard Hindus — was there any evidence against Gulzari Lal Nanda — in connivance with people with similar thoughts, started conceiving and exploiting a local dispute at the national level, maybe for their selfish political needs, — what was Gulzari Lal Nanda's political need in 1992 — or, for achieving the old theory of Hindu *rashtra*. He was your Prime Minister, your Party's Prime Minister. When did he become a supporter of Hindu *rashtra*? If you are given to head a Commission of Inquiry, how can you pass any comment about anyone without having gone through a procedure? Mr. Amar Singh was very agitated that something has been said about Deoraha Baba, and, Dr. Singhvi said, "Oh, it is a mistake in that list of 68 people, where he uses the word 'culpable'." I am afraid that is only half-truth. Let me read the full sentence which he has written about Deoraha Baba at page 427. "Open threats by exhorting the dacoits to take on arms for the Ram temple were made by Ashok Singhal, Deoraha Baba, and, Harishbhai". ...*(Interruptions)*... Deoraha Baba asked the dacoits to pick up the arms and come in support of Ram temple. Mr. Home Minister, please show us the evidence which led to this conclusion.

SHRI AMAR SINGH: This is very disgusting, very disgusting. *(Interruptions)*

श्री विनय कटियार: इंदिरा गांधी जी वहाँ उनके पास क्या करने जाती थीं...**(व्यवधान)**...

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान): राजीव गांधी जी क्या करने गए थे? ...**(व्यवधान)**...

श्री विनय कटियार: राजीव गांधी जी क्या करने गये थे? ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please sit down. ...*(Interruptions)*... Please sit down. Do not interrupt your leader. ...*(Interruptions)*... No, no. ...*(Interruptions)*... Why are you interrupting? ...*(Interruptions)*...

SHRI AMAR SINGH: Sir, on the issue of Deoraha Baba, I am with the Leader of the Opposition. ...*(Interruptions)*...

श्री विनय कटियार: क्या बलराम जाखड़ जी वहाँ...**(व्यवधान)**...

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Pany, Mishra *ji*, please take your seats. Why are you interrupting your leader?

श्री विनय कटियार: *

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): This will not go on record. ...*(Interruptions)*

श्री कलराज मिश्र: *

श्री रामदास अग्रवाल: *

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Why are you interrupting your leader? आप सब लोग बैठिए। ...**(व्यवधान)**... आपके नेता बोल रहे हैं ...**(व्यवधान)**... आप लोग बैठिए।...**(व्यवधान)**...

श्री विनय कटियार: *

*Expunged as ordered by the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): That will not go on record. Please don't do that. ...*(Interruptions)*... Mr. Katiyar, sit down. ...*(Interruptions)*...

श्री अरुण जेटली: सर, रिपोर्ट के अंदर जब सब तरफ से यह आ गया कि किसी षडयंत्र की गवाही नहीं है, किसी ने कोई तथ्य नहीं दिए षडयंत्र के संबंध में, तो फिर यह कमीशन आडवाणी जी को और उनके अन्य साथियों को कैसे indict करता है। किसी ने यह नहीं कहा। अब किस प्रकार का तर्क कमीशन ने ढूंढा, and the relevant page is 255. मैं एक लेडी IPS Officer का नाम डा0 सिंघवी से सुन रहा था, वह उस दिन के लिए श्री आडवाणी जी की PSO थी। उसने दो बयान दिए हैं, एक लिब्रहान आयोग के सामने और एक सी0बी0आई0 को रायबरेली की अदालत में। आडवाणी जी मंच से खड़े होकर अपील कर रहे हैं और आडवाणी जी के साथ-साथ नाम लिखते हैं पेज 255 पर — श्री एल0के0 आडवाणी, डा0 मुरली मनोहर जोशी, श्री अशोक सिंघल, विजय राजे सिंधिया, श्री एच0वी0 शेषाद्रि। ये सब लोग अपील कर रहे हैं, जो 50, 60, 70 लोग डोम के ऊपर चढ़ गए थे कि आप नीचे उतर आइए, मत चढ़िए। बार-बार अपील कर रहे हैं, लेकिन वे लोग नीचे नहीं उतरे। आडवाणी जी ने इस PSO महिला को यह कहा कि मैं स्वयं वहां पर जाता हूं। वह स्वयं वहां पर गई, वापिस आई और कहा कि वहां पर तनाव है, आपको जाने की अनुमति नहीं है। यह evidence में है। फिर आडवाणी जी ने कहा कि मैं उमा भारती को भेजता हूं कि वहां जाकर उन लोगों को नीचे उतारिए। अब ये षडयंत्र में कैसे शामिल हो सकते हैं — शेषाद्रि जी संघ के सबसे प्रमुख लोगों में से थे, आडवाणी जी भाजपा के अध्यक्ष थे, अशोक सिंघल जी VHP के प्रमुख व्यक्ति थे। Now, what is the logic he contrives to disbelieve this? And, the logic is, आपने जो अपील की, यह कहा कि डोम से नीचे उतर जाइए, यह नहीं कहा कि गर्भ गृह के अंदर नहीं जाइए। इसलिए यह बहुत खोखली अपील थी। It was a feeble appeal and, therefore, your real intention was that it be demolished. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. CHIDAMBARAM: It is not plausible. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: Well, it is plausible, if Deoraha Baba escorted dacoits two years after he died. ...*(Interruptions)*... if any of these things is plausible ...*(Interruptions)*... why is it plausible ....*(Interruptions)*....

SHRI P. CHIDAMBARAM: Don't mix up things. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Why are you impatient? ...*(Interruptions)*...

SHRI P. CHIDAMBARAM: I am not getting impatient. ...*(Interruptions)*... I was very patient yesterday. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You are only impeding the smooth flow of your own leader. Why are you doing that? ...*(Interruptions)*...

श्री अरुण जेटली: उपसभाध्यक्ष जी, अब इस तरह का तर्क ले लेना कि आपने कहा कि डोम से उतरिए, आपने कहा कि मैं स्वयं जाऊंगा, आपने उमा भारती को वहां भेजा, लेकिन आपकी नीयत अच्छी नहीं थी, क्योंकि आपने यह शब्द प्रयोग नहीं किया कि गर्भ गृह के अंदर मत जाइए, therefore, everything is disbelieved. इस तरह के तर्क पर पहुंचने के लिए किस तरह की मानसिकता चाहिए, वह मानसिकता मेरे अगले तर्क से स्पष्ट होती है। अब विवाद आता है कि यहां पर 1528 से पहले क्या ढांचा था? इसके संबंध में पेज 23 पर वे कहते हैं कि अयोध्या के बारे में धारणा है कि यह भगवान राम का जन्म स्थान है। पेज 63 पर कहते हैं कि 1934 से यहां नमाज़ नहीं पढ़ी गई। 1885 में एक ब्रिटिश जज का अपील में जो जजमेंट था, उसका भी ज़िक्र है, जिसका वाक्य है, "It is most unfortunate that a *masjid* should have been built on a land sacredly held by the Hindus, and as it occurred 356 years ago, it is too late to remedy the grievance".

ये सब नोट करते हैं, उसके बाद वे कहते हैं, पेज 561 पर, "The History books produced before the Commission as well as the White Paper of the Government of India and the BJP and the various contentions of various counsels are unanimous". सर्वसम्मति है इस बात पर कि "In 1528, Emperor Babar ordered Mir Baqi, his commander, to erect a mosque at Ayodhya". ये सारे तथ्य, चिदम्बरम साहब ने उस सदन में ठीक कहा कि ये तो Title Suit है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है और क्योंकि Title Suit इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, लिबरहान साहब को यह finding नहीं देनी चाहिए थी। वे पूरे के पूरे तथ्य लिखते हैं और लिखने के बाद कहते हैं कि सर्वसम्मति थी कि 1528 में जहां जन्म स्थान था, वहां पर एक मस्जिद बनी। उसके बाद उनकी सोच और ज़हनियत क्या थी, यह पेज 547 से स्पष्ट हुआ — "The demand for the construction of the temple deprived the Hindu religion of its secular, multi-religious and multicultural credentials of the well reputed philosophy and the thoughts generally prevalent."

इन सब तथ्यों के बाद भी अगर आप कहोगे कि जन्मस्थान पर मंदिर बनेगा, तो यह मांग सेक्यूलर नहीं है, अगर आप कहोगे कि किसी ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया और वह कब्जा करने के बाद चलता रहे, वह सेक्यूलर है।

उपसभाध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहता हूं कि कमीशन को तथ्य ढूंढने थे कि किसने तोड़ा, षड्यंत्र था या नहीं था, उसकी स्पष्टता में जाने के बजाय जब कमीशन एक विचारधारा के साथ अपने आपको जोड़ लेता है, when a Commission acquires an ideology, and in this case the ideology was a demand for a temple at the *Ram janmasthan*, which he himself says, "..was altered to a mosque in 1528 itself robbed the Hindu society of its secular character," इसलिए मंदिर की बात करना anti-secular है और जो बना हुआ है, वह बना रहे, वह सेक्यूलर है — यही सोच थी। अब यह विषय आया कि अटल जी का नाम क्यों लिया? अटल जी का नाम लेने से पूर्व, मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि Section 8B of the Commission of Enquiry Act में स्पष्ट लिखा है और उसके दो भाग हैं — पहला भाग यह है कि किसी व्यक्ति के आचरण के बारे में जांच होगी, 'if the conduct of a person is to be inquired into' और दूसरा है 'if his reputation is likely to be affected.' दोनों में से अगर किसी चीज पर असर पड़ेगा तो उसको आपको नोटिस देना पड़ेगा। अटल जी को तो कोई नोटिस नहीं दिया। जिन 68 लोगों की सूची बनाई, और वह कोई casual सूची नहीं है, वह कहते हैं कि, 'persons culpable for creating communal disorder,' आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि सांप्रदायिक सद्भावना को इस देश में आपने खराब किया, इससे उनकी प्रतिष्ठा पर असर नहीं पड़ता, reputation पर असर नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि मैं एक रिटायर्ड जज हूं, मुझे नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है, मुझे कानून का उल्लंघन करने का अधिकार है और फिर उस सूची में अटल जी का नाम डाल दिया गया।

In the entire process, I am afraid whoever wrote this report misjudged and miscalculated his own credibility and Vajpayeeji's credibility. By going after Vajpayeeji, he went for an overkill and then shot his own credibility and shot himself in the foot.

Now, everybody in the Government has to come out with various statements that he is sorry that this has happened, it should not have happened. Dr. Singhvi just now said that it could be segregated if this was an illegality from the rest of the report. But what was the thought process of this gentleman when he was going in for this kind of an inquiry? The only person, Sir, this Commission had been kind to was to its own appointing authority — Shri P.V. Narasimha Rao.

And to be kind to him, he had to ignore two vital facts. It is never our case that Article 356 should have been imposed. Some others say that. And some people argued before the Commission that Article 356 should have been imposed in Uttar Pradesh अब कमीशन का पूरा तर्क यह है कि जब राज्यपाल ने रिपोर्ट नहीं दी, तो 356 कैसे लग सकता था और राज्यपाल की रिपोर्ट अनिवार्य है। Now these are the two facts. The Commission never summoned Mr. Reddy, the then Governor. No 8-B notice was issued to him. And he simply says, 'no report came.' Amar Singhji read it out in the earlier part of the day. I am reading it out. The truth is that the Government had sent a report. The report may have been wishy-washy, but the report categorically had a sentence — 'the possibility of damage to the disputed structure itself may not be ruled out.' Should this report not have been before the Justice Liberhan? Or did he decide to conceal the factum of this report? This book had been published by Mr. Narasimha Rao. He wrote the book and said that this should be published after his death. Its title is: Ayodhya 6 December 1992.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: What was its final conclusion?

SHRI ARUN JAITLEY: The conclusion was: 'It is a delicate situation; I leave it to the Central Government.'

SHRI KAPIL SIBAL: No.

SHRI ARUN JAITLEY: Don't forget, Mr. Sibal, you know Article 356 as well as I do. The Governor of Tamil Nadu, Mr. Barnala, refused to give a report for dismissal of the State Government when the Centre asked him. Why? Because Article 356 says, '..on receipt of a report of the Governor or otherwise...' And, therefore, Karunanidhi's Government was dismissed even without ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: You are reading one sentence. Please read the final conclusion. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, this is the most unprecedented Commission I have ever come across. It is a fact in public domain that the Judge heading it, a retired Chief Justice of a High Court, was not considered appropriate by the collegium of Supreme Court for elevation. So, what does he do? The Supreme Court did not consider it appropriate to recommend his elevation. This is the first Commission in India's history which decided to pass strictures against the Supreme Court. This was his last opportunity to get back at the Supreme Court. So, he says at page 535, "The intransient stance of the High Court of Uttar Pradesh, the obdurate attitude of the Governor, the inexpiable irresponsibility of the Supreme Court's observer and the short-sightedness of the Supreme Court are itself fascinating and complex stories, the depth of which I must not plumb." ...*(Interruptions)*... किसी को Section 8(b) का नोटिस नहीं, किसी की सुनवाई नहीं। Supreme Court itself is short-sighted; Governor is obdurate; हाई कोर्ट को कोई कानून की समझ नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट का जो observer गया, वह गैर-जिम्मेदाराना था। मुझे किसी को नोटिस नहीं

देना, मेरे हाथ में कलम है, मैं जिसको चाहूं और जिसके खिलाफ चाहूं, उसके खिलाफ आरोप लगा दूं। What is the action taken on this part of the Report? ...*(Interruptions)*... Sir, please answer just one question. The Commission had the CBI and the intelligence agencies. The whole national media was there when the incident of 6th December took place. Everybody knew who was present and who was not present. Now, on page 743, he gives a list of people who were present. And that is why, I say, Sir, the real draughtsperson of the Report needs to be found out. He must stand up and own that he wrote the Report. I could understand a casual error into a by-lane, as Abhishek says. The Report says, prominent among those present that day were Balasaheb Thakre who was admittedly in Bombay. And Balasaheb Thakre is a person whose identity can't be so easily mistaken. Then he says, Kalyan Singh, Rajender Gupta, Uma Nath Singh, Lalji Tadon and Brahm Dutt Dwivedi. They were all Ministers or the Chief Minister of Uttar Pradesh. They were all in Lucknow. Then he says, Kushabhau Thakre, Sundar Singh Bhandari, Sikander Bakht who were in Delhi. In fact, after the incident, three of them addressed a Press Conference in Delhi on 6th December. It also lists the name of Prabhat Kumar, the Home Secretary, who was certainly not there. So, anybody can give you a report like that. What the Congress is seriously doubting is that Jagdamba Pal is not a Kar Sevak. You must actually seriously enquire if he is not, how did his name come in. Abhishek said, "It's a mistake." Well, all the mistakes can be qua you. The mistakes can't be qua us. If this Report is a compilation of howlers and a tragedy of errors, then, to come up and say that this is the Report which he signed as his gospel which has now indicted you.

Sir, how did the Commission and the Government create evidence? I think, this itself is a fascinating story. The Commission has a list of witnesses. There were three kinds of witnesses — Commission's witnesses, Central Government's witnesses and defence witnesses. Now, all these witnesses were examined. But, the truth has a very inconvenient habit. At times, it can slip out. So, one of the witnesses who admittedly has given a strong testimony against the BJP leaders is a journalist called Raman Kirpal. He is listed as the Central Government's witness. He said some leaders made provocative speeches. I picked up the 4th December issue, the latest issue, of a new magazine called "Open". This journalist has written a two-page article called "My Crippled Testimony". He writes, "The CBI officers gave me a date for deposition in Delhi. I reached there right in time. They showed me an affidavit and asked me to sign it". So, the CBI would bring prepared affidavits and get them signed by the witnesses. He says, "I didn't disagree with the contents of the affidavit. I said, 'I have to say something more'. They told me, 'You come before the Commission when you are summoned; you say the rest orally". He says, "I wanted to say something more". What was that "something more"? He says, "When I went to appear before the Commission, they asked me a question if Lal Krishna Advani gave any speech from the dais inciting the *karsevaks".* I said, "No, Sir". But I wanted to say somebody else's name, to which they said, "You shut up". These are the words he uses, "answer only in 'yes' or

'no'." Answer only in 'yes' or 'no'. He says, "I only answered a few questions in 'yes' or 'no' and I came back. I find my testimony has been heavily relied upon by the Commission". After giving the testimony, he says what the testimony that they did not allow him to speak was. He says, "What surprises me is that the Commission rescues the Central Government. Its conclusion says that the Central Government was crippled by its failure of intelligence agencies to provide an analysis of the situation. I wanted to give my evidence that the Central Government was lapse. I was not allowed to give it". So, he concludes his article by saying, "This is my truth as a reporter. My affidavit as Central Government witness No.24 still stands. But in it is a crippled truth. There was much more that I could have said and wanted to say". This is how your Commission has functioned. This is not somebody who has any friendly overtones to my party. He is someone who has severely gone against and given evidence against some of our leaders. It is not against Mr. Advani. He says, "The moment I wanted to say something about the Central Government and something else, they said ' just shut up; the answer is only 'yes' or 'no'." This is what has happened in the last seventeen years and you want the entire country to believe this kind of a procured evidence!

Sir, what is it that the Commission in its recommendations has been saying? I just give you the pages. He uses a word for my leaders, say, "little men". The truth is that when you appoint a little man to conduct such a monumental inquiry, he, probably, thinks that he is now to run the entire Government and the burden of suggesting an alternative system falls on him. Look at page 996. Mr. Home Minister, if you can, in your reply, explain to us the meaning of this and how it is implementable, please let us know. The next logical conclusion must be that the Government which is formed on the premise of religion or has religion on agenda must be barred. I have heard of organisations being banned. But he wants Governments to be banned. He wants a new constitutional order where some authority will be created and the elected Governments and the Indian democracy can be barred. It is stated on page 996 that a Government elected on the basis of religion and their plans must be banned.

SHRI P. CHIDAMBARAM: It is not on page 996. I know that sentence is there. But it is not on page 996.

SHRI ARUN JAITLEY: The sentence is there. I will correct the page. It is fair on the part of the Home Minister to say that. Now, please explain to us how Governments can be banned. Then, he says that there must be a body to look into it. ...*(Interruptions)*... That is exactly my argument. The Commission suggests to review the whole Constitution. It makes a recommendation to review the whole Constitution. Its third recommendation is to review the recruitment policy of bureaucracy and no postings on caste. His next recommendation is — and this, I think, will go down as a tribute, in a sense of humour, to the Judge who held the inquiry, a gentleman who got 48 extensions for himself and has the audacity to say it on page 971 — that no retired person should ever be given a job. Forty eight extensions के बाद वह कहता है कि किसी भी सेवानिवृत्त व्यक्ति को extension नहीं देनी चाहिए।

SHRI KAPIL SIBAL: When he was given the job, he was a sitting Judge. He had not retired then. He is excluding others, not himself.

SHRI ARUN JAITLEY: But when he wrote this,...*(Interruptions)*...

PROF. RAM GOPAL YADAV (Uttar Pradesh): This is the only good recommendation.

SHRI ARUN JAITLEY: Then, he goes on to say that no State Government must be allowed to discriminate against people who are not born within the State. Now, how does that concern with 6th of December? It is, no doubt, a good recommendation. Next comes a fascinating recommendation at Page 976. He says, "Party affiliations must come to an end as soon Members of Legislatures and Parliament are elected." So, he wants the Tenth Schedule to be scrapped and defections to start all over again. How does this come under the scope of this Commission looking into the Ayodhya issue? The then Law Minister is no longer in active politics; he holds a Constitutional post. But he must, certainly, be complimented for the discovery, from where he got a gentleman with these kinds of ideas. Then, my friends, in the media gallery, got shouted at, the day the Report was leaked. He, obviously, did not like that. He says that they all do yellow journalism, and he calls them mischievous journalists. Then, he makes two very important recommendations about the media. He says that there must be a permanent Commission, which must keep entertaining complaints against the media. His next recommendation which, I am sure, the Home Minister will reject because he was privy to the post-1991 liberalisation process which delicensed everything. He says, "Journalism is one profession which must be subjected to licensing, and nobody should be allowed to become a journalist till he obtains a licence." This Report is a national joke, and you want to go by some findings that he has made. He says, "Though there is no evidence of conspiracy, I have come to the conclusion that there was some conspiracy." Sir, there is a very important recommendation that he makes. If you turn to Page 979, he says, "It is, therefore, my recommendation that a statutory National Commission be composed of acknowledged experts to delve into the question of provenance of historical monuments, artefacts, etc., and their determination should be deemed to be definitive and final." It is to say that if ever there is a monument, or, a place of worship, if there is a dispute, judges or commissions should not examine that. We must have archaeologists and historians who must decide, and their findings must be final. So, the first part of the recommendation, obviously, is that the Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991, should be repealed. The meaning of the word 'provenance' is very clear. It means the original ownership of the structure. The Oxford dictionary of difficult words defines provenance as a place of origin or the earliest known history of something. Now, there must be 30,000 places of worship where there may be a dispute about the original ownership. He says, "Constitute a permanent Commission." And, since your Report was in the lock and key, and the ATR was being finalised, in Para 6.6, you say, "Well; we already have an ASI; that is, the Archaeological Survey of India. So, we don't need a commission." But, curiously, Sir, and I come to the last limb of my argument. I will just take five minutes more. Going by Liberhan's recommendation

and your ATR, in this case, the High Court had directed the ASI, "Please go and find out what the original character is." The ASI gave a Report in 2003. I am not reading the entire Report. I will just read out the relevant five or seven sentences of it. It says, "Now viewing in totality and taking into account the archaeological evidence of a massive structure just below the disputed structure and evidence of continuity in structural phases from the Tenth century onwards up to the construction of the disputed structure along with the yield of stone and decorated bricks as well as mutilated sculpture of divine couple and carved architectural members including foliage patterns, amalaka, kapotapali doorjamb with semicircular pilaster, broken octagonal shaft of black schist pillar, lotus moif, circular shrine having pranala (water chute) in the north fifty pillar bases in association with the huge structure, are indicative of remains which are distinctive features found associated with the temples of North India." So, the Archaeological Survey of India went there in 2003. ...*(Interruptions)*... After the demolition. ...*(Interruptions)*... 2003 was after the demolition. Under the orders of the Allahabad High Court, the ASI dug up, found the structure underneath and this is what the ASI says. Justice Liberhan says, "Have a Commission." You say, 'no, let the ASI do it'. The ASI has already done it in this case. What remains? The argument is, ...*(Interruptions)*...

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.]

SHRI KAPIL SIBAL: Take it forward. Say, 'you will demolish it'. ...*(Interruptions)*...

SHRI ARUN JAITLEY: I will take it forward. Have patience. ...*(Interruptions)*... This Report, Sir, is earlier preceded by a ground penetrating radar survey, a GPRS, which came to the same conclusion. So, now you have experts who have come to this finding. Sir, Mr. Sibal says, how do you take it further from this? The Commission has now come to a complete finding. Well, in 1528 this happened. Prior to 1528, the character was, perhaps, of a temple. He does not give a definitive finding. But, he says, 'Mir. Baqi constructed the mosque'. The last 500- odd years have seen various struggles. Abhishek said in 1767 something happened. In fact, one of the earliest evidences, prior to 1528 is, when Shri Guru Nanakdev, before establishing the Sikh religion, went around the large part of the world, in this region, at least, between 1508 and 1510, he goes to Ayodhya. He then tells his disciple, Mardana, who records it, there are contemporaneous recordings which, I am sure, some Members will refer to, of that, and prior to 1528, where he says "राम जन्म स्थान ते जाके मत्था टेकना" which is the meaning of that. And, nobody can ever say Sikh history is epic. Sikh history is real history. Then, you have voluminous evidence of international travellers, French travellers, which are all available. I have all the copies here, Sir. The official gazetteer of ours, French traveller, William Foster's book, 'On the Early Travels of India', each one says *janamsthan* converted to a mosque in 1528.

Sir, the question, therefore, is, and I come to my last point, how do we resolve this issue? Obviously tension cannot resolve it. We have had 500 years of struggle. You had 1885 as the first

judgement. You had almost 130 years of litigation. And, obviously, there is a very large majority in this country which feels that the place of birth of the most revered is sacred. It is no ordinary place; it is no ordinary temple. They also feel that whoever established a mosque over a temple, it was not an act of religiosity, it was an assertion of political power. And, therefore, if the litigation process cannot decide in over 100 years, if there are struggles and tensions, any civilised society must obviously avoid it. Therefore, we feel the best process would have been negotiations. But that hurdle to the negotiations is not the parties which are willing to negotiate, but it is the parties which have now developed an interest in allowing the dispute to perpetuate.

Sir, secular polity is not anti-religion. It is not irreligion. Civilised secular polity certainly requires the protection of every minority. But the basis of secularism also cannot be a reverse discrimination against the majority sentiment. And, if for 500 years they lived with this sentiment and struggles go on, how do you resolve it in a society? And, therefore, the resolution will have to come through a process of negotiation. You said, Mr. Chidambaram yesterday, 'well, this is a struggle between inclusiveness and divisiveness'. And, inclusiveness has one. Well, I think, you framed the wrong question. Any inclusiveness must necessarily include the aspirations of a minority, but it cannot be based on a reverse discrimination against the majority. It must be an inclusiveness for all. Therefore, please revise your question. And, the real answer must be justice for all, and that is what we stand for. And, in that justice for all, we do not believe in discriminating, but, at the same time, we speak out against reverse discrimination. That is why we reject this report in toto. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Sitaram Yechury. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. CHIDAMBARAM: Take the argument further. Say that you have demolished the mosque. ...*(Interruptions)*...

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, उनको बाद में बोलने का मौका मिलेगा। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Shri Sitaram Yechury. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. CHIDAMBARAM: He must say that no legislation was possible, no negotiation was possible, therefore, we have demolished the mosque. ...*(Interruptions)*...

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, मंत्री जी को बोलने का मौका मिलेगा। ...**(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have called Mr. Sitaram Yechury.

श्री कलराज मिश्र: महोदय, माननीय मंत्री जी को...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: कलराज जी, आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सीताराम येचुरी: सर, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: मैं संरक्षण दे रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री सीताराम येचुरी: सर, मैं दोनों पक्षों के बीच में हूं। सर, जो असली मुद्दा है, उसको छोड़कर और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जब इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, तो मेरा ध्यान, मेरे मैन पाइंट्स बोलने से पहले, मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ था। ...**(व्यवधान)**... डिप्टी चेयरमैन सर, आपकी भी इसके बारे में जरूर दिलचस्पी

होगी। सर, हमें फिराक गोरखपुरी याद आ रहे हैं। मुझे फिराक साहब की बात इसलिए याद आ रही है, क्योंकि वह पैदा हिन्दू सवर्ण जाति में हुए थे और उनका असली नाम रघुपति सहाय था। वह अंग्रेजी पढ़ाते थे। वह हरिवंश राय बच्चन जी के साथ प्रोफेसर थे, लेकिन वह उर्दू की शेर- शायरी करते हुए मशहूर हुए। फिराक साहब के कई सारे मशहूर शेर हैं, लेकिन उनके चुटकले भी बड़े फैमस हुआ करते थे। एक दिन उनके पड़ौसी आकर उनसे कहने लगे कि फिराक भाई कल मुझे घर को खोदना पड़ा और मैं इतनी गहराई पर पहुंचा, तो मैंने देखा कि मुझे तार मिल गया और तार मिल गया तो इसका मतलब है कि प्राचीन हिन्दुस्तान की सभ्यता में इतना विकास हो चुका था कि उस जमाने में लोगों के पास टेलीफोन और टेलीग्राम था। फिराक साहब सुनते रहे और उन्होंने कहा कि भाई यह अजीब बात है कि मुझे भी मेरे घर में खोदना पड़ा और आप जितनी गहराई पर गए, मैं उससे भी नीचे गया, लेकिन हमें तो कोई तार नहीं मिला। इसका मतलब है कि प्राचीन हिन्दुस्तान की सभ्यता इतनी विकास कर चुकी थी कि उस जमाने में उनके पास वायरलेस था या मोबाइल टेलीफोन था और तार की भी जरूरत नहीं थी। अब सवाल यह है कि यह खुदाई कर-कर के कहां तक आप पहुचोगे? मैं आपके बाकी सवालों पर आऊंगा। इस रिपोर्ट पर आने से पहले। ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: पाताल की सच्चाई तक।

श्री सीताराम येचुरी: आप पाताल की सच्चाई खोजते रहिए। हमारे देश के नौजवानों जो दो-तिहाई आबादी है, उनके भविष्य के साथ क्या जुड़ा हुआ है। सर, देश को भूत के अंधेरे में नहीं, लेकिन भविष्य के उजाले में ले जाना चाहिए। Let us come down actually to this basic point that we are discussing today that what is this Commission all about. The whole issue is, that the Commission was about the destruction of the Babri Masjid. How the destruction of the Babri Masjid happened, what were the circumstances that have led to that. On that issue, Sir, whatever be the other bye-lanes and narrow lanes and Alleys they have gone through, the basic conclusion that the report comes to is this. I am reading out from page 917, para 158.10, "The claim made by leaders of the movements of the icons from political or social organisations does not carry conviction to conclude that the demolition was carried out by Kar Sevaks spontaneously out of sheer anger or emotions. The mode of assault, the number of Kar Sevaks who carried out the demolition and the constraints of the space to accommodate the number of people, veiling of the identity of the Kar Sevaks entering the domes, the removal of idols and the cash box from under the dome and subsequent reinstallation in the make shift temple, construction of the make shift temple, availability of instruments and materials for demolition and for the swift construction of the make shift temple categorically leads to the conclusion and finding that the demolition was carried out with great painstaking, preparation and pre-planning." This is the conclusion that the Commission has come to. It has come to the conclusion on the basis of certain evidence.

We have heard a large number of issues that the hon. Leader of the Opposition had raised which, I think, are completely extraneous to this central issue of determining how this Mosque was demolished. I am speaking by standing between legal luminaries. When judges give their judgment or their statements, there is a lot more that is in the non-operative part where much of their opinions are being given, which I don't think it should be. The seriousness should not be

attached to many of these issues. The central issue was how this mosque was demolished, how this act was conduction and who is responsible for this. That is why, Sir, after this 17 long years, it has come. Much has been said about the delay. Yes, Sir, everybody here is responsible for giving extensions to the Commission — 14 by them and 32 by the others, and there were, in fact, two years of the United Front Government also in between, which continued to give extensions. There, it is not a question of apportioning blame but I wish this had come earlier, earlier for the interest of our country and for the interest of our future. But, there are two contradictory points with which I want to begin. One is that this Report legally confirms what the country had already internalised during these last 17 years that the demolition was not an act of spontaneity but it was a pre-planned action executed to perfection. Now, I still remember, it is there in records, the then, Chief Minister, Shri Jyoti Basu, deposing before the Commission had given a CD and evidence of the then Chief Minister of UP, Mr. Kalyan Singh, who had gone to Kolkatta to give a speech and where he boasted and claimed that if he had given this job to contractors it would have taken some days, but his Kar Sevaks have done this job in five hours. This is on record. Therefore, Sir, all this has been internalised. We all knew this, but it took so long to come, and the fact that it took so long to come, all of us know. There is a famous saying, "Justice delayed is justice denied." But, at least, now, we want that justice needs to be done and this is important for reestablishing the credibility of the people in our systems. We have had many such Commissions in the past, and in many such Commissions in the past what has been done, what has been recommended has never been implemented. You can see even on this issue the charge-sheet issued by the Additional Sessions Judge of Ayodhya episode, the designated court of Lucknow, who way back on the 9th September, 1997 frames this charge-sheet against all the people that the Liberhan Commission has actually listed and all the points which the Liberhan Commission has repeated are contained in this charge-sheet. This was ready before the country in 1997. Every single person named there has been named in this as well. But, all of us know after 1997 when the judicial process began the changes of Government that have come in, various other factors led to this delay. So, the issue is not about 'delay' or 'no delay' but, what in substance, are we going to do about it. Why I am saying this, Sir, is the credibility of this system is falling by the day. You had the Srikrishna Commission recommendations. Nothing has happened about it. You had nine Commissions of Inquiry on anti-Sikh riots in Delhi. Nothing has happened about it. If you want to know the Reports submitted since Independence, I would say that you had Justice Jagan Mohan Reddy Commission which enquired into the Ahemadabad riots way back in 1969, you had Justice D.P. Madan Commission on the Bhiwandi riots in 1970, you had Justice Vithaya Commission, you had Justice Jitendra Narain Commission on Jamshedpur riots, you had Justice Venugopal Commission on the Kanyakumari riots. But, none of the recommendations of these Commissions are implemented. The moot question and what we want to know from the

Government is this. The Government has submitted the ATR which don't enthuse any confidence that this process will be reversed and the countrymen and my country will be assured that justice in our system may be delayed, but cannot be denied. So, we want justice to be done. And, if justice is to be done, this ATR is completely unsatisfactory. As far as this ATR is concerned, I am completely dissatisfied. We are all very dissatisfied, because it does not say how justice will be provided. In 1.7 and 1.9 of the ATR, it talks of pending cases on these issues and they are pending in separate courts in various parts of the country. So, the implication is, till the courts decide, nothing can be done. If the Government is actually sincere about this Report and if the Government wants to deliver justice, it must, through its judicial officers, intervene in this judicial process, get all these cases clubbed together and be brought to the Supreme Court for immediate disposal. Sir, the Government should club all these cases together, bring them all before the Supreme Court and ask the Court to give an early verdict on it. Otherwise, this will go on for years together. The point is: it is important to create credibility in our system. That is the important point I wish to touch upon. What was demolished, in my opinion, was not just the Babri Masjid or a structure. What was demolished was an attempt to demolish one of the foundations and pillars of modern India. The foundations and pillars of modern India were sought to be demolished. It was done on the basis of a very strong political campaign that was built up leading to demolition. The Liberhan Commission has nails down the entire sequence of events. It not only nailed down the sequence of events, but, I think, the important point that has not been properly brought out is, in the years leading up to the demolition, you had a very rabid communal campaign and inflammatory on communal passions unleashed in the country. This was unleashed which resulted in demolition and I quote the then Prime Minister's own admission. He says, "In 1989 when the Sila Poojans began, there were, in that year alone, 79 communal incidents, 505 people died and 768 injured. During the Rath Yatra of Shri Advani in 1990, 312 communal incidents took place, 483 were killed and more than 2,000 injured, 210 mosques and 35 temples were damaged or desecrated during that period." This build up ultimately led to the demolition. And, after that, we have seen that more than 3,000 people dying all across the country. So, the point that we try to understand here is that the very concept of modern India has been challenged. This challenge cannot go unmet. This challenge has to be met in which case a criminal act of destruction of a place of worship — a Masjid — has to be brought to book. If that justice has to be done, I think, we need to go back into the very concept of why are such issues brought to the fore for political expediency.

The entire temple movement, I would submit, is the worst expression of vote bank politics. It was the worst expression of vote bank politics. I do not require any evidence and Report of the Commission of Inquiry for that. As a practising politician, I can tell you that this was the worst vote bank politics that took place and it continues to take place Sir, I think the battle between these three visions began in 1920's. It was a remarkable coincidence in that decade. You had the

formation of the RSS; you had the formation of the Communist Parties and you had the recommendations of the Motilal Nehru Committee which, actually, defined the structure of the Congress and its programmatic orientation in 1928. Since then began, Sir, a battle between three visions as to what should constitute Modern India. There was a Congress vision about what should constitute 'Modern India', which was the leading vision when we acquired Independence. That was the vision of having a secular democratic system. A secular democratic foundation was laid for Modern India. Then, you had the Left vision, which we articulated, and we continue to articulate. Merely the establishment of a secular democratic India is not sufficient. Unless you translate the political independence into the economic independence of the people, you cannot even sustain this very secular democratic India. To sustain that, you require to transform this and the Left continued with that vision which continues even today, for such a social transformation and for the true economic independence of our people. But, Sir, antagonistic to these two visions — that is why, I differ with the hon. Home Minister that it was a battle not between these two visions of India, but you had a battle among three visions — and completely disagreeing with both these visions was the third variant which had twin expressions. That vision was, the future Independent India would be decided by the religious denomination of its people. One expression was found in the *Muslim* League which talked of a separate Islamic nation, and the other was found in the *Rashtriya Swayam Sevak Sangh* which talked of *Hindu Rashtra*. Some people, today, bring out these points of commonality between the vision of the twin expression that came in on the basis of the religious denomination of the people. Well, some heads have rolled within the BJP, former Leader of the Opposition is no longer with the Party, poor man, for having, I think, said the truth. Three years before Mohd. Ali Jinnah articulated his 'Two Nation theory, addressing the Hindu *Mahasabha*, in his presidential address, Savarkar says and I quote: "India cannot be assumed today to be a Unitarian and a homogenous nation. But, on the contrary, there are two Nations in the main, the *Hindus* and the *Muslims*." Later in 1943, Savarkar says again, " I have no quarrel with Mr. Jinnah's 'Two Nation' Theory. We, Hindus, are a Nation by ourselves and it is a historical fact that Hindus and Muslims are two Nations." This sub-communal virus that came to dominate sections of our polity at that point of time continues to take its toll even today, Sir. And, it is this battle among these three visions that has to be settled by India and it is this battle that is continuing even today. We have achieved certain milestones in politically isolating these forces that seek to destroy the plurality of my country, destroy the fact that we cannot but exist only on the basis of our diversity. The country can be strengthened only if we strengthen the bonds of commonality amongst our diversity and not by imposing a uniformity on this diversity, whether it is religious, whether it is linguistic, whether it is cultural or any other form. This reality must be accepted and what we are discussing today is a part of this battle that is continuing. That is why, Sir, as I said, it is not, actually, the destruction of any concrete structure or the destruction of a mosque alone, but it is

destruction of what 'Modern India' ought to constitute, it is that which is important and, therefore, justice being delivered on this score is very important. That is why, Sir, I have drawn the attention of the House once earlier, but I want to draw it again, with your permission, Sir, to the very fact that let us go back to the first article of our Constitution. What do we say? We say, " India, that is Bharat, is a Union of States." Now, why 'Bharat', Sir? Without 'that is, Bharat' also, the clause would read the same, both in letter and spirit, or may be in spirit; it may be different in letters. But why did we add 'Bharat', Sir? Why was it not 'Hindustan'? Why was it not 'Hind'? Why was it not various other names that came?

श्री रुद्रनारायण पाणि: संसद भवन में जगह-जगह पर जो संस्कृत में लिखा हुआ है।

श्री सीताराम येचुरी: पाणि जी, एक मिनट ....**(व्यवधान)**... सर आपके माध्यम से मैं यही कहूंगा कि सीताराम को बोलने से टोकोगे तो पाप पाओगो ...**(व्यवधान)**... अब आप समझ गए न, बस अब आप यह मत करिए ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: अगर आप ...**(व्यवधान)**... आपको पाप मिलेगा ...**(व्यवधान)**... ।

श्री सीताराम येचुरी: आपको भी उतना ही पाप मिलेगा ...**(व्यवधान)**... आपको भी उतना ही पाप मिलेगा ...**(व्यवधान)**... ।

Sir, why this word, 'Bharat'? We said, 'Bharat' is, because he is one of the brothers of Ram. But that Bharat was different. There is another Bharat who was the son of Shakuntala and Dushyant. And because of whom they say these lands were united. There was another Bharat *muni*, who in the Vedic traditions, is supposed to have given us a lot of wisdom and brought about unity. But all that apart, I believe firmly, the word 'Bharat' has been added in our Constitution with a specific purpose, and that purpose was to describe a country with such diversity that does not exist anywhere else in the world. How the name of our country has come about, is worth mentioning, Sir. 'Bharat' is a confluence of three syllables. One is 'Bha' — *bhavana* or *bhavam* as we call it in the South; 'ra' is *ragam* or *raga*, the melody, the music; 'tha' is the *taal*, that is, the rhythm. Thus, the character which expresses in a melodious tune, with a proper rhythm, is my country, Bharat. That is the proper rhythm; this is my country. Like in *sa re ga ma pa dha ni sa*, you would have a Hindu, a Muslim, a Sikh, an *Isai*, a Buddhist, a Jain, and you would have an atheist, like me. But it can happen only with all of them combined into a melodious rhythm, a melodious tune. That is how I will define my country. And, that is broken the moment you try to impose any uniformity. And communalism is the worse uniformity that is sought to be imposed to divide my country. That is why, today, I think we should take this discussion on this Commission as a resolve to deliver justice, to get this confidence back into our people that this is a system on which there cannot be any compromise; this is the character of modern India which is not negotiable. Therefore delivery of justice today is absolutely important.

Now, if that is the position, Sir, I come to the other point. If the Congress vision was that of a secular, democratic India and it was for a secular society, then why is it that under the

Congress Government we had this heinous crime being committed? We have gone through this and we will go through this again! But I would like to only say that I am very dissatisfied with the Commission. I am not going into all the judgements of the Supreme Court which said very clearly that they stand betrayed by all the assurances they had been given. That is a point apart. But when Shri P.V. Narasimha Rao was the Prime Minister, at that point of time he had written a book, and I am quoting from his own book on Ayodhya, only to establish the point that the whole country, the secular sections of the country, completely empowered him to do whatever was necessary to protect the Babri Masjid and uphold secularism. I am quoting from his own writing, page 105, "Amidst the boycott of the BJP and VHP, the National Integration Council held its meeting as per schedule on 23rd November 1992. A four-line Resolution was moved by the CPM leader, Shri Harkishan Singh Surjit, and was adopted by thumping of desks. The Resolution stated, 'The NIC meeting, after considering all aspects of the Babri Masjid - Ram Janmabhoomi dispute and the report of the Government, extends its whole-hearted support and cooperation in whatever steps the Prime Minister considers essential in upholding the Constitution and rule of law and in implementing the Court orders'".

I do not think any Prime Minister of the country has been given any greater power than this sort of wide-ranging authority bestowed on him, to do whatever is necessary in order to uphold the rule of law. And then he goes on to say more; it makes for an interesting reading as to how he feels he has been betrayed on this entire point. But it is not the question of any one person's betrayal; there is a whole system at work. You had the collective responsibility of the Cabinet. You had Members of the Cabinet even then and some of them are Members of this House who raised these issues. But, here, what is Mr. Narsimha Rao's own assessment that he comes to? I quote this from the concluding paragraph of this book. "They.." meaning his detractors, "..could loudly proclaim later that the Muslim vote did not come to the Congress after the demolition of the Babri Masjid solely because of me ..", that is Mr. Narsimha Rao, not me, "It remains to be seen whether the future will vindicate me in this regard." The future has not vindicated him. After his death, we will have to say that future has not vindicated him. In fact, it vindicated his detractors. It has vindicated too much damage to the Congress, much damage to the country and its polity. It has actually vindicated how a serious misjudgement can be made and that is what raises the doubts whether it was believing in something that should not be believed in, or, whether there was also shades of pale saffron and soft Hindutva at work, which is what our charge has always been. Whatever all has been earlier referred to, whether it was Shilanyas, opening the locks, Shahbano, etc., etc., whether all this was a cumulative game, but that is something that the country cannot afford. We will have to go past it because on the 7th of December it was Mr. Narsimha Rao in both the Houses — I will quote from his statement that he made, where he said, at that point of time, which even then everybody thought it may not be possible but it goes down as an exercise where we are not serious about what we are saying and

what we want to do with our country — who said, "The demolition of the mosque was the most barbarous act. The Government will see to it that it is rebuilt." Now these issues have been raised, my colleague in the Samajwadi Party has raised this, they remain and will remain unanswered. The basic issue right now is that Liberhan Commission despite all its faults, despite the delay it took in coming out with its Report, despite the fact whether it was Liberhan or Giani who wrote it and whatever else be the thing, the point is that the content is on the demolition of Babri Masjid which was a criminal act. The conclusion that he has come to is: 'That it was not an act of spontaneity, but a pre-planned act which was meticulously implemented.' If that is the conclusion that he comes to, proper action must follow. I am urging the Government to actually have a re-look at the ATR and strengthen this. It is not only to bring in certain laws, but how is justice going to be delivered. And if justice is not delivered, please believe in me, the credibility of the system will go down further and that is very, very dangerous for the future of India. And that is why, yes I have used this analogy in the past, but the point still remains कि आपको एक खूनी और एक कोतवाल के बीच में फर्क तो करना पड़ेगा। कोतवाल की कमजोरी की वजह से कोई खून हुआ। वह खून को रोक सकता था, लेकिन रोका नहीं और क्योंकि वह खून होने से रोक नहीं पाया, इसलिए खून हुआ। इस प्रकार इसके लिए कोतवाल जिम्मेदार है। आपको कोतवाल को कठघरे में खड़ा करने की जरूरत है। जो कोतवाल उस समय के थे, वह तो खैर अब हैं नहीं, लेकिन सरकार तो थी, इसलिए उसकी जिम्मेदारी उसे लेनी होगी। आखिर खूनी ने ही तो खून किया। खूनी को तो आप नहीं बख्श सकते हैं! खूनी को तो आपको सजा देनी होगी। यह खून हुआ, हालाँकि यह होना नहीं चाहिए था यह अलग बात है, लेकिन वह हुआ। अब आपको उस खूनी को सजा देनी है। अगर आप उसे सजा नहीं देंगे तो हमारे सिस्टम के अन्दर विश्वास पूरा खत्म हो सकता है।

सर, आज के दिन हमारे दूसरे साथी भी इस मुद्दे पर बोलेंगे। मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है, इस पार्लियामेंट में भी बहुत-सी जगहों पर लिखा है- 'तमसो मा ज्योतिर्गमय।' भूत के अंधेरे में नहीं रहिए कि 500 साल पहले क्या हुआ या 15 सौ साल पहले क्या हुआ? देखिए, मेरी किस्मत अच्छी है कि मैंने अपने परदादाओं के साथ खेला है। पता नहीं, आप में से कितने अपने परदादाओं के साथ खेले होंगे? आप तो वहाँ तक भी नहीं पहुँच सकते, अपने परदादा तक, और आप 500 साल पीछे पहुँचेंगे, 15 सौ साल पीछे पहुँचेंगे? सर, अब सवाल यहाँ पर यह है कि मेरे मुल्क की दो-तिहाई आबादी नौजवान है। उसकी उम्र 40 साल से कम है, उसको चाहिए नौकरी, उसको चाहिए भविष्य, मंदिर बने या मस्जिद बने, यह सवाल उसके सामने नहीं है, ...**(व्यवधान)**... तो यहाँ पर...**(व्यवधान)**...

श्री बलबीर पुंज: आप अभी तक बाबरी मस्जिद को लेकर रो रहे हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री सीताराम येचुरी: पुंज साहब, आप कोशिश कीजिए, मुझे नाम लेकर नहीं कहना चाहिए था। मैंने उस समय भी एक लेख लिखा था और पत्रकारों की जो हालत 6 दिसम्बर 1992 को हुई थी, ...**(व्यवधान)**... उस समय मैं आपकी प्रशंसा कर रहा था कि अगर पुंज साहब जैसे लोग पत्रकारों में हैं तो कारसेवकों की जरूरत नहीं है पिटाई करने के लिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री बलबीर पुंज: मुझे याद है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सीताराम येचुरी: याद है न आपको, तो फिर आज आप provoke मत कीजिएगा।...**(व्यवधान)**... आप provoke मत कीजिए।...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: नंदीग्राम में पत्रकारों के साथ क्या हुआ?...**(व्यवधान)**...

श्री सीताराम येचुरी: 500 साल पहले क्या हुआ? ...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: नंदीग्राम में क्या हुआ था? ...**(व्यवधान)**... 6 महीने पहले नंदीग्राम में क्या हुआ था? ...**(व्यवधान)**...

श्री सीताराम येचुरी: सर, लोगों में एक बड़ी अजीब बीमारी होती है कि उनको कभी 6 महीने पहले की बात याद आती है और कभी 500 साल पहले की बात याद आती है, बीच में कुछ याद नहीं आता।...**(व्यवधान)**... इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको।...**(व्यवधान)**...

श्री कलराज मिश्र: खूनी कौन है, उसको तो आप identify कीजिए...**(व्यवधान)**...

श्री सीताराम येचुरी: बिल्कुल। ....**(व्यवधान)**... Point यही है।...**(व्यवधान)**...

श्री बलबीर पुंज: सर, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : नहीं, वह yield नहीं कर रहे हैं।

श्री बलबीर पुंज: सर, इन्होंने मेरा नाम लिया है ...**(व्यवधान)**... मैं यह पूछना चाहता हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी ने पाकिस्तान की डिमांड को सपोर्ट किया था या नहीं किया था? ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: वह सवाल यहाँ नहीं है...**(व्यवधान)**... This has nothing to do with the subject.

श्री बलबीर पुंज: इन्होंने देश को तीन हिस्सों में बांटा। देश को बांटने में...**(व्यवधान)**...

श्री सीताराम येचुरी: मैं आपको और इस सदन को भी यह बता दूँ। मैंने यह पढ़ कर भी सुना दिया, यह शायद अंग्रेजी में था। मैं अभी इसका अनुवाद हिन्दी में करके आपको सुनाता हूँ कि सन् 1940 में जब जिन्ना साहब ने लाहौर में two-nation theory की बात कही थी, उससे ठीक तीन साल पहले 1937 में विनायक दामोदर सावरकर ने हिन्दू महासभा को address करते हुए अपने Presidential address में यह कहा था कि अपने मुल्क के अंदर दो देश हैं, एक हिन्दू राष्ट्र, एक मुसलमानों का देश। ...**(व्यवधान)**... तो यह बात है।...**(व्यवधान)**...

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: जो आप पहले कह चुके हैं, वह सुन लिया। ...**(व्यवधान)**... आप क्यों दोहरा रहे हैं...**(व्यवधान)**... आप बैठिए।...**(व्यवधान)**...

श्री सीताराम येचुरी: कलराज मिश्र जी ने कहा था कि यह बताइये।...**(व्यवधान)**...

श्री बलबीर पुंज: जहाँ तक ...**(व्यवधान)**...

श्री सीताराम येचुरी: आप 17 साल बाद मेरे point को फिर से सही prove कर रहे हैं। ..**(व्यवधान)**.. आप जब तक रहेंगे तब तक और किसी भी कारसेवक की जरूरत नहीं है मुझे पिटाई करने की ..**(व्यवधान)**

SHRI BALBIR PUNJ : I am proud to be a *karsevak*. . *(Interruptions)*

श्री उपसभापति: ठीक है, आप बैठिए।...**(व्यवधान)**...

श्री सीताराम येचुरी: सर, मेरा यही कहना है कि इन्होंने कहा कि खून किसने किया, यह बताओ। हमने बताना नहीं। लिब्रहान कमीशन ने 68 नाम गिनाये, अब इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, जल्द से जल्द हो और लोगों को इंसाफ दिलाया जाए।

आखिर में, मैं यही कह रहा था, जब interruption हो गया, कि "तमसो मा ज्यातिर्गमय"। आप भूत के अंधेरे से अलग हटकर भविष्य के उजाले में चलिए, तभी हमारा भारत महान हो सकता है। इस तरह के चक्कर और झगड़ों में फंसना अपने देश की ताकत को कमजोर करने वाली बात होगी। इससे देश को फायदा नहीं, नुकसान ही है। अब साल हो गये, इस राजनीति को छोड़ दीजिए और चलिए हम एक आधुनिक भारत का निर्माण करें।

श्री गंगा चरण (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं अपनी बात लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट की प्रस्तावना से शुरू करता हूँ। मैं पूरी रिपोर्ट से तो सहमत नहीं हूँ, लेकिन लिब्रहान कमीशन ने जो बातें प्रस्तावना में कही हैं, उनसे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मैं आज सदन के सामने लिब्रहान कमीशन द्वारा जो प्रस्तावना लिखी गई है, उसको पढ़कर सुना रहा हूँ।

कुछ लोगों के लिए सत्ता का प्रलोभन सर्वोपरि होता है, सत्ता प्राप्त करने का सामान्य साधन राजनीति होता है। हमेशा सत्ता प्राप्त करने और अपने प्रयोजन के लिए राजनीति का उपयोग करने की लालसा और इच्छा होती है। राजनैतिक रूप से वांछनीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के आगे किसी चीज का महत्व नहीं होता, चाहे वे किसी भी तरीके से प्राप्त किए जाएं। सत्ता प्राप्त करने की प्रक्रिया में इस बात की भी परवाह नहीं की जाती है कि इस प्रकिया का संस्था, राष्ट्र, व्यक्तियों और समूचे समाज के लिए क्या परिणाम होगा। स्वयं जीवन का राजनीतिकरण हो जाता है। इस प्रक्रिया में वस्तुपरकता, राजनीतिक ईमानदारी अथवा स्तर का लोप हो जाता है। राजनैतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए अथवा राजनैतिक रूप से वांछनीय परिणाम प्राप्त करने के लिए संविधान, कानून, लिखित अथवा अलिखित, नैतिक आचार-विचार एवं धर्म ग्रंथों की तिरस्कारपूर्ण अवहेलना की जाती है। मैं इस लाइन को दोबारा पढ़कर सुनाता हूं, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजनैतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए अथवा राजनैतिक रूप से वांछनीय परिणाम प्राप्त करने के लिए संविधान, कानून, लिखित अथवा अलिखित, नैतिक आचार-विचार एवं धर्म ग्रंथों की तिरस्कारपूर्ण अवहेलना की जाती है। शासन की स्वस्थ अथवा वैध प्रक्रिया की परवाह नहीं की जाती है और राजनीतिक तटस्थता समाप्त हो जाती है।

मान्यवर, मैं यहीं से अपनी बात शुरु कर रहा हूं। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का जो आन्दोलन चलाया, उसके लिए मैं दो लाइनें अर्ज़ करना चाहता हूं, यहां वरिष्ठ नेता विराजमान हैं — कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, बड़ा जुल्मी है जालिम जमाना। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की निगाहें उस समय दिल्ली की कुर्सी पर थीं और निशाना ढांचा था। इसलिए, इनका मकसद राम मंदिर बनाना नहीं था, मकसद सत्ता प्राप्त करना था। मंदिर तो एक बहाना था, भाजपा को सत्ता हथियाना था और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को मिटाना था। अभी तक लोक सभा और राज्य सभा में जो चर्चा हुई, किसी भी हमारे सम्मानित सदस्य ने ...**(व्यवधान)**... मैं कहां था यह भी बता रहा हूं, इसका ज़िक्र नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी की इस आन्दोलन के पीछे मंशा क्या थी। मैं याद दिलाना चाहता हूं अपने साथियों को कि 1989 में, 9वीं लोक सभा में, मैं लोक सभा का मैम्बर था, मुझे याद है शायद माननीय श्री शांता कुमार जी भी उस समय मिनिस्टर थे, माननीय श्री वी0पी0 सिंह जी के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी थी, जिसे बाहर से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। मैं याद दिलाना चाहता हूं उस आन्दोलन की कि माननीय कांशी राम जी के नेतृत्व में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए दिल्ली का घेराव किया गया था। चौराहों पर एक महीने तक ये नारे लगाए गए थे — मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। अंदर से जनता दल का मेनिफेस्टो था कि सरकार बनेगी तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। हम लोगों ने अंदर से दबाव बनाया कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाए और माननीय श्री वी0पी0 सिंह ने 1990 में

मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की। जैसे ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई, मंडल विरोधियों ने देश में आग लगा दी, पूरी दिल्ली धू-धू करके जलने लगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मंडल कमीशन की रिपोर्ट नागवार गुजरी और उन्होंने इसका कैसे विरोध किया जाए, इसका एक नया तरीका निकाला।

मुझे याद है कि उस समय तक जनता दल की सरकार से उनका कोई विरोध नहीं था, लेकिन जैसे ही पिछड़ी जातियों को 27 फीसदी आरक्षण देने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई, भारतीय जनता पार्टी को यह बात पसंद नहीं आई। यदि वे प्रत्यक्ष रूप में विरोध करते, तो देश की सारी पिछड़ी जातियां इनके खिलाफ हो जातीं। इसलिए इन्होंने एक योजना बनाई और जनता दल की सरकार को गिराने के लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा कर दी कि हम रथ लेकर चलेंगे, कमंडल लेकर चलेंगे ...**(व्यवधान)**...

श्री कलराज मिश्र: आप भी शायद उस समय बी.जे.पी. में थे?

श्री गंगा चरण: नहीं, मैं बी.जे.पी. में नहीं था, मैं जनता दल में था ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप लिब्रहान कमीशन पर बात कीजिए, आप कब कहां थे, यह विषय नहीं है।

श्री गंगा चरण: उपसभापति जी, मैं लिब्रहान कमीशन की बात पर ही आ रहा हूं, लिब्रहान कमीशन ने वी.पी. सिंह जी का जिक्र किया है और यह भी बताया है कि मस्जिद गिराने का उद्देश्य क्या था, ढांचा गिराने का उद्देश्य क्या था। मैं जिक्र करना चाहता हूं कि 1950 से उस ढांचे में मूर्तियां स्थापित हो गई थीं, पूजा हो रही थी और 1990 तक किसी को मंदिर निर्माण की याद नहीं आई, लेकिन जैसे ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई, सिर्फ एक बहाना बनाकर कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को हमें समाप्त करना है, इसलिए वह आंदोलन चलाया गया था। उस आंदोलन के पीछे केवल जनता दल की सरकार को गिराने की मंशा थी।

श्री रुद्रनारायण पाणि: आंदोलन कब से शुरू हुआ ...**(व्यवधान)**...

श्री गंगा चरण: आप बैठिए, अभी मैं बोल रहा हूं, जब आपका नंबर आएगा, तब बोलिएगा ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: पाणि जी, आप बैठिए, देखिए, हाउस का वक्त जा रहा है ...**(व्यवधान)**... यह ठीक नहीं है। See, you are wasting the time of the House. ...*(Interruptions)*... आप बैठिए, इससे आपको भी कोई फायदा नहीं मिलेगा, आपको भी समय नहीं मिलेगा।

श्री गंगा चरण: उपसभापति जी, कार-सेवा शुरू हुई और माननीय मुलायम सिंह जी ने कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण भाषण दिए कि परिंदा, पर नहीं मार पाएगा, इससे और उत्तेजना फैली। कार-सेवकों पर गोली चली और जनता दल की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये रामभक्त बनते हैं, राम मंदिर बनाना चाहते हैं, लेकिन ये असली तौर पर रामभक्त नहीं हैं और राम मंदिर बनाने की इनकी कोई मंशा नहीं है, यह मेरा आरोप है। ये सिर्फ पिछड़ी जातियों के विरोधी हैं, पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ न मिले, इसलिए यह पूरी योजना रची गई थी। ये केवल पिछड़ी जातियों के विरोधी नहीं हैं, बल्कि ये दलितों के भी विरोधी हैं। इन्होंने 6 दिसंबर की तिथि क्यों चुनी? उस दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का निर्वाण दिवस था। उस दिन सारा देश, हमारे सारे पिछड़े और दलित भाई शोक में डूबे होते हैं, उसी दिन को इन्होंने उस ढांचे को गिराने के लिए चुना। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह पार्टी केवल मुसलमानों की विरोधी नहीं है, बल्कि दलितों और पिछड़ों की भी विरोधी है,

उपसभापति जी, ये कहते हैं कि लिब्रहान आयोग ने लिखा है कि सत्ता का लालच हमें अपने धर्मग्रंथों की अवहेलना करने के लिए भी मजबूर कर देता है और हम अपने धर्मग्रंथों को ताक पर रख देते हैं। इन्होंने भी यही किया, अपने धर्म-शास्त्रों का अपमान किया और उनकी अवहेलना की। गोस्वामी तुलसीदास जी से बड़ा कोई रामभक्त, हिंदुस्तान तो क्या, पूरे विश्व में नहीं हुआ है। उन्होंने रामचरितमानस में भगवान राम के चरित्र की

व्याख्या की है और उन्होंने कहा है कि राम के आदर्शों, राम के पदचिह्नों पर चलने वाला व्यक्ति ही रामभक्त कहलाएगा। तो राम का चरित्र क्या था? राम का चरित्र यह था कि—

"रघुकुल रीति सदा चली आई।
प्राण जाए पर वचन न जाई।।"

मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने कैसे अपने वचन को भंग किया।

श्री रुद्रनारायण पाणि: आपने कितनी बार पार्टी बदली?

श्री गंगा चरण: आप चुपचाप बैठकर सुनते रहिए, मैं आपसे माफी चाहता हूं। यह मंच है बोलने का, अपनी-अपनी बात कहने का, आपका नंबर आए, तो आप अवश्य अपनी बात कहें ...**(व्यवधान)**... इस तरह कमेंट्री न करें ...**(व्यवधान)**...

मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय कल्याण सिंह जी के बयान को उद्धरित करना चाहता हूँ, जो उन्होंने 2 नवंबर, 1991 को राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में दिया — "जहां तक विवादाग्रस्त ढांचा है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जैसा मैंने आपको आश्वासन दिया कि उस विवादाग्रस्त ढांचे की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। हम मुस्तैदी से उस ढांचे की सुरक्षा करेंगे। हमने वहां उसकी सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध किए हैं। वहां पर अब कोई नहीं जा पाएगा। जो घटना घटित हो गई थी, तीन लोग गुम्बद पर चढ़ गए थे, लेकिन अब वहां पर किसी प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी।" यह आश्वासन मैं इस सदन के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, "कुल मिलाकर न्यायालय की बात के बारे में यह स्पष्ट निवेदन है कि न्यायालय ने जो आदेश दिया है, उस आदेश का पालन हम करेंगे। हम न्यायालय के आदेश से बंधे हैं। इसके आदेश को तोड़ कर हम कोई काम नहीं करना चाहते हैं।" यह मैं inverted comma में बात कर रहा हूँ। तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय कल्याण सिंह जी ने राष्ट्रीय एकता परिषद और न्यायालय के सामने यह कहा। इससे आप सहमत हैं? मुख्य मंत्री जी ने चार विशिष्ट आश्वासन दिए। इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण हल ढूढ़ने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे, जब तक अंतिम हल नहीं हो जाता है, तब तक उत्तर प्रदेश सरकार राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार समझी जाएगी। भू-अधिग्रहण कार्यवाहियों से संबंधित न्यायालय के आदेशों का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन किया जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों में उनके निर्णय का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। माननीय कल्याण सिंह जी ने यह लिखित आश्वासन/affidavit सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय एकता परिषद में दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि महामना गोस्वामी तुलसी दास जी ने कहा है कि "रघुकुल रीत सदा चलि आई और प्राण जाए पर वचन न जाए"। राम भक्त वह है, जो अपने वचन का पालन करे। प्राण चले जाएं, पर वचन नहीं जाना चाहिए। राम ने अपने माता-पिता के वचन का पालन करने के लिए सत्ता का परित्याग कर दिया और चौदह वर्ष का वनवास भोगा। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के लिए अपने वचन का परित्याग कर दिया, इसलिए आप राम भक्त नहीं हो सकते हैं। ...**(व्यवधान)**... चलिए हम इस अपराध को भी माफ कर सकते हैं कि इन्होंने अपने वचन को भंग किया, कानून तोड़ा, संविधान का उल्लंघन किया और न्यायपालिका की मर्यादा तोड़ी। आप कहते हैं कि हमारी आस्था और जन भावनाओं का सवाल है। देश चाहता है कि राम मंदिर वहीं बने। देश नहीं दुनिया चाहती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जब देश की जनता ने तीन बार उत्तर प्रदेश में और केन्द्र में सरकार बनाने का मौका दिया, तो फिर उस समय आस्था का सवाल कहां चला गया था, वे जन भावनाएं कहां चली गई थीं, वह शहादत कहां चली गई थी। फिर आपने मंदिर क्यों नहीं बनाया? आपके पास इसका कोई जवाब है? फिर आप कहेंगे कि हम कानून कैसे तोड़ते, हम न्यायपालिका की मर्यादा को कैसे भंग करते। आप कब से कानूनदा हो गए? जब आप एक बार मर्यादा भंग कर सकते हैं, एक बार कानून तोड़ सकते हैं, एक बार संविधान का उल्लंघन कर सकते हैं, तो जनता को दिए हुए वचन के लिए आप कानून तोड़ सकते थे, लेकिन आपने कानून इसलिए नहीं तोड़ा कि यदि

आप कानून तोड़ कर मंदिर बनवाते, तो alliance दल आपसे समर्थन वापस ले लेता और आपकी सरकार गिर जाती। इससे स्पष्ट होता है कि आप सत्ता लोलुप हैं, सत्ता भक्त हैं और राम भक्त नहीं हैं। आप यदि सच्चे दिल से भगवान राम से प्रार्थना करते कि मंदिर बनना चाहिए, तो बनता।

"जो इच्छा करुहु मन माहीं, राम कृपा कछु दुर्लभ नाहिं।"

यदि आप सच्चे दिल से मंदिर बनाना चाहते, तो मंदिर ज़रूर बनता। आपने तो सच्चे दिल से भगवान राम से सत्ता मांगी थी, इसलिए सत्ता मिल गई, आपने राम मंदिर नहीं मांगा था।

आप कहते हैं कि वह राम जन्मभूमि है। मैंने अपने धर्मग्रंथों को थोड़ा बहुत पढ़ा है, ज्यादा अध्ययन तो आप ही ने किया है, ज्यादा ज्ञाता आप ही लोग हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने भी अध्ययन किया है, क्योंकि मैं भी हिंदू हूं, मैं भी सत्संग करता हूं, मैं भी "आस्था" देखता हूं, मुरारी बापू की कथा सुनता हूं। तमाम संतों की कथा सुनने के बाद, सारे संतों का, हमारे धर्मशास्त्रों का यही मत है कि राम का जन्म नहीं हुआ, राम प्रकट हुए थे और यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है—

"भये प्रगट कृपाला, दीन दयाला कौशिल्या हितकारी।
हर्षित महतारी, मुनिमन हारी अद्भुत रूप निहारी।।"

चार भुजाओं वाले, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए साक्षात् विष्णु भगवान प्रकट हुए थे, राम का जन्म नहीं हुआ था और तब माता कौशल्या ने कहा था—

"कीजै शिशु लीला अति प्रिय शीला, सो सुख परम **अनूपा**।"

कथा लंबी है। मन-शतरूपा की कथा में जाएं, तो विष्णु भगवान की तपस्या करते हुए उन्हें वरदान मिला था। उन्होंने अपने पुत्र के रूप में वरदान मांगा था और किसी भी धर्मग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि पैगम्बर पैदा होते हैं। पैगम्बर हमेशा दुनिया में प्रकट होते हैं। तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि वहां राम जन्मभूमि थी? वहां राम का गर्भगृह था? "मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लला हम आएंगे" पर तारीख नहीं बताएंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि वहां जन्मभूमि थी? वहां जन्मभूमि थी, तो किसकी जन्मभूमि थी? क्या परमब्रह्म परमात्मा की जन्मभूमि थी? परमब्रह्म परमात्मा कभी गर्भ में नहीं जाता है। परमब्रह्म परमात्मा, जिसने हमारी पृथ्वी की रचना की है और ....

श्री उपसभापति: गंगा चरण जी..... अब सिर्फ दो मिनट बाकी हैं आपके।

श्री गंगा चरण: सर, हमारी नेशनल पार्टी है, सिर्फ दो मिनट कैसे होंगे? सबका समय बराबर होगा।

श्री उपसभापति: नहीं, नहीं। आपका जितना समय है, उतना समय दे रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री गंगा चरण: आप नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं?

श्री उपसभापति: नाइंसाफी नहीं है, हम इंसाफ कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री गंगा चरण: सर, हमारी नेशनल पार्टी है, दूसरे मैम्बर भी हैं।

श्री उपसभापति: प्लीज़, आप conclude कीजिए।

श्री गंगा चरण: चलिए, हम अपनी बात जल्दी समाप्त करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है –

"विप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार।"

भगवान ने अवतार लिया है और आप झगड़ा कर रहे हैं कि राम जन्मभूमि है, भगवान पैदा हुए। यदि आपने धर्मग्रंथों का अध्ययन किया है, तो आप साबित कीजिए कि भगवान पैदा हुए और यदि भगवान पैदा हुए, तो वे दशरथ के पुत्र राम हो सकते हैं, वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नहीं हो सकते। भगवान पैदा होते ही नहीं हैं। मुझे एक कथा का प्रसंग याद आ रहा है कि जब रावण के अत्याचार से चारों ओर त्राहि-त्राहि मची हुई थी, तब

शंकर जी के पास देवता गए। उन्होंने शंकर जी से पूछा कि भगवान कहां रहते हैं? उससे पहले ब्रह्मा जी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि बैकुंठ में रहते हैं। बैकुंठ में गए, भगवान नहीं मिले, क्षीरसागर में भी नहीं मिले, तो शंकर जी के पास गए कि भगवान कहां रहते हैं? इनके भगवान तो अयोध्या में ही अकेले रहते हैं, लेकिन शंकर जी देवताओं से कहते हैं कि "हरि व्यापक सर्वत्र समाना"। ज़रा इसको गहराई से सुनिए – "हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मम जाना।" भगवान सभी जगह सर्वत्र, समान रूप से रहते हैं। वे मंदिर में भी उसी रूप से रहते हैं, मस्जिद में भी उसी रूप से रहते हैं, गुरुद्वारे में भी उसी रूप से रहते हैं और चर्च में भी उसी रूप से रहते हैं। भगवान कहीं भेदभाव नहीं करते हैं और "प्रेम से प्रगट" – भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, भगवान घृणा और हिंसा से प्रकट नहीं होते। प्रेम से एक बार शबरी ने पुकारा, तो भगवान शबरी के जूठे बेर खाने के लिए प्रकट हो गए। ...**(समय की घंटी)**... गुहराज निषाद ने बुलाया, तो गुहराज निषाद को प्रेम से गले लगा लिया — यह है भगवान राम का चरित्र! गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि "सियाराम मय सब जग जानी, करहुं प्रणाम जोरि जुग पानी।"

श्री उपसभापति: बहुत अच्छा, अब समाप्त कीजिए।

श्री गंगा चरण: मतलब यह कि इस धरती, आसमान, पर्वत — सभी में भगवान हैं, मैं उस भगवान श्री राम को प्रणाम करता हूं। ये हैं तुलसीदास जी के राम और रामायण में कहीं भी नहीं आया है कि उस अयोध्या के राम को मैं प्रणाम करता हूं। तुलसीदास जी ने दूसरा दोहा लिखा है...।

श्री उपसभापति: अब दोहे पर समाप्त कीजिए।

श्री गंगा चरण: उन्होंने लिखा है:—

जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान।
बन्दहु सबके पद कमल सदा जोरिजुग पान।।

जड़ यानी पहाड़, पर्वत, चेतन यानी पशु-पक्षी, जीव मतलब जितने भी संसार में जीव हैं और जत यानी जितनी भी जातियां हैं — हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई...।

जड़ जेतन जग जीव जत सकल राममय जान।
बन्दहु सबके पद कमल सदा जोरिजुग पान।।

जब गोस्वामी तुलसीदास जी सभी जीव-जन्तुओं, सभी जाति धर्म के लोगों की वंदना करते हैं तो आप अगर राम भक्त हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी को मानने वाले हैं तो फिर आप मुसलमानों से, ईसाइयों से, अल्पसंख्यकों से घृणा क्यों करते हैं?

श्री उपसभापति: आप समाप्त कीजिए।

श्री गंगा चरण: सर, केवल पांच मिनट और लूंगा। थोड़ा सा अपने कांग्रेसी बंधुओं की तरफ मुखातिब होना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: देखिए, अभी बहुत से honourable members को participate करना है। समय नहीं है। Please cooperate.

श्री गंगा चरण: सर, आपने सबको समय दिया है।

श्री उपसभापति: सबको उतना ही समय दिया है जितना उनका समय है।

श्री गंगा चरण: मैं माननीय कलराज जी से कहना चाहता हूं कि हिन्दुओं ने ही भगवान राम की महिमा नहीं गायी है ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप बहुत अच्छा बोले हैं। बस वहीं पर समाप्त कर दीजिए।

श्री गंगा चरण: रहीमदास जी ने भी भगवान राम के बारे में लिखा है कि

चित्रकूट में बस रहे रहिमन अवध नरेश।
जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश।।

अब मैं कांग्रेस के अपने बंधुओं से कहना चाहता हूं कि...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: कांग्रेस तक आने का समय नहीं है।

श्री गंगा चरण: सर, केवल एक मिनट। आप हमें बताइए कि आपकी मंशा क्या थी?...**(व्यवधान)**... सर, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: देखिए, मैं और ज्यादा समय नहीं दे सकता हूं। अभी दो-तीन और वक्ताओं ने बोलना है। ...**(व्यवधान)**... ऐसा नहीं हो सकता है। ...**(व्यवधान)**...

श्री गंगा चरण: उत्तर प्रदेश में माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार थी, केन्द्र में नरसिंहराव जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, बाबरी मस्जिद का आन्दोलन 2 नवम्बर 1991 से शुरू हुआ। 6 दिसम्बर 1992 में जब 70,000 कारसेवक वहां पहुंच गए और ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: श्री अली अनवर अंसारी।

श्री गंगा चरण: आपके गृह सचिव आपको मिनट-मिनट की सूचना दे रहे थे तो मैं जानना चाहता हूं कि उस समय आपने राष्ट्रपति शासन लागू क्यों नहीं किया? आपकी नीयत और आपकी नीति स्पष्ट नहीं थी। आप चाहते थे कि मुसलमानों को भाजपा का भय दिखाकर हम वोट हासिल कर लें, लेकिन मुसलमान समझ गया और इसीलिए आपको सजा दी कि 17 साल बाद भी आज पूर्ण बहुमत से आप केन्द्र में नहीं आ पा रहे हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं कि इस लिब्रहान कमीशन की जरूरत क्या थी? आप 17 साल पुराने घाव कुरेदना चाहते हैं, जले पर नमक छिड़क रहे हैं। इसकी जरूरत क्या थी? यह काम तो एक दारोगा भी कर सकता था...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप समाप्त करिए। श्री अली अनवर अंसारी।

श्री गंगा चरण: यह काम तो एक दारोगा भी कर सकता था, लेकिन आपने 2000 करोड़ रुपए खर्च करके ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: अब रिपोर्टिंग स्टॉप हो जाएगी।

श्री गंगा चरण: सर, केवल एक मिनट और लूंगा। आपने देश के धन की बर्बादी की है। आपकी नीयत और नीति स्पष्ट नहीं थी, इसलिए ढांचा गिरा। यदि आपकी नीयत और नीति स्पष्ट होती तो ढांचा गिरने वाला नहीं था। धन्यवाद।

श्री उपसभापति: श्री अली अनवर अंसारी। अंसारी जी, आपके पास दस मिनट हैं।

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): सर, जितना समय उनको दिया है, उतना ही मुझे भी दिया जाए।

श्री उपसभापति: नहीं। ऐसे नहीं होता है। उनकी पार्टी की strength अलग है, आपकी पार्टी की strength अलग है। मेहरबानी करके यह तुलना मत कीजिए।

श्री **अली अनवर अंसारी**: महोदय, पक्ष और विपक्ष के दो दिग्गज वकीलों ने अपनी राय जाहिर की है। माननीय वकीलों के बारे में कहा जाता है कि बाल की खाल निकालते हैं। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था और मुझे हैरत हुई कि दोनों माननीय वकील, माननीय सदस्यों ने बड़ी सफाई से जो मूल बात है, उसको गोल कर दिया। हम कहना चाहेंगे कि दोनों ने आधा सच कहा है। पूरा सच क्या है, मैं आपसे एक शायर की जुबानी अर्ज करना

चाहता हूं। वह शायर कोई दूसरी जगह का नहीं है, वह फैजाबाद का है, अयोध्या का है। जिसने एक तरह से अपने दिल और अपनी आंखों से देखा है छः दिसम्बर की घटनाओं को, वह है मिराज फैजाबादी। वह क्या लिखते हैं,

"हमारे माज़ी की एक इमारत यह कह रही है,

माज़ी का मतलब होता है भूत का, पीछे का।

"हमारे माज़ी की एक इमारत यह कह रही है,
बचाने वाले, गिराने वाले, सब एक निकले।"

महोदय, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने आधे सच का बयान किया है। महोदय, हमारी पार्टी का मानना है कि जो भी दोषी है, जिसने इतना बड़ा अपराध किया है उनको सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा भी कम होगी, सजा मिलनी चाहिए। यहां किसी के पर्सनल लॉ से देश नहीं चलेगा, किसी की आस्था से देश नहीं चलेगा। देश चलता है संविधान से, कानून के राज से, रूल ऑफ लॉ से। इस मुल्क में जम्हूरियत है, प्रजातंत्र है। छः दिसम्बर का जो हमला है, वह एक पुरानी मस्जिद ढहाए जाने का मामला नहीं है, वह हमारी जो जम्हूरियत है, हमारा जो संविधान है, हमारे मुल्क की जो आत्मा है, उस पर यह हमला है। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी सजा हो, उसके लिए कम है। हम चाहते हैं, हमारी पार्टी की नीति है कि इस मसले का हल आज भी किसी की आस्था से, किसी के विश्वास से नहीं होने वाला है। या तो यह मामला आपस में जो पक्षकार हैं वह बैठ करके तय करेंगे और नहीं तो कोर्ट तय करेगा और कोर्ट से भी हम चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द तय करे। जिस तरह से हमारी सरकार ने बिहार में स्पीडी ट्रॉयल करके जो बाहुबली हैं, जो अपराधकर्मी हैं, उन लोगों को शिकन्जे में लिया है। पहले होता क्या था कि मुकदमे चलते रहते थे और अपराधकर्मी, बाहुबली एम0एल0ए0 और एम0पी0 भी बने रहते थे। लेकिन आज वे शिकन्जे के पीछे हैं, सलाखों के पीछे हैं। इसलिए उस तरह से स्पीडी ट्रॉयल करके इस मामले का निष्पादन भी होना चाहिए। लेकिन महोदय, बड़े अफसोस के साथ हम कहना चाहते हैं कि जो लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट है और जिस तरह से वह तैयार की गई है तथा उस पर जो ए0टी0आर0 आई है, उसमें से कहीं यह मंशा नहीं झलकती है कि अपराधियों को सजा मिलेगी? कही भी यह मंशा नहीं झलकती है और संदेह होता है कि अपराधियों को सजा मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। 17 साल बाद यह रिपोर्ट आई है। महोदय, मैं सजा के बिन्दु से भी आगे जाकर कहना चाहता हूं, सभी पक्ष के लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, अभी माननीय कांग्रेस के नेता सिंघवी साहब बी0जे0पी0 पर आरोप लगा रहे थे कि वह रिग्रेट नहीं कर रही है। महोदय, हम कहना चाहते हैं कि यह पश्चाताप का मामला नहीं है, यह इतना बड़ा पाप है और दोनों पक्ष उसके दोषी हैं, जो उस समय स्टेट में हुकूमत में थे और सेंटर में हुकूमत में थे। इसके लिए प्रायश्चित होना चाहिए। पछतावा को पश्चाताप कहते हैं..... प्रायश्चित का मतलब होता है खुद को सजा देना और ऐसी सजा देना, जिसको दुनिया देखे और जनता समझे। उस पक्ष के लोगों को भी और इस पक्ष के लोगों को भी अगर सही मायने में इस मुल्क से मुहब्बत है, वे चाहते हैं कि यह बद-अमनी खत्म हो, इस मसले का हल हो, तो उनको प्रायश्चित करना चाहिए, खुद को सजा देकर के उनको दिखाना चाहिए, साबित करना चाहिए।

महोदय, हम कहना चाहते हैं कि हमें सहानुभूति की जरूरत नहीं है। हम सहानुभूति नहीं मांग रहे हैं, न इस सदन से मांग रहे हैं, न इस सरकार से मांग रहे हैं। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हम सहानुभूति नहीं, हम समानभूति की बात कर रहे हैं। हम सहानुभूति नहीं चाहते हैं, हम समानभूति चाहते हैं। समानभूति का मतलब है कि हम और आप एक जैसे अनुभव से गुजरें, इसी को समानभूति कहते हैं।

महोदय, हम कहना चाहते हैं कि अगर कोई जनता को बांटकर राजनीति करेगा, मजहब की बुनियाद पर करेगा, जाति की बुनियाद पर करेगा, इलाके की बुनियाद पर करेगा, जुबान की बुनियाद पर करेगा, तो इसी तरह के नतीजे आएंगे। हमें आज की बहस से अफसोस हुआ कि 17 साल के बाद भी हमने सबक नहीं सीखा है, लेकिन जनता ने कुछ-कुछ सबक सीखा है। जनता ने हम लोगों को पहचाना है कि जो हमारा नेतृत्व है वह कितना बौना है। हम बड़े-बड़े राजनेता तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन हम राष्ट्र नेता पैदा नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर स्टेटमनशिप नहीं है, आज भी आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, हमने अपने हृदय के अंदर झांककर देखने की कोशिश नहीं की है। महोदय, यह बड़े अफसोस का मुकाम है। हम कहना चाहते हैं कि मजहब की बुनियाद पर और दूसरी बुनियाद पर बांटने की जो राजनीति है, वह कहां से शुरू हुई ? महोदय, हमको यह कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है।

उपसभापति महोदय, आप भी सुनिए। हम अपने जाती तजुर्बे के आधार पर कह रहे हैं। मैं उन दिनों पत्रकार हुआ करता था। शाहबानो का मामला चल रहा था, हमने न जाने कितने अखबारों को काला किया है, हमने कितने अखबारों के पन्नों को काला किया है, कि यह गलत नज़ीर पेश की जा रही है किसी की आस्था की बुनियाद पर, किसी के पर्सनल लॉ की बुनियाद पर, बल्कि हमने तो यह कहा था कि इस्लाम के कंसेप्ट के खिलाफ बात है। एक बेवा औरत के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है, उस फैसले को बदल कर के, संविधान में संशोधन करके एक गलत नज़ीर पेश कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद को ढहाने वाले जो लोग हैं, आज वही उसको आधार बनाते हैं कि आपकी आस्था का सवाल था, तो हमारी भी आस्था का सवाल है, हम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे। ...**(समय की घंटी)**...

महोदय, हम कहना चाहते हैं कि चाहे शाहबानो का मामला हो या बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने का मामला हो, किसने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया, किसने शिला पूजन की इजाजत दी, कौन इस बंडी के ऊपर जनेऊ लगाकर दूरदर्शन पर और टी0वी0 पर पूरे मुल्क को दिखा रहे थे कि हम हिन्दू हैं, यह क्या संकेत देना है? आज सियासत में जो लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों ने समझा कि यह कॉपी राइट तो हमारे पास है। इधर के लोग इसको भुनाने के लिए चले, तो ये भी उससे कड़ा रुख अख्तियार करके, उसी रास्ते पर गामजन हो जाते हैं, चल निकलते हैं। वे सोंचते हैं। इसका एक्सपर्टीज तो हमारे पास हैं, आप क्यों प्रयोग करने लगे? ...**(समय की घंटी)**... महोदय, ऐसा मत कीजिए। मुझे पांच मिनट का समय और दे दीजिए।

श्री उपसभापति : देखिए, इस विषय पर बोलने के लिए जो आपकी पार्टी का समय है, आप उससे ज्यादा समय ले रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री अली अनवर अंसारी : हम बैठ जाते हैं, हुजूर।

श्री उपसभापति : मैं आपको बैठने के लिए नहीं कहूंगा, बल्कि मैं तो कहंूगा कि आप अपना समय लीजिए और समाप्त कीजिए।

श्री अली अनवर अंसारी : महोदय, हम आपकी बात का उल्लंघन नहीं करेंगे। हुजूर, हम एक बात कहकर बैठ जाते हैं। आज भी कुछ लोग यह कहते हैं और तैयारियां भी चल रही हैं पत्थर भी तराशे जा रहे हैं, नक्शे भी बनाकर दिखाए जा रहे हैं तथा उनकी बुनियाद पर पैसे भी वसूले जा रहे हैं। इन लोगों की टेक है कि हमारा मंदिर यहीं बनेगा। दूसरी तरफ दूसरे पक्ष के लोगों की भी टेक है कि हम उसी जगह पर मस्ज़िद भी बनाएंगे। महोदय, चाहे वह सिंघल हो, तोगड़िया हो, बुखारी हो या शाहबुद्दीन हो अथवा जो भी ऐसी दिमागी सोच के लोग हैं, जो मस्ज़िद बनाना चाहते हैं, जो मंदिर बनाना चाहते हैं, उन तमाम लोगों से हम हाथ जोड़कर यह कहना चाहते हैं कि आप नक्शे पर न जाएं। इस नक्शे से और इस जमीन के टुकड़े से मुल्क नहीं

चलता है, कौमें नहीं चल सकती हैं। हम इसकी त्रासदी को आज तक भुगत रहे हैं, झेल रहे हैं। महोदय, हम एक शेर कहकर, अपनी बात समाप्त करना चाहते हैं,

'नक्शे को तुम न जांचो, लोगों से मिलके देखो।
क्या चीज जी रही है, क्या चीज मर रही है।'

श्री तारिक अनवर: उपसभापति महोदय, मैं कानूनदा नहीं हूं, इसलिए कानूनी पेचीदगी में नहीं जाना चाहूंगा। मैं इतिहास में भी नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि इतिहास सबको मालूम है। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो विवाद है और जिसको लेकर जो घटनाएं घटीं और कमीशन बना तथा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, हम आज उसी पर बहस कर रहे हैं। उपसभापति महोदय, किसी भी विवाद का निपटारा करने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो बातचीत का रास्ता है। आपस में मिल-बैठकर बाचतीत के द्वारा अगर हम किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं, कोई समझौता हो जाता है, तो उसके जरिए उस विवाद का निपटरा किया जा सकता है, उसका समाधान किया जा सकता है। अगर उसमें पेचीदगी है, वह हल नहीं हो पाता है, तो फिर दूसरा रास्ता न्यायालय का है, कानून का है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी तथा उसके सहयोगी दलों का बार-बार यह कहना कि इससे कानून का कोई लेना देना नहीं है, यह मामला आस्था का है। जहां तक आस्था का सवाल है, मैं मानता हूं कि कोई भी धर्म आस्था के जरिए ही चलता है, जैसे आपकी आस्था है, ऐसी ही दूसरे धर्म के लोगों की भी आस्था है। कोई भी धर्म यह नहीं सिखाता है कि आस्था के नाम पर, विश्वास के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को अपमानित किया जाए।

हमें हर धर्म सहनशीलता सिखाता है, एक-दूसरे के प्रति सम्मान सिखाता है, इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो आस्था की बार-बार बात कही जाती है, वह मुनासिब नहीं है। किसी भी सभ्य समाज को पहचानने के लिए सबसे पहले यह जरूरी होता है कि समाज में रहने वाले खास तौर पर जो अल्पसंख्यक हैं या कमजोर वर्ग के लोग हैं, वे यह महसूस करें कि वे सुरक्षित हैं। 6 दिसम्बर को जो घटना घटी, यह बात बिल्कुल साफ और वाज़ा हुई कि वह सिर्फ बाबरी मस्जिद की शहादत नहीं थी, वह राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का, जो विवादित स्थल था, सिर्फ उसको नहीं गिराया गया था, बल्कि हमारे देश का जो संविधान है, जो संवैधानिक ढांचा है, उसको गिराने का प्रयास हुआ था। हमारे पूर्वजों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने इस देश को धर्मनिरपेक्ष और एक लोकतांत्रिक देश बनाने का जो संकल्प लिया था, उसको तोड़ने की कोशिश की गई, उसको गिराने का प्रयास किया गया। यह सिर्फ हमारे देश तक की बात नहीं है, बल्कि तमाम दुनिया में भारत की जो एक छवि थी, हमारे राष्ट्र की जो एक छवि थी, अलग-अलग जाति, भिन्न-भिन्न धर्म के लोग, अलग-अलग मजहब के लोग हमारे यहां रहते हैं और सभी को मिलाकर यह देश बना है। यही हमारे देश की खूबसूरती है। उस ढांचे को तोड़ने का प्रयास हुआ, उस ढांचे को तोड़ने की कोशिश की गई। इससे हमारे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ी। उपसभापति महोदय, यह बात बार-बार कही जाती है कि यह जो घटना घटी, वह स्पॉन्टेनियस था, उसमें कोई साजिश नहीं हूई थी। जबकि कमीशन की रिपोर्ट में यह वाज़ा हुआ कि इसके पीछे पूरा एक षड्यंत्र था, एक पूरी साजिश थी और स्पॉन्टेनियस कहकर उस मसले को दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि यह स्पॉन्टेनियस था तो यह माहौल कोई एक दिन में नहीं बना। आडवाणी जी की रथ यात्रा से लेकर, कार सेवकों को जमा करना और उसके बाद जो तमाम घटनाएं घटीं, अगर उसकी पृष्ठभूमि में सारी बातों को देखा जाए तो यह महसूस किया जाएगा कि उस घटना के पीछे वे तमाम भड़काने वाली बातें थीं लोगों के जज्बात, लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया गया, जिसकी वजह से सारी घटनाएं घटीं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए वही लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इस पूरे मसले को खड़ा करने की कोशिश की और लोगों के जज्बात को उभारने का

काम किया। सिर्फ यह कह देने से कि यह मामला स्पॉन्टेनियस था, यकायक हो गया, लोग जज्बात में आ गए, लोग भावना में आ गए, लोग जमा हो गए, इसलिए घटना घट गई, मैं समझता हूं कि यह बात किसी तरह से भी स्वीकार करने वाली नहीं है। उपसभापति महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि राजनीतिक दल आखिर किसलिए होते हैं। राजनीतिक दल का काम मंदिर या मस्जिद बनाने का नहीं है, यह तो हमारे धार्मिक गुरु इस बात का फैसला करेंगे कि कहां मंदिर बनना है, कहां मस्जिद बननी है, कैसे बनना है, क्या करना है, वे देखेंगे, लेकिन दुख की बात यह है कि आज हमारे जो राजनीतिक दल हैं, उन्होंने इसका ठेका ले लिया है कि कहां मंदिर बनेगा, कहां मस्जिद बनेगी और इसके पीछे खालिश राजनीति है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने इस बात को महसूस किया कि वे कार्यक्रम के आधार पर या राजनीतिक आंदोलन करके या जो एक लोकतांत्रिक तरीका है, उस तरीके से सत्ता में नहीं आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने एक शॉर्ट कट रास्ता अपनाने का प्रयास किया और वह शॉर्ट कट रास्ता यह था कि धार्मिक उन्माद पैदा करके, लोगों के जज्बात उभार कर लोगों को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की गई। उनको इसमें थोड़ी कामयाबी भी मिली, लेकिन यह देश के हित में नहीं था, यह राष्ट्र के हित में नहीं था। इससे जो आपस की भाईचारगी थी, जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारा संस्कार था मिल-जुल कर रहने का, उसको चोट पहुँची। इस घटना के 17 साल गुजरने के बाद आज भी लोगों के अन्दर भाईचारगी की कमी महसूस की जा रही है। इस तरह की जो घटनाएँ घटती हैं, उसके पीछे कारण वही है। अगर वह 6 दिसम्बर की घटना नहीं होती, तो शायद वह सिलसिला आज नहीं होता। लेकिन शायद यह बात हमारे राजनीतिक दलों को समळा में नहीं आती। मैं सीताराम जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि आज देश को एक दूसरे रास्ते पर लेकर चलने की जरूरत है। धार्मिक उन्माद पैदा करके, सामाजिक तनाव पैदा करके हम इस देश का भला नहीं कर सकते, समाज का भला नहीं कर सकते, बल्कि जो हमारी मूल समस्याएँ हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। गरीबी कैसे दूर हो, बेरोजगारी कैसे दूर हो, हमारे देश का विकास कैसे हो, हमारे देश में जो गरीबी है, आज भी एक बड़ी जनसंख्या गरीबी से पीड़ित है, इससे कैसे निजात दिलाया जाए। बजाय इन कामों के हम ऐसे कामों में उलझ रहे हैं, जो राजनीतिक दलों का काम नहीं है।

उपसभापति जी, यह बात सही है कि कमीशन बनाने के पीछे सरकार का मकसद यही होता है कि उसकी रिपोर्ट आने के बाद उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी लोग दोषी हैं, जिनका नाम उसमें शामिल है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह विश्वसनीयता का सवाल है, credibility का सवाल है, किसी भी सरकार के लिए, व्यवस्था के लिए, शासन के लिए, क्योंकि अगर मुजरिम को सज़ा नहीं मिलेगी, तो फिर इससे जुर्म पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता और उसको रोका नहीं जा सकता। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आने वाले समय में हम चाहेंगे कि जो भी लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कमीशन ने यह बात बिल्कुल सही कही है कि इसके पीछे professional लोग थे, क्योंकि बाबरी मस्जिद को जिस तरह से ढहाया गया, सिर्फ कारसेवक उसको नहीं ढाह सकते। अगर उसके पीछे साज़िश नहीं होती, तो चन्द घंटों में इतनी बड़ी ऐतिहासिक इमारत नहीं गिराई जा सकती थी। इसलिए जरूर कुछ professional लोगों को पहले से इसके लिए hire किया गया, जिसकी वजह से ये सारी घटनाएँ घटीं। लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और उस समय वहाँ के जो मुख्य मंत्री थी, वे सभी उस साज़िश में शामिल थे। बिना उनकी मदद के या बिना उनकी सहमति के यह काम सम्भव नहीं था। एक तरह से यह कहा जाए कि यह एक national betrayal था, तो गलत नहीं होगा। मैं चाहूँगा कि जो भी recommendations आई हैं, उन पर जल्द-से-जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस पर फिर से लोगों को यकीन हो।

आखिर में अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं यह चाहूँगा ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: एक शेर सुना दीजिए।

श्री तारिक अनवर: शेर सुना दूँ, आपको शेर सुनने का शौक है। अहलुवालिया जी, एक छोटा सा शेर है, लेकिन यह भावना है और यह भावना इस देश के अल्पसंख्यकों की भावना है, जो मैं एक शेर के जरिए आपको बताना चाहता हूँ।

श्री एस.एस. अहलुवालिया: हम भी अल्पसंख्यक हैं।

श्री तारिक अनवर: आप भी अल्पसंख्यक हैं, तो आप भी उसमें शामिल हो जाएँ।

श्री उपसभापति: दोनों सामने बैठे हैं।

श्री तारिक अनवर: "तुझको मालूम नहीं दिल को दुखाने वाले,
ये जो मज़लूम हैं, आहों में असर रखते हैं।"

उपसभापति महोदय, मैं इसी शेर के साथ अपनी बात समाप्त करूँगा और यह कहूँगा कि सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए और हर तरह से यह विश्वास इस देश के, सिर्फ अल्पसंख्यकों का सवाल नहीं है, दुनिया को यह विश्वास दिलाने की जरूरत है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, महात्मा गाँधी का देश है, सर्वधर्म समभाव पर हमारा विश्वास है। यह बात दुनिया को बताने की जरूरत है और तभी लोगों को विश्वास होगा, तभी लोगों को भरोसा होगा कि सही मायने में हम लोकतांत्रिक हैं, सही मायने में हम इंसाफ पसन्द हैं। इस घटना के करने वालों को, जिनकी वजह से जो साम्प्रदायिक दंगे हुए, जो नुकसानात हुए, समाज में जो बँटवारा हुआ, इन सारी चीजों के लिए अगर कोई जिम्मेदार है, तो उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। यह देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है, समाज के हित में है। धन्यवाद।

श्री राजनीति प्रसाद: सर, एक सैकेंड ...**(व्यवधान)**... ।

डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला (राजस्थान): सर, एक मिनट, मुझे एक शेर सुनाना है ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: प्लीज़, आप बैठिए ...**(व्यवधान)**... आप दोनों ही एक मिनट के लिए बोल रहे हैं ...**(व्यवधान)**...

डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला: सर, मैं तो आधे मिनट में खत्म कर दूंगी।

श्री उपसभापति: राजनीति जी, आप पहले इन्हें शेर बोल लेने दीजिए, बाद में आप बोल लेना।

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार): सर, पहले मुझे बोल लेने दीजिए न।

डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला: चलिए आप ही बोल लीजिए।

श्री राजनीति प्रसाद: सर, इन्होंने शब्द कहे 'राजनीतिक दलों का'। इसका मतलब it includes all parties. ...**(व्यवधान)**...

श्री तारिक अनवर: मेरे कहने का मतलब यह था ...**(व्यवधान)**...

श्री राजनीति प्रसाद: नहीं-नहीं, आपने राजनीतिक दलों ही बोला था ...**(व्यवधान)**...

श्री तारिक अनवर: नहीं-नहीं, इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल।

अभी जेडीयू के नेता अंसारी साहब बोल रहे थे, मेरी उनसे भी गुज़ारिश है, वह अभी यह बात कह गए कि उनको फांसी लगनी चाहिए। लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी की मदद से आज बिहार में उनकी सरकार चल रही है। वह किस मुंह से यह बात कह रहे हैं।

डा. (श्रीमती) नजमा ए. हेपतुल्ला: सर, तारिक जी ने आह के बारे में एक शेर पढ़ा था, उसके जवाब में ग़ालिब का एक शेर है —

आह को चाहिए इक उम्र असर होने तक।
कौन जीता है तेरी ज़ुल्फ़ के सर होने तक॥

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri D. Raja. You start.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): But, Sir, as you said, I will speak tomorrow.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, at 5 o'clock, you are adjourning the House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, there is a message from Lok Sabha.

MESSAGE FROM LOK SABHA

The Representation of the People (Amendment) Bill, 2009

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:—

"In accordance with the provisions of rule 120 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 9th December, 2009, agreed without any amendment to the Representation of the People (Amendment) Bill, 2009, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 25th November, 2009."

SHORT DURATION DISCUSSION

Liberhan Commission Report and trial of Babri Masjid case (Contd.)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. Raja, you start.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Sir, he can continue tomorrow. ...*(Interruptions)*...

SHRI D. RAJA: Sir, I will start. Then, you adjourn the House. Tomorrow, I will continue.

श्री साबिर अली (बिहार): सर, पांच मिनट का टाइम हमें दे दीजिए, पांच मिनट में ही खत्म कर देंगे।

श्री उपसभापति: ऐसा नहीं होता है।

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, we are having a very serious debate on the Liberhan Commission Report. We do not need the expertise and eloquence of Shri Arun Jaitley, or Dr. Abhishek Manu Singhvi, or for that matter, of Shri Kapil Sibal or Mr. Chidambaram to understand what happened on 6th December, 1992, at Ayodhya. It was Shri K.R. Narayanan, the former President of India who said, "The demolition of Babri Masjid was the second huge tragedy after Mahatma Gandhi's assassination." Many concerned citizens expressed their serious concern over what happened on December 6, 1992. The motives behind Gandhi's murder and Babri Masjid demolition were the same, paving the way for *Hindu Rashtra* of the RSS. It is a known fact. We can debate on this. Sir, I will continue if you allow me, or, I will continue this tomorrow.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You please continue tomorrow.